संपादकीय जागरण

शनिवार, 9 मई, 2026: ज्येष्ठ कृष्ण - 7 वि. 2083

मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनने लगता है

# विपक्षी गठबंधन में दरार

तमिलनाडु में अभिनेता जोसेफ विजय की नई पार्टी टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरते ही कांग्रेस ने जिस तरह उसके साथ जाने के संकेत दिए और फिर बिना किसी संकोच ऐसा ही किया, उससे डीएमके का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। डीएमके नेताओं ने कांग्रेस के छिटकने को केवल धोखेबाजी ही नहीं बताया, बल्कि यह भी फैसला किया कि अब संसद में उसके सांसद कांग्रेस सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे। यह आइएनडीआइए से नाता तोड़ने की घोषणा ही है। कांग्रेस की तरह डीएमके संग मिलकर चुनाव लड़ने वाली माकपा, भाकपा और वीसीके ने भी जिस प्रकार विजय के साथ जाना पसंद किया, वह अवसरवाद के अलावा और कुछ नहीं। चूंकि अब माकपा और भाकपा की कोई खास राजनीतिक अहमियत नहीं, इसलिए उनके डीएमके से अलग होने का कोई अधिक महत्व नहीं, लेकिन कांग्रेस का अलगाव विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को और अधिक कमजोर करने वाला है। यह एक तथ्य है कि आइएनडीआइए से छिटकने वाले दलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले जदयू अलग हुआ, फिर आम आदमी पार्टी। अब एक तरह से कांग्रेस ही उससे किनारा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि वे चुनाव से पहले ही टीवीके के साथ जाने पर विचार रहे थे, लेकिन यह कथित विचार उन्हें चुनाव बाद गठबंधन तोड़ने का लाइसेंस नहीं देता। आखिर राजनीतिक नैतिकता और गठबंधन धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं?

आने वाले समय में आइएनडीआइए के बिखरने की आशंका इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की घटक दलों से खटपट होती रहती है, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। यह भी ध्यान रहे कि हाल के विधानसभा चुनावों में बंगाल और केरलम में इस गठबंधन के घटक आमने-सामने ही थे। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि कांग्रेस को उसी गठबंधन के भविष्य की परवाह नहीं, जिसका नेतृत्व वह अपने हाथ रखना चाहती है। पहले भी इस गठबंधन का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं दिख रहा था, पर अब तो वह और स्याह दिखने लगा है। डीएमके संग चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सत्ता की मलाई खाने जिस तरह एक झटके में टीवीके के साथ चली गई, उससे यही साफ हुआ कि वह स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का साथ दो दशक से भी अधिक पुराना था, लेकिन उसने स्वार्थ के लिए इस लंबे साथ को कोई अहमियत नहीं दी। अब इसके भरे-पूरे आसार हैं कि इस गठबंधन के अन्य घटक भी मौका देखते ही कांग्रेस से अलग होने में देर नहीं करेंगे। इसकी अनदेखी न की जाए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पलटी मारने पर यह कहकर उस पर तंज ही कसा है कि हम वे नहीं, जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें।

# सतर्कता जरूरी

दिल्ली में मंदिर के साथ ही सोनीपत के एक ढाबे और हिसार में सेना के कैंप के आतंकी निशाने पर होने की बात सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में सामने आया है कि आइएसआइ किस तरह बड़े पैमाने पर राजधानी और आसपास के शहरों में आतंकी हमलों की साजिश रच रही है। यह सराहनीय है कि उसकी इन साजिशों को दिल्ली पुलिस लगातार विफल कर रही है।

आइएसआइ की सक्रियता को देखते हुए न सिर्फ दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए

दिल्ली में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने के साथ ही आइएसआइ की एनसीआर के शहरों में सक्रियता के सुबूत भी लगातार मिल रहे हैं। पिछले माह गाजियाबाद में ऐसे युवकों को पकड़ा गया था, जो रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर सेना की गतिविधियों पर नजर रखना चाहते थे। आइएसआइ की सक्रियता को देखते हुए न सिर्फ दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए, बल्कि दिल्लीवासियों को भी आंख और कान खुले रखने चाहिए। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को ठुकरा कर सही किया?

### आज का सवाल

क्या कांग्रेस के डीएमके से नाता तोड़ने से विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए और अधिक कमजोर होगा?

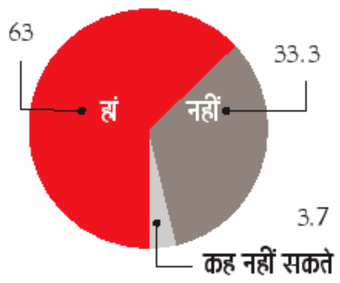


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

# बंगाल में परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण

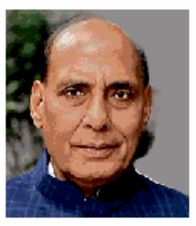

राजनाथ सिंह

**बंगाल में हुआ बदलाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है, जिन्होंने राज्य को उसके मूल से दूर किया**

अवधेश राजपूत

''हे नूतन, देखा दिक आर-बार, जन्मेरो प्रथम शुभोखोन।'' इसका अर्थ है-हे नवीन, एक बार फिर से सामने आओ, ठीक उसी तरह जैसे जन्म के समय वह पहला शुभ क्षण आया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां केवल एक कविता का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर स्वत:स्फूर्त और नवीन होने वाली बंगाल के आत्मा का आह्वान भी हैं। गुरुदेव भली-भांति समझते थे कि बंगाल समय के साथ केवल बदलता नहीं है, बल्कि वह बार-बार बेहतर और नए रूप में पल्लवित होता है। गुरुदेव की जयंती पर गाई जाने वाली यह कविता नवजागरण और नवचेतना का प्रतीक है। यह एक सुखद संयोग है कि टैगोर की 165वीं जयंती से कुछ दिन पहले ही बंगाल कई दशकों के बाद नवजागरण का साक्षी बना। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव कभी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह चुनाव इस महान भूमि के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर था-एक ऐसा सभ्यतागत आह्वान, जो चुनावी समीकरणों और गणनाओं से कहीं ऊपर है।

आज जब बंगाल की चेतना और गौरव का अरुणोदय हो रहा है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि बंगाल क्या है और उसकी चेतना का पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है? बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र होने से पहले ज्ञान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में नबद्वीप के गंगा तट पर एक युवा संन्यासी निमाई ने अपने कीर्तन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उस युवा संन्यासी को हम संत चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता का अभियान भी था। उनके द्वारा प्रवाहित वैष्णव परंपरा ने समाज में करुणा, समावेशिता, समता और सद्भावना को बल दिया। यही चेतना बाउल परंपरा में भी दिखाई दी। बाउल परंपरा के फकीरों की पहचान जाति, पंथ या कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की भावना थी। बाउल परंपरा के सबसे महान प्रवर्तक लालन फकीर थे। वे किस संप्रदाय से थे, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया तथा मुस्लिम समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे बंगाल की उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे, जिसमें सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का भाव समाहित था।

विगत तीन शताब्दियों में बंगाल और यहां के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। राजा राममोहन राय ने लोगों को आत्मबोध कराकर समाज को भीतर से सुधारने का मार्ग चुना। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को नारी शक्ति के उत्थान, सशक्तीकरण और मुक्ति का साधन बनाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ''वंदे मातरम्'' जैसा अमर मंत्र राष्ट्र को दिया। इस गीत ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया और सदियों से सोए हुए देश को जगा दिया। यह गीत आज भी भारत के लोगों के अंतरात्मा का स्वर है। भारत की पहली महिला चिकित्सक डा. कादंबिनी गांगुली ने सभी को और विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया। बंगाल की ही धरती पर जन्मे प्रखर राष्ट्रवादी डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।

संभवत: बंगाल की धरती ने जितनी विलक्षण प्रतिभाओं और महान लोगों को जन्म दिया, उनमें सबसे देदीप्यमान और प्रबुद्ध स्वामी विवेकानंद को कहा जा सकता है। शिकागो में दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने विश्व को वेदांत और भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों से परिचित कराया।

दुर्भाग्यवश लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझा और उसे हेय दृष्टि से देखा। सभ्यता, धर्म, संस्कृति और बंगाल की चेतना की बात करने वाले लोगों को और उनकी आवाज को दबाया गया। परिणामस्वरूप बंगाल ने दशकों तक विकासहीनता, अराजकता, संस्थागत पतन और वैचारिक जड़ता का दंश झेला। बंगाल में हुआ परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हैं, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है, जिन्होंने बंगाल को उसके मूल से दूर किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बंगाल विधानसभा का चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल के गौरव और विरासत को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ था। बेलूर मठ से प्रधानमंत्री मोदी का आत्मिक जुड़ाव, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और सुशासन को 'सेवा' के रूप में देखने का उनका दृष्टिकोण, ये सभी इसके प्रमाण हैं कि 'प्रधान सेवक' बंगाल के विकास और पुनर्जागरण को एक पावन दायित्व मानते हैं, जिसे वे अपने 'प्रधान धर्म' और 'प्रधान कर्म' के रूप में निभा रहे हैं।

बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण का अर्थ कई दशकों से उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो है ही, साथ ही उन घाटों को पुनर्जीवित करना भी है, जहां चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन ने लोगों को भाव-विभोर किया था। इसका अर्थ उन शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त करना भी है, जिनका स्वप्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा था। इसका अर्थ आदिवासी भाइयों-बहनों को गरिमा, सम्मान और अवसर देना और उपेक्षा झेल रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है।

पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो, किंतु आज बंगाल एक बार फिर नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शांति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बनने वाली पहली भाजपा सरकार गुरुदेव के द्वारा वर्णित 'नूतन' भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रतिष्ठा और समृद्धि के साथ राज्य का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।

(लेखक भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं)

response@jagran.com

# सरकार और देश में अंतर करना जरूरी

प्रो. मनोज कुमार झा

**एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहां नागरिक निर्भीक होकर सवाल पूछ सकें और जहां असहमति को भी सम्मान मिले**

आलोचना को अवसर माने सरकार ● फाइल

लोकतंत्र की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक यह है कि देश और सरकार एक ही इकाई नहीं होते। यह फर्क केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। देश एक जीवंत, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाली सामूहिक चेतना है और उसकी विविधताओं, संघर्षों, इतिहास, आकांक्षाओं और भविष्य का समुच्चय होता है। इसके विपरीत, सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे जनता समय-समय पर चुनती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर देश बना रहता है। इस सरल-सी प्रतीत होने वाली सच्चाई को धुंधला करना, लोकतंत्र के आत्मा को कमजोर करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत करने लगता है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन आज के दौर में इसका स्वर अधिक मुखर और आक्रामक हो गया है। सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के रूप में चित्रित करना, असहमति को राष्ट्रद्रोह के साथ जोड़ देना और किसी एक नेता की छवि को राष्ट्र की गरिमा के साथ मिला देना, ये सभी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करने के औजार हैं। इससे नागरिकों पर दबाव बढ़ता है कि वे सवाल उठाने से बचें, अन्यथा उन्हें ''देश-विरोधी'' ठहरा दिया जाएगा। यह माहौल लोकतंत्र की मूल भावना-स्वतंत्र विचार और बहस के सर्वथा प्रतिकूल है।

किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी होती है। सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यशैली पर सवाल उठाना, उनका विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार उनका विरोध करना सक्रिय नागरिकता के अनिवार्य तत्व हैं। यदि यह प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, तो सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता है और जवाबदेही कम होती जाती है। जब-जब सरकार और राष्ट्र को एक मान लिया गया, तब-तब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं, नागरिक अधिकारों पर आघात हुआ और तानाशाही प्रवृत्तियां पनपीं। किसी भी उच्च पदस्थ नेता की गरिमा और प्रतिष्ठा निस्संदेह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे राष्ट्र की गरिमा का पर्याय बना देना एक खतरनाक सरलीकरण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की छवि पर नहीं, बल्कि उसके संस्थानों की मजबूती, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और समाज की समावेशी संरचना पर निर्भर करती है। जब हम किसी नेता की आलोचना को राष्ट्र के अपमान के रूप में देखने लगते हैं, तो हम अनजाने में लोकतंत्र के उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच स्थापित होना चाहिए। यह याद रखना प्रासंगिक है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होती हैं। व्यक्ति-पूजा का यह चलन धीरे-धीरे संस्थागत ढांचे को कमजोर करता है और लोकतंत्र को एक व्यक्ति-केंद्रित व्यवस्था में बदलने का खतरा पैदा करता है। सत्ताधारी दल का हित और राष्ट्रहित भी हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर दल स्वाभाविक रूप से अपने विस्तार, प्रभाव और चुनावी सफलता के लिए काम करता है और यह लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जब इन हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास होता है, तब समस्या पैदा होती है। इससे नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोणों की गुंजाइश कम हो जाती है और निर्णय एकतरफा हो सकते हैं।

लोकतंत्र का सार ही यह है कि विभिन्न विचारों के बीच संवाद हो और उसी से नीतियों का निर्माण हो। इस बहस में सबसे केंद्रीय भूमिका नागरिक की है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सवाल पूछना, जानकारी जुटाना, नीतियों का मूल्यांकन करना और अपनी स्वतंत्र राय बनाना, ये सभी लोकतांत्रिक नागरिकता के आवश्यक तत्व हैं। यदि नागरिक इस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, तो सत्ता का असंतुलन बढ़ता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। समझना जरूरी है कि आलोचना का अर्थ विरोध या नकारात्मकता नहीं होता। रचनात्मक आलोचना वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों में सुधार होता है और शासन अधिक प्रभावी बनता है। एक परिपक्व लोकतंत्र में सरकार आलोचना को अवसर के रूप में देखती है, न कि खतरे के रूप में, पर जब आलोचना को ही शत्रुता के रूप में देखा जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक असुरक्षा का संकेत है। आवश्यक है कि हम देश और सरकार के बीच इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझें और बनाए रखें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन देश स्थायी है। इसलिए हमारी सर्वोपरि निष्ठा किसी दल या व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उन मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, जो इस देश को परिभाषित करते हैं-लोकतंत्र, न्याय, समानता, संप्रभुता और स्वतंत्रता।

एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहां नागरिक निर्भीक होकर सवाल पूछ सकें, जहां असहमति को सम्मान मिले और जहां सरकारें स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह मानें। देश और सरकार के बीच की इस आवश्यक दूरी को बनाए रखना ही लोकतंत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यदि हम इस अंतर को भूल जाते हैं, तो हम न केवल अपनी नागरिक जिम्मेदारी से विमुख होते हैं, बल्कि उस लोकतांत्रिक आत्मा को भी कमजोर कर देते हैं, जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रखा है।

(लेखक राजद के राज्यसभा सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## समय का महत्व

विचारकों ने समय की तुलना धन से की है। इन्हीं विचारकों ने सलाह दी कि जो समय बीत गया, उसके अनुभवों का लाभ तो लेना चाहिए, लेकिन उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि समय निरर्थक बीत गया। इससे सिर्फ ग्लानि ही हाथ लगती है। यदि अतीत के दिनों में किसी स्तर पर नासमझी हो गई, तो उसे सुधार कर आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए। समय को बहुत बलवान माना गया है। शारीरिक स्तर पर देखा जाए, तो नवजात शिशु बहुत कोमल और सुंदर लगता है। शनैः शनैः वह बड़ा होता है। कोमलता कम होती जाती है। एक समय आता है कि शरीर जर्जर हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कितना भी यत्न कोई कर ले, लेकिन बाल्यावस्था जैसी कोमलता, स्निग्धता और मधुरता को बरकरार नहीं रख पाता है। जहां समय इस तरह के सौंदर्य को अपहृत करता है, वहीं जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, तो बदले में यही समय अनुभव, नई जानकारियों का तोहफा देता है तथा परिचय का दायरा विस्तृत करता है। जब समय की यह गति है, तो इसके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। समय अपहर्ता है, तो वह दाता भी है। बशर्ते उसके द्वारा दी गई विशिष्टताओं को पूंजी की तरह संभाल कर रखा जाए।

समय की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि यदि किसी दिन कोई नया काम न किया गया हो, किसी नए व्यक्ति से परिचय न हुआ हो, तो उस दिन को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि यह उसके जीवन का निरर्थक दिन था। नए काम करते रहने से बहुआयामी प्रतिभा का विकास होता है। नए-नए व्यक्तियों से परिचय होने से जुड़ाव बढ़ता है। इस प्रकार समय को सार्थक ढंग से जीते हुए कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। व्यक्ति जब भी जागृत हो जाता है, तो सामने उपलब्धियों का सूरज दिखाई पड़ने लगता है।

सलिल पांडेय

## पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

### बंगाल में हिंसा क्यों

'चुनाव बाद हिंसा का दुष्चक्र' संपादकीय पढ़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से राज्य में हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चुनाव के बाद हिंसा की यह प्रवृत्ति राज्य में नई नहीं है। आखिर चुनाव समाप्त होने और जनादेश स्पष्ट हो जाने के बाद भी बंगाल में हिंसा क्यों होती है? क्या इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, हार-जीत की प्रतिक्रिया और स्थानीय स्तर पर बढ़ती कटुता जिम्मेदार है? यदि ऐसा है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है, बल्कि लोकतांत्रिक परिवेश को भी प्रभावित करती है। अब इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती टकराहट का लाभ देशविरोधी और असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है और सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी संयम और जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर होने वाली बहसें ऐसी होनी चाहिए, जो शांति और संवाद को बढ़ावा दें, न कि तनाव और उत्तेजना को। कई बार तीखी बयानबाजी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना देती है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, जनादेश के सम्मान और सामाजिक सौहार्द में निहित है। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कभी भी हिंसा का कारण न बने।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### मोबाइल के दुष्परिणाम

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक लगभग हर काम अब मोबाइल के माध्यम से होने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। इसका असर केवल उनकी पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के माहौल पर भी दिखाई देने लगा है। आज कई बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम खेलने, वीडियो देखने या इंटरनेट मीडिया में समय बिताने लगे हैं। शुरुआत में यह सामान्य आदत लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई व एकाग्रता पर पड़ता है। पढ़ाई में मन कम लगना, देर रात तक जागना व सुबह थकान महसूस करना जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने के कारण कम उम्र में ही बच्चों की आंखें कमजोर होने लगी हैं। चश्मा लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति से माता-पिता भी काफी परेशान रहते हैं।

तरुण शर्मा, नंगली वाजिदपुर, नोएडा

### बंगाल में नए युग की शुरुआत

बंगाल की राजनीति में लंबे समय बाद ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। सुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई है। दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बदलाव को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा आरोप-प्रत्यारोप व वैचारिक संघर्ष का केंद्र रहा है। चुनाव के दौरान भी राज्य में हिंसा और तनाव की कई घटनाएं सामने आई हैं। सुवेंदु का राजनीतिक सफर भी संघर्षपूर्ण रहा है। कभी ममता के करीबी सहयोगी रहे सुवेंदु ने बाद में भाजपा का दामन थामा और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लगातार दूसरी बार नंदीग्राम से जीत और भवानीपुर में ममता को हराने की चर्चा ने उन्हें भाजपा के सबसे प्रभावशाली बंगाली नेताओं में शामिल कर दिया। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत संगठनकर्ता और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है। भाजपा का दावा है कि अब भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को पारदर्शी बनाया जाएगा।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

## पोस्ट

त्रिपुरा, असम और बंगाल। भाजपा ने बांग्लादेश को तीनों ओर से घेर लिया है। रवि भदौरिया@ravibhadoria

पिछले दो बार से भाजपा मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची नहीं निकाल रही। बिहार के बाद बंगाल में भी उम्मीद के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुना गया है।

सुकेश रंजन@RanjanSukesh

मुझे लगता है कांग्रेस के द्रमुक गठबंधन से बाहर निकलने के बाद आइएनडीआइए का स्वरूप समाप्त हो गया है। डीएमके को गुस्सा इस बात पर आया है कि कांग्रेस ने अपने फैसले की जानकारी एमके स्टालिन को नहीं दी, जबकि अन्य सहयोगी दल उनसे बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि हमें क्यों बताना चाहिए? इसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। धन्य राजेंद्रन@dhanyarajendran

तमिलनाडु में इन दिनों जिस तरह पुराने गठबंधन टूट रहे हैं एवं सत्ता की लालसा उन राजनीतिक रंजिशों पर भारी पड़ रही है, जिन्हें कभी न भूलने योग्य बताया जाता था, वह स्थिति बहुत कुछ सिखाने वाली है। असल में आज सत्ता ही एकमात्र उद्देश्य बन गई है। बाकी सब खरीदे और बेचे जाने वाली चीज बनकर रह गई हैं।

निस्तुला हेब्बार@nistula

## जनपथ

हारीं ममता जी मगर परेशान अखिलेश,
है उनके आगे खड़ा सत्ताइस का क्लेश।
सत्ताइस का क्लेश जमे पहले से बाबा,
नाचो-गाओ आप दिलों में रखकर 'काबा'!
बीजेपी का दांव पड़ रहा सब पर भारी,
चला न 'खेला' एक उसी से ममता हारीं!!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120-4615800, E-mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 294

# अब नई सरकारें

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली नई पार्टी टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है और इसके साथ ही वहां सियासी उठापटक की आशंका टलती दिख रही है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके चुनाव में 108 सीटें जीतने में कामयाब रही, पर बहुमत से 10 सीटें कम होने की वजह से उसे सरकार गठन में परेशानी आई। इसकी वजह से एक समय ऐसा लगा कि वह सरकार नहीं बना पाएगी। उसके विधायकों ने यहां तक फैसला कर लिया कि अगर राज्य में किसी और की सरकार बनी, तो वे विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल, चुनाव जीतने के तुरंत बाद विजय से कुछ गलतियां हुईं, जिनका उन्हें आगे ध्यान रखना होगा। जब गठबंधन की नौबत आए, तब नेताओं को समावेशी होना पड़ता है। विजय में एक नेता के रूप में जो लचीलापन चाहिए, उसका अभी अभाव है। राजनीति में फिल्मी स्टारडम मतदाताओं के बीच तो चलता है, पर राजनीतिक समाज इसे ज्यादा महत्व नहीं देता है।

अब तमिलनाडु में बहुमत विवाद सुलझ गया है, पर अगली सरकार बनाने के लिए जिस तरह की सियासत वहां हुई है, वह दिलचस्प है। तमिलनाडु ने याद दिलाया, राजनीति में अवसरवादिता के दिन नहीं लदते। यह आश्चर्य का विषय है कि दशकों से एक-दूसरे की धुर विरोधी द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच मिलकर सरकार बनाने की चर्चा चल पड़ी। इसके अलावा द्रमुक के नेतृत्व में गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस का विजय के पक्ष में आ जाना भी बहुतों को नागवार गुजरा। खुद द्रमुक ने इसे देश की सबसे पुरानी पार्टी का चरित्र बता दिया। संकेत स्पष्ट है, विजय तमिलनाडु में सरकार बना लेंगे, पर उन्हें कदम-कदम पर तगड़े विपक्ष से दो-दो हाथ करना पड़ेगा। द्रमुक को दोहरा झटका लगा है। कांग्रेस, वीसीके, भाकपा और माकपा ने राज्य में सत्ता के लिए द्रमुक का साथ छोड़कर विजय का दामन थाम लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि द्रमुक के नेता एम के स्टालिन अपने गठबंधन को पर्याप्त सम्मान और समन्वय से नहीं चला रहे थे। यह द्रविड़ पार्टियों का गैर-समावेशी स्वभाव है कि ये चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करती हैं, पर अपने सहयोगी दलों को सत्ता से दूर रखकर अपमानित भी करती हैं।

**तमिलनाडु में जहां अभिनेता-राजनेता विजय मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ चले हैं, वहीं भाजपा ने भी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुन लिया है।**

खैर, तमिलनाडु जैसी स्थिति बंगाल में नहीं बनी। यहां सहजता से भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुन लिया है। मजबूत जमीनी नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर हमेशा इक्कीस पड़े हैं। वह भाजपा की संस्कृति में इतने घुल-मिल गए हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार का गठन स्वाभाविक है। तृणमूल की आक्रामकता के सामने हिम्मत न हारने का पुरस्कार शुभेंदु अधिकारी को मिलना ही चाहिए था। वैसे, उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह सरकार ही नहीं बनाती है, समाज को बदलती भी है। अतः लोग उम्मीद करेंगे कि वहां हिंसा, उपद्रव, कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। ध्यान रहे तृणमूल की हार के बाद भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और वामदलों को भी जगह-जगह अपने दफ्तर खोलने-चलाने का मौका मिल रहा है। नई सरकार से पहले यह शुभ संकेत है, इसी लकीर पर समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने की ओर बढ़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बंगाल को भद्रलोक की ओर लौटाने का समय है। तमाम जोखिम उठाकर भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत देने वाले लोग यही चाहेंगे कि कभी भारत को राह दिखाने वाला यह राज्य अपने खोए हुए औद्योगिक, सांस्कृतिक गौरव को फिर से हासिल करे।

## हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 9 मई, 1951

### भारतीय मुसलमान

विभाजन के बाद भी भारत में साढ़े चार करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। किन्तु इन वर्षों में ऐसे बहुत कम अवसर आये हैं, जब भारतीय मुसलमानों ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किये हों। उनकी चुप्पी ने कभी-कभी गलतफहमी भी पैदा की है, इसलिए हमें खुशी है कि भारतीय मुसलमानों ने अपने तौर पर कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसके जरिये अपना स्वतन्त्र मत प्रकट किया। सम्मेलन की अध्यक्षता सर सुलतान अहमद ने की थी, जो मुस्लिम लीग की राजनीति के जमाने में भी अपने स्वतन्त्र विचार रखते थे। पाकिस्तान की स्थापना के बाद देश की राजनीति का रूप एकदम बदल गया। अब साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के लिये देश में अवकाश नहीं रह गया है। भारतीय मुसलमान अपने को बिल्कुल नयी परिस्थितियों में पाते हैं। इस कारण स्वभावतः उनमें कर्तव्य विमूढ़ता की भावना पैदा हो गयी है। उन्हें अपने को नयी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मुस्लिम समाज के नेताओं पर यह दायित्व है कि वह अपने समाज के आम लोगों का सही दिशा में पथ-प्रदर्शन करें और उन्हें अपने को नयी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में मदद करें।

गत फरवरी में कराची में एक विश्व मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया, वे न तो उन देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करते थे, न राजनीतिक पार्टियों का। पाकिस्तान ने जिनको चाहा, उनको निमंत्रित कर लिया था। उसमें लंका, मेडेगास्कर, दक्षिण अफ्रीका, स्याम आदि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जो न तो मुस्लिम राष्ट्र हैं और न जहां मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। विचित्र बात यह थी कि इसमें न तो भारतीय मुसलमानों को निमंत्रित किया गया, जिनकी संख्या तुर्की, मिस्र मौर ईरान तीनों देशों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक होती है और न रूस के आधीन मुस्लिम राष्ट्रों को निमंत्रित किया गया। भारतीय मुसलमानों की उपेक्षा करने का इसके सिवा और कोई कारण नहीं था कि उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान की हां में हां नहीं मिलाते और ऐसे विचार प्रकट करते, जो उसे रुचिकर न होते। ऐसी दशा में कराची के कथित विश्व मुस्लिम सम्मेलन को किसी भी तरह से विश्व के मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता।

**तमिलनाडु में राज्यपाल के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुए हैं, आखिर यह नौबत क्यों आई? वहां राज्यपाल ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए सरकार बनाने के लिए लालायित सबसे बड़ी पार्टी के नेता विजय को दो बार लोकभवन से लौटा दिया। अंततः बहुमत जुटाने के बाद ही तमिलनाडु में नई सरकार बन रही है, लेकिन क्या हम इस अप्रिय विवाद से बच नहीं सकते थे? पता नहीं, इस बहस का अंत कब होगा और हम एकमत होंगे?**

# राज्यपाल की भूमिका पर बार-बार सवाल

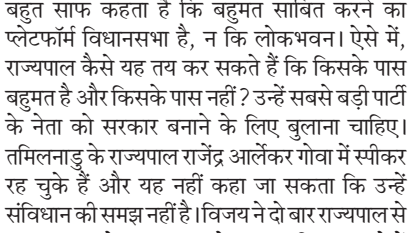


- अधिकतर राज्यपाल केंद्र सरकार के रबड़ स्टैंप की तरह काम करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, बहुमत साबित करने का प्लेटफॉर्म विधानसभा है।
- संविधान सभा ने साफ कहा था, राज्य में सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते।

**आशुतोष** | वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु में नतीजों के बाद के घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्यपाल की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका हमेशा से विवादों में रही है। एकाध अपवाद को छोड़कर उन पर सदैव केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान करने और असांविधानिक तरीके से राज्य सरकार को बर्खास्त करने के आरोप लगते रहे हैं। इस खेल में कोई पार्टी या गठबंधन अपराध मुक्त नहीं है।

अमूमन सरकार गठन में राज्यपाल की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल पर अक्सर अपने सांविधानिक 'विवेक' का इस्तेमाल न कर केंद्र के इशारे पर काम करने के आरोप लगे हैं। यह भी सच्चाई है कि ऐसे तमाम राज्यपालों ने एक तरह से विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए दरवाजे खोले और अनैतिक राजनीति को बढ़ावा दिया। तमिलनाडु में चुनावी नतीजों के आने के बाद वैसी ही आशंका ने जन्म ले लिया था।

तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता देने में आनाकानी ने वहां के राज्यपाल की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया है। विपक्ष ने तर्क दिया कि एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत साफ कहता है कि बहुमत साबित करने का प्लेटफॉर्म विधानसभा है, न कि लोकभवन। ऐसे में, राज्यपाल कैसे यह तय कर सकते हैं कि किसके पास बहुमत है और किसके पास नहीं? उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर गोवा में स्पीकर रह चुके हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें संविधान की समझ नहीं है। विजय ने दो बार राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा किया, पर दोनों बार उन्होंने उनसे बहुमत का आंकड़ा लाने को कहा।

दरअसल, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल किसे बुलाएंगे, इस पर संविधान में बहुत स्पष्टता नहीं है। ऐसे में, राज्यपाल का विवेक महत्वपूर्ण हो जाता है और सारी दिक्कत इसी विवेक के इस्तेमाल की वजह से होती है। अधिकतर राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर रबड़ स्टैंप की तरह काम करते हैं।

आर्लेकर के पास दो विकल्प थे। एक शंकर दयाल शर्मा का मॉडल और दूसरा केआर नारायणन का। बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 1996 में जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का मौका दिया। वाजपेयी बहुमत नहीं साबित कर पाए और 13 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने।

गुजराल सरकार गिरने के बाद हुए चुनाव में जब फिर त्रिशंकु लोकसभा बनी और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब उस वक्त के राष्ट्रपति केआर नारायणन ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का दावा करने वाला दल या नेता उन्हें आश्वस्त करे कि उसके पास बहुमत है और 272 सांसदों के समर्थन की चिट्ठी दे। जब वाजपेयी ने बीजेपी सांसदों के साथ दूसरे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की चिट्ठी नारायणन को दी, तब 1998 में उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया गया। साल 1999 में भी नारायणन ने इसी प्रकिया का पालन किया।

शंकर दयाल शर्मा के बाद नारायणन का मॉडल भारतीय सांविधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक परिष्कार है। शंकर दयाल शर्मा के मॉडल में राजनीतिक अस्थिरता के बीज हैं। नारायणन का मॉडल सैद्धांतिक स्तर पर 'हार्स ट्रेडिंग' और अस्थिरता को न्यून करता है। ऐसे में, कायदे से नारायणन के मॉडल को ही फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन राज्यों में राज्यपाल ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है और वह किया, जो केंद्र सरकार ने उनको करने का कहा। इसका सबसे हास्यास्पद उदाहरण तो महाराष्ट्र का है, जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सूरज निकलने के पहले ही देवेंद्र फडनवीस और अजित पवार को सरकार बनाने के लिए न केवल न्योता दिया, बल्कि आनन-फानन में शपथ भी दिला दी। वह सरकार 80 घंटे भी नहीं चली, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था।

इसी तरह, साल 2018 में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा आई थी और आनन-फानन में बिना पड़ताल किए कि येदियुरप्पा के पास बहुमत है या नहीं, उनको

सरकार बनाने के लिए बुला लिया गया। वह सरकार ढाई दिन चली। दोनों ही मौकों पर राज्यपाल को लगा कि फडनवीस और येदियुरप्पा के सरकार बनाने के बाद दूसरे दल समर्थन दे देंगे या फिर दूसरे दलों को तोड़कर बहुमत का आंकड़ा पूरा किया जा सकता है। ऐसे में, बड़ा सवाल यही है कि आर्लेकर ने क्या नारायणन के रास्ते को और सही किया या उनका यह कदम केंद्र के इशारे पर विजय की ताजपोशी में अड़ंगे अटकाने का ही रहा?

संविधान लागू होने के 76 साल बाद राज्यपाल की भूमिका अब स्पष्ट होनी चाहिए। सांविधानिक रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर वह क्या कदम उठा सकते हैं और क्या कदम उनके लिये वर्जित होंगे। मेरे हिसाब से नारायणन के मॉडल को तरजीह दी जानी चाहिए। भले ही सरकार बनाने में देरी हो, पर सरकार बनाने का दावा करने वाले दल या नेता को यह सुबूत राज्यपाल को देना ही चाहिए कि उसके पास बहुमत का समर्थन है।

संविधान सभा में राज्यपाल की भूमिका पर बहस के समय यह बात साफ तरीके से कही गई थी कि प्रदेश में सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते। इसलिए वक्त आ गया है कि राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह लिखित में निर्धारित हो, ताकि वह पद का दुरुपयोग न करें और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म न दें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

**आमने-सामने**

# भारत में अच्छे गवर्नर की कोई कमी नहीं

- राज्यपाल का कहना कि पहले समर्थन-पत्र पेश करें, असांविधानिक नहीं।
- संविधान राज्यपाल से ऐसा निर्णय लेने की अपेक्षा करता है, जो राष्ट्रहित में हो।
- राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह राज्य के लोगों के हित को सबसे ऊपर रखे।

**हरबंश दीक्षित** | विधि विशेषज्ञ

तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थिति ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका को चर्चा के केंद्र में ला दिया। वहां राज्यपाल पर राजनीति से प्रभावित होने के आरोप भी लगे। वैसे यहां ध्यान रखने की बात है कि अपने देश में राज्यपाल से जुड़े विवाद अप्रिय स्थिति में कम ही पहुंचते हैं। ज्यादातर राज्यपाल अच्छे ही हुए हैं, जिन्होंने बहुत लोकतांत्रिक ढंग से विवादों का समाधान किया है।

राज्यपालों से जुड़े अच्छे उदाहरण ही ज्यादा हैं। कुछ उदाहरण अगर गिनाएं, तो ध्यान आता है, साल 1998 में दिल्ली विधानसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तब उप-राज्यपाल ने बुला-बुलाकर सबसे संवाद किया था और जिस नेता ने विश्वसनीय बहुमत का भरोसा दिलाया था, उसे ही सरकार गठन के लिए बुलाया गया था। साल 2002 में जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था, तब भी महामहिम राज्यपाल ने सभी दलों से परामर्श किया और उसके बाद जब उन्हें लगा कि स्थिर सरकार बन सकती है, तब उन्होंने सरकार बनाने का न्योता दिया। कर्नाटक में साल 2023 का उदाहरण भी ताजा है, जब राज्यपाल के प्रयासों से बहुत शांतिपूर्वक ढंग से नई सरकार का गठन हुआ। भारतीय राजनीति में राज्यपाल से जुड़े बुरे उदाहरण कम ही हैं, लेकिन उनकी चर्चा ज्यादा होती है।

भारत में ही नहीं, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भी ऐसी ही परामर्श परंपरा की पालना होती है। अच्छा यही है कि तकनीकी आधार पर फैसला लेने के बजाय परामर्श का सहारा लिया जाए। परामर्श से विवादों का निपटारा हो जाता है। राज्यपालों के लिए सबसे अच्छी विधि यही है कि वे सबकी बात सुनने के बाद यथोचित निर्णय तक पहुंचें। आखिर संवाद से ही पता चलता है कि कौन ठीक से सरकार चला सकता है। सभी राज्यपालों को एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अच्छे राज्यपाल ही ज्यादा हुए हैं।

राजनेताओं को भी चाहिए कि वे राज्यपाल के साथ सहयोग करें। हार को स्वीकार न करने से भी समस्या होती है और नई सरकार के गठन में कठिनाई आती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जब हार स्वीकार नहीं की, तब अप्रिय स्थिति बनी और यहां पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना किया, तब भी अप्रिय स्थिति बनी। राजनेताओं को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि राज्यपाल को सही निर्णय लेने में सुविधा हो।

तमिलनाडु में राज्यपाल को लेकर पहले भी शिकायतें रही हैं, लेकिन 1990 के दशक में वहां के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह को भी याद करना चाहिए। उन्होंने अपने समय में तमिलनाडु और वहां की राजनीति को अपने कुशल नेतृत्व से सहारा दिया था।

ताजा विवाद तमिलनाडु में तब खड़ा हुआ, जब राज्यपाल ने सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता विजय को सरकार बनाने के लिए तुरंत आमंत्रित नहीं किया। उनका कहना था कि पहले विजय बहुमत का समर्थन-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे में, यह केवल एक राजनीतिक प्रश्न नहीं रह जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसा कि इस बार तमिलनाडु में हुआ, कई बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं भी मिलता है। ऐसे में, संविधान राज्यपाल से अपने विवेक से ऐसा निर्णय लेने की अपेक्षा करता है, जो राष्ट्रहित में हो। यही कारण है कि ऐसे मामलों में सांविधानिक परंपराओं और राज्यपाल के विवेक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

सामान्य परंपरा यह रही है कि यदि किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, तो उसके नेता को पहले बुलाया जाए। यदि स्पष्ट बहुमत न हो, तो सबसे बड़े दल के नेता को अवसर दिया जा सकता है, बशर्ते वह बहुमत सिद्ध करने का दावा करे। यदि कोई चुनाव पश्चात गठबंधन बहुमत का समर्थन प्रस्तुत कर दे, तो उसे भी आमंत्रित किया जा सकता है। कई बार बाहर से समर्थन प्राप्त अल्पमत सरकार को भी अवसर दिया गया है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी इसी प्रकार के सिद्धांत सुझाए थे, ताकि राज्यपाल का विवेक पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ हो।

तमिलनाडु के मौजूदा मामले में राज्यपाल का यह कहना कि पहले समर्थन-पत्र प्रस्तुत किए जाएं, असांविधानिक नहीं कहा जा सकता। यदि किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल का दायित्व है कि वह स्थिर सरकार की संभावना देखे। कुछ जटिल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विकल्प भी सुझाया है कि बहुमत का परीक्षण लोकभवन के बजाय विधानसभा के भीतर होना चाहिए। 1994 के प्रसिद्ध एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी सरकार का बहुमत सदन के पटल पर ही परखा जाना चाहिए। यह निर्णय भारतीय संघीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

साल 2018 में कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस और जनता दल (एस) ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने शीघ्र 'फ्लोर टेस्ट' कराने का निर्देश दिया। अंततः सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी। इस प्रकरण से यह स्पष्ट हुआ कि सबसे बड़े दल को बुलाना अपने आप में असांविधानिक नहीं है।

समग्रता में राज्यपाल को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे किसी राजनीतिक दल को यह महसूस न हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। राजनीतिक, सामाजिक और सांविधानिक अंतर्संबंधों के ताने-बाने गणित के सूत्रों की तरह सीधे और सपाट नहीं होते। सामाजिक-राजनीतिक विकास के साथ-साथ पूरी दुनिया में वे जटिलतर होते जा रहे हैं। इसलिए हर मामला अपनी पृष्ठभूमि के कारण दूसरे मामलों से अलग होता है। किंतु राजनीतिक दलों और लोकभवन, दोनों के लिए यह बात शाश्वत सत्य है कि संविधान और उसकी मर्यादा सर्वोपरि है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# तभी आत्मबोध होगा

जिस प्रकार मकड़ी (जाल के) धागे को अपने से बाहर निकालती है और फिर से उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार मन संसार को अपने से बाहर निकालता है और फिर से उसे अपने में समेट लेता है। जब मन स्वयं को छोड़ देता है, तब संसार प्रकट हो जाता है। अतः जब संसार प्रकट होता है, तब आत्मा प्रकट नहीं होती और जब आत्मा प्रकट होती है (चमकती है), तो जगत प्रकट नहीं होता।

जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है, तो मन शांत हो जाएगा और स्वयं को अवशेष के रूप में छोड़ देगा। मन हमेशा किसी स्थूल (भौतिक शरीर) पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में रहता है; यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। मन को ही सूक्ष्म शरीर या आत्मा कहा जाता है। जो शरीर में 'मैं' के रूप में उगता है, वह मन है। यदि कोई पूछे कि मैं का विचार सबसे पहले शरीर में कहां से उठता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय में उठता है। वह मन की उत्पत्ति का स्थान है। मन में उठने वाले सभी विचारों में मैं-विचार सबसे पहले आता है। इसके बाद ही अन्य विचार आते हैं।

'मैं कौन हूं?' यह विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा और चिता को भड़काने वाली लाठी की तरह अंत में स्वयं भी जल जाएगा। तभी आत्मबोध होगा। जैसे ही कोई विचार उठे, व्यक्ति को सचेत होकर पूछना चाहिए, 'यह विचार किसके मन में उत्पन्न हुआ है?' जो उत्तर सामने आएगा, वह होगा 'मेरे।' इसके बाद यदि कोई पूछता है, मैं कौन हूं? मन अपने स्रोत पर वापस चला जाएगा और जो विचार उत्पन्न हुआ, वह शांत हो जाएगा।

**रमण महर्षि**

मार्क कार्नी | प्रधानमंत्री, कनाडा

हम गाजा में पैदा मानवीय संकट को लेकर बहुत चिंतित हैं और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार के विरोध में अपने रुख पर कायम हैं। हम इस क्षेत्र में शांति के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।

# समाज में पनपती विकृतियां रिश्तों पर भी हावी

हाल ही में कानपुर में एक पिता ने अपनी 11 साल की दो मासूम जुड़वां बेटियों की निर्मम हत्या कर दी। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन समाज में पनपती विकृतियां अब आपसी रिश्तों पर भी हावी होती प्रतीत हो रही हैं। यह बर्बादी की एक नई कहानी है, जो अब धीरे-धीरे सामान्य बनती जा रही है। यह अपने-आप में पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले दरकते रिश्तों की दास्तां बयान करते हैं। जिन रिश्तों और संबंधों को किसी समय प्रेम, विश्वास और सुरक्षा से बंधा पाया जाता था, वही अब स्वार्थी, अनैतिक आचरण में लिप्त होकर कलियुग कहे जाने वाले समय की कालिख बनने का काम कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर समाज कहां जा रहा है?

कानपुर घटनाक्रम में हत्या के पीछे तनाव व नशे को जांच का आधार बनाया गया, लेकिन देश का कोई भी कोना ऐसे मामलों से शायद ही अब अछूता हो। इससे पहले नोएडा में कथित तौर पर आरुषि तलवार और गुरुग्राम में राधिका यादव की अपने ही पिता द्वारा जघन्य हत्या जैसे मामले टूटते भरोसे की कहानी बयां करते हैं। राजस्थान के अलवर और यूपी के मेरठ में पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने, लखनऊ में बेटे द्वारा कारोबारी पिता की हत्या करने जैसे दिल दहला देने वाले प्रकरणों ने जनमानस को हिलाकर रख दिया है।

असल में अब समाज में रिश्तों का कत्ल एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिनके स्वरूप अलग-अलग देखे जा सकते हैं। जहां आपसी विवाद, प्रॉपर्टी और पैसा, अनैतिक संबंध, अहंकार और भरोसे की कमी के कारण भाई-भाई, बेटा-पिता, पिता-बेटी और पति-पत्नी के रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। अत्यधिक स्वार्थ, लालच और अहंकार के कारण व्यक्ति अपनों के प्रति संवेदनहीन हो रहा है। रिश्तों में प्यार और भरोसे की कमी के कारण वे बोझ बनकर अंततः टूट जाते हैं। आपसी सम्मान और प्रेम में कमी आ रही है, जिससे रिश्तों की परिभाषा बदल रही है और सामाजिक सौहार्द खत्म हो रहा है। परिणामस्वरूप, परिवार तबाह हो रहे हैं और समाज शर्मसार हो रहा है। इस तरह के मामले बताते हैं कि भौतिक सुख-सुविधाओं की चाह में इंसानियत खत्म हो रही है।

देश में हरेक रोज कहीं न कहीं हो रही इस तरह की घटना बता रही है कि परिवार और समाज में सुरक्षा का भाव दिनों-दिन कम हो रहा है। तनाव के चलते रिश्तों में खटास होने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मानवता पर सवाल उठने लगे हैं। प्यार और स्नेह की जगह अब नफरत ले रही है, जो सभ्य समाज के लिए बेहद खतरनाक है।

**मोनिका शर्मा,** टिप्पणीकार

**अनुलोम-विलोम**

## रिश्ते में विकृतियां

# नशा और संवादहीनता इसका बड़ा कारण

इन दिनों रिश्तों में खटास और खूनी खेल का जो दौर चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण नशाखोरी का आम हो जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज ही खराब हो गया है या हमारी संस्कृति नष्ट हो चुकी है। ऐसा सोचना निराशा के गर्त में डूब जाने जैसा होगा। समाज अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन बीच-बीच में इसमें कई विघ्न-बाधाएं आती रहती हैं। यह क्षणिक आवेग का परिणाम है। जब व्यक्ति नशा कर लेता है, उसके बाद वह यह नहीं समझ पाता कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है? वह कोई सगा-संबंधी है या फिर कोई विरोधी? ऐसे में, समाज में रिश्तों का कत्ल आम बात हो गई है।

खबरों में अक्सर हम इस तरह की घटनाएं घटित होते सुनते हैं। इससे परिवार और समाज में सुरक्षा बोध कम होता जा रहा है। इससे होने वाले तनाव के चलते रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मानवता पर सवाल उठने लगे हैं। प्यार और स्नेह की जगह अब नफरत ले रही है, जो समाज के लिए खतरनाक है। यह आवश्यक है कि हम अपने रिश्तों में आपसी विश्वास, समझ और प्रेम को बहाल करें, ताकि समाज में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे।

इन परिस्थितियों को देखते हुए आज जरूरी हो गया है कि समाज छोटे-छोटे स्तर पर समुदायों को संभालने की दिशा में अग्रसर हो। परिवार में हर सदस्य एक-दूसरे से खुलकर बात करे और सामने खड़ी समस्याओं पर गहनता से विचार-विमर्श करे। उसका निदान करे। बेहतर है कि परिवार में बड़े-बुजुर्गों की सलाह को अहमियत दी जाए। उनके पास अपना लंबा अनुभव होता है। साथ ही वे किसी समस्या के हर पहलू को बारीकी से देखकर कोई सलाह देते हैं। परिवार में हर सदस्य के बीच ईमानदारी भी जरूर होनी चाहिए। बिना ईमानदारी के आपसी विश्वास जम नहीं पाता है।

परिवार और समाज के स्तर पर जो अविश्वासपूर्ण माहौल बनता है, वह कोई एक दिन के तनाव या आक्रोश का नतीजा नहीं है। पारिवारिक स्तर पर रिश्तों का कत्ल करने की नौबत आने में लंबे समय का तनाव और आक्रोश काम करता है। इसमें सबसे बड़ा कारण आपस में संवादहीनता ही है। हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हो रहे खूनी संघर्षों के पीछे मुख्य कारण अत्यधिक भौतिकवादी सोच, स्वार्थ, संपत्ति का लालच है। समाज को इस विकट स्थिति से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सभी स्तर पर एकजुटता लानी होगी, तभी सुधार संभव है। ऐसा करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

**विभा चौधरी,** सामाजिक कार्यकर्ता

# कार में हवादार सीट का बढ़ता चलन

**तेज गर्मी और ट्रैफिक के बीच वेंटिलेटेड सीट्स अब कोई प्रीमियम फीचर नहीं है। कुछ किफायती कारों में भी यह सुविधा मिलने लगी है, जो सफर को ज्यादा आरामदायक बनाती है। इसे आप अपनी कार में भी लगवा सकते हैं। क्या है इसकी तकनीक और बाजार? क्या रखें सावधानियां? आइए जानें...**

एक सर्वे के अनुसार भारत में 70 फीसदी से ज्यादा कार खरीदार अब वेंटिलेटेड सीट्स को अहम फीचर मानते हैं। गर्मियों में लंबे समय तक ड्राइविंग के दौरान सीट पर पसीना और असहजता आम समस्या होती है, इसलिए यह फीचर किफायती कार खरीदारों की चाहत भी बन रहा है। कई कंपनियां अपने किफायती वेरिएंट में इसे लेकर भी आई हैं, जैसे रेनॉ कीगर। इस कार के टॉप स्पेक इमोशन ट्रिम में आगे की सीट्स में यह फीचर मिलता है। इस ट्रिम की कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच रखी गई है। यह वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स वाली सबसे किफायती कारों में है। ऑटोकार इंडिया के एक लेख के अनुसार 2018 में हुंडई वरना कार के माध्यम से वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर बीस लाख रुपये तक के सेगमेंट की कारों में शुरू हुआ था। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसे किया सोनेट, टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन और एमजी जैसे बड़े कार ब्रांड्स ने भी पेश किया है।

महिंद्रा कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स सेल्स से जुड़े धरमपाल के अनुसार फिलहाल यह फीचर 10 लाख रुपये से ज्यादा की कारों, वह भी अधिकतर उनके टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा। उनका कहना है कि इसे आफ्टरमार्केट लगवाया जा सकता है, लेकिन बाहर से फिटमेंट करवाते समय क्वालिटी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एसी सिस्टम में छेड़छाड़ कार की रीसेल वैल्यू को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल मास मार्केट की कारों में वेंटिलेटेड फीचर केवल आगे की सीटों या ड्राइवर सीट में मिल रहा है। दोनों पंक्तियों में यह सुविधा आमतौर पर 15 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली कारों में आ रही है। उदाहरण के लिए किआ साइरोस की शुरुआती कीमत 8.39 लाख रुपये है, लेकिन दोनों पंक्तियों में वेंटिलेशन वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपये से अधिक है।

## कितनी तरह के सिस्टम

वेंटिलेटेड सीट्स को एसी सीट या कूल्ड सीट्स मान लिया जाता है। दोनों काफी अलग हैं। वेंटिलेटेड सीट में बने छोटे छिद्रों से हवा पहुंचकर पसीना और गर्मी कम करने में मदद करती है।

■ **फैन वाली सीट्स :** फिलहाल बजट कारों में ज्यादातर फैन-बेस्ड वेंटिलेटेड सीट्स दी जाती हैं। इनमें सीट के अंदर छोटे कई पंखे लगे होते हैं। ये पंखे केबिन की हवा को खींचकर आपकी पीठ तक पहुंचाते हैं। इस तरह पीठ पर पसीने से राहत मिलती है। इन्हें सीट के साइड में दिए गए बटन से कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं, प्रीमियम कारों में दमदार ब्लोअर-आधारित वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं।

■ **कूल्ड/एसी सीट्स :** ये एक एअर कंडीशनर की तरह काम करती हैं। इसमें कुछ डिवाइस जोड़ा जाता है, ताकि केबिन की गर्मी का असर सीट पर ना पड़े। जिससे सीट ज्यादा ठंडी और आरामदायक महसूस होती है।

कई कॉम्पैक्ट एसयूवी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आ रही हैं।

## क्यों हो रही लोकप्रिय

वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइविंग के दौरान सीट पर आए पसीने से बचाती हैं, जिससे लंबे सफर में थकान और असहजता कम महसूस होती है।

**लेदराइट के शौकीनों के लिए :** आजकल कारों में इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक लेदर सीट्स गर्मी ज्यादा रोकती हैं, इसलिए इनके साथ वेंटिलेशन फीचर काफी उपयोगी माना जाता है।

**सर्दियों में भी उपयोगी :** वहीं कई प्रीमियम कारों में हीटेड सीट्स भी मिलती हैं, जो सर्दियों में सीट को गर्म रखने में मदद करती हैं।

## अब अलग से भी उपलब्ध

वेंटिलेटेड सीट्स का बड़ा आफ्टरमार्केट भी है। यानी लोग इन्हें बाहर से भी लगवाते हैं। बाजार में सीट कूलिंग और वेंटिलेशन किट्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी फिटेड ऐसी सीट्स का किफायती विकल्प देते हैं। हालांकि बाहर से इन्हें लगवाने में कुछ मामलों में आपकी कार की सीट, वायरिंग और इंटीरियर में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। भारत में रिगगियर, एअरमैग, ऑटोफॉर्म और लुकैरियो जैसे आफ्टरमार्केट ब्रांड्स के वेंटिलेटेड सीट कवर आम उपलब्ध हैं। साधारण प्लग-एंड-प्ले सीट कवर आमतौर पर 6,000 से 10,000 रुपये तक मिल जाते हैं और इन्हें 12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट से चलाया जा सकता है। वहीं सीट के अंदर फिट होने वाली इंटरनल किट्स का खर्च करीब 12,000 से 18,000 रुपये तक आ सकता है। कुछ ऐसे प्रीमियम मॉडिफिकेशन और भी महंगे होते हैं।

## बाद में भी जोड़ सकते हैं यह फीचर...

■ यदि आपकी कार की सीट में साइड एअरबैग्स हैं, तो कभी भी बाहरी सीट कवर न लगवाएं। यह एयरबैग को खुलने से रोक सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। पोर्टेबल कूलिंग कुशन आजमा सकते हैं।

■ आफ्टरमार्केट सिस्टम में कभी-कभी शोर महसूस हो सकता है।

■ अगर किट के लिए तारों को काटा गया, तो कार की इलेक्ट्रिकल वारंटी खत्म हो सकती है।

■ सस्ते मॉडल्स से बचें। कंपनी फिटेड सिस्टम में सुनिश्चित करें कि इंजन बंद होने पर यह सिस्टम चालू न रहे, वरना बैटरी पर जोर पड़ता है।

## चाहिए ज्यादा रखरखाव

■ **सफाई :** वेंटिलेटेड सीट्स के छिद्रों में धूल जाती है। इन्हें ज्यादा और गहरी सफाई की जरूरत होती है।

■ **तरल पदार्थों से बचाव :** इन सीटों पर पानी गिरने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर सीट में इलेक्ट्रिक पंखे होते हैं।

■ **सॉफ्ट ब्रश का उपयोग :** अगर सीट गंदी हो जाए, तो गीले कपड़े के बजाय सूखे या हल्के नम सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। -रिया शर्मा

## इस फीचर की कौन सी कारें

■ **माइक्रो या कॉम्पैक्ट एसयूवी में :** इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी कही जाने वाली पंच के टॉप मॉडल एंपॉवर्ड प्लस ट्रिम में है। कीमत 12.29 लाख से 14.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

वहीं किया सोनेट, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है, बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है। यह एचटीएक्स ट्रिम में मिलता है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपये के आसपास आएगी। वही टाटा नेक्सन के फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस ट्रिम में मिलती हैं। हुंडई क्रेटा के एसएक्स ट्रिम में मिलता है।

■ **एमपीवी में :** मारुति सुजुकी एक्सएल6 एक प्रीमियम एमपीवी है, जो वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई हाई-एंड फीचर्स के साथ आती है। कीमत वेरिएंट के अनुसार 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा हो सकती है। यह फीचर केवल इसके टॉप-टियर अल्फा प्लस ट्रिम में ही उपलब्ध है।

■ **सेडान में :** हुंडई वर्ना के एचएक्स 6प्लस, एचएक्स8 और एचएक्स10 में यह फीचर फ्रंट सीट्स के लिए मिलता है। इसकी कीमत 13-15 लाख के आसपास मिल सकती है। स्कोडा स्लाविया, फोक्सवैगन वर्टुस में यह बीस लाख रुपये की कीमत के अंदर वेरिएंट में उपलब्ध मिल सकती है।

मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। कीमत 15.50 लाख से 19.90 लाख रुपये तक के बीच होगी।

---

गैजेट

# दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन

## वन प्लस नॉर्ड सीरीज

नया लॉन्च हुआ वन प्लस नॉर्ड सी-6 स्मार्टफोन इस सीरीज का ज्यादा दमदार वर्जन है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7एस जेन 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। 50एमपी पीछे का कैमरा है और 32एमपी का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए है। सबसे बड़ी खासियत 8000एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है और 80वाट तेज चार्जिंग के साथ आती है।

**नॉर्ड सी-6 लाइट :** वन प्लस का ही नॉर्ड सी-6 लाइट सस्ते सेगमेंट में पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो 6.72 इंच का एचडी डिस्प्ले 120हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है और कुछ एप्स में 144 हर्ट्ज तक भी चलता है। यूएफएस 3.1 स्टोरेज है, जिससे एप्स जल्दी खुलते हैं। फोन में 50एमपी पीछे और सामने 8एमपी का कैमरा है, जो वीडियो कॉल और सामान्य फोटो के लिए ठीक है। 7000एमएएच की बैटरी भी है।

**कीमत :** वेरिएंट के अनुसार नॉर्ड सीई 6 लाइट की शुरुआती कीमत 20,999 रुपये और नॉर्ड सीई 6 की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। दोनों ही फोन आधिकारिक वेबसाइट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स मंच पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। नॉर्ड सी-6 को फ्रेश ब्लू, लूनर पर और पिच ब्लैक रंगों में पेश किया गया है।

## आईटेल ए100 सी

देसी कंपनी आईटेल के नए मिलिट्री ग्रेड फोन में 2जीबी से 4जीबी तक रैम और 64जीबी से 128जीबी तक स्टोरेज विकल्प मिलते हैं। यह व्हाट्स एप, यूट्यूब और कॉलिंग जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है। इसमें लंबी चलने वाली 5000एमएएच की बड़ी बैटरी, टाइप-सी चार्जिंग और लगभग 15वाट की सामान्य चार्जिंग स्पीड मिलती है।

**कैमरा और फीचर्स :** फोटोग्राफी के लिए पीछे 8एमपी और सामने 5एमपी कैमरा मिलता है, जो कम रोशनी में भी फोटो को थोड़ा साफ और बेहतर दिखाने में मदद करते हैं। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के साथ आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे इसे टीवी या एसी रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास फीचर अल्ट्रालिंक कॉलिंग है, जिसमें कुछ स्थितियों में ब्लूटूथ के जरिए आसपास के फोन से कॉल जैसी सुविधा मिल सकती है।

**डिजाइन और डिस्प्ले :** 6.6 इंच की बड़ी एचडी+ स्क्रीन मिलती है, जो सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक है। इसका डिजाइन करीब 8.5 एमएम पतला है। इसका डिजाइन इसे हल्के झटकों, गिरने व पानी के छींटों को सहने में सक्षम बनाता है।

-फीचर डेस्क

### कीमत

फोन की शुरुआती कीमत मात्र 7999 रुपये रखी गयी है। यह सिल्क ग्रीन, टाइटेनियम गोल्ड और प्योर ब्लैक रंगों में खरीदा जा सकता है। यह फोन केवल 4जी नेटवर्क पर ही काम करता है।

---

# पहले से ज्यादा कारगर हुआ चैट जीपीटी

**ओपन एआई ने चैट जीपीटी के लिए नया जीपीटी-5.5 इन्स्टेंट मॉडल पेश किया है, जिसे पहले से ज्यादा स्मार्ट बताया जा रहा है। कंपनी के अनुसार यह मॉडल कम गलतियां करेगा और यूजर्स को बेहतर अनुभव देगा।**

टेक्नोलॉजी

**एआई** चैटबॉट चैट जीपीटी अब सिर्फ सवाल-जवाब का टूल नहीं, बल्कि कई यूजर्स की डिजिटल जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसी के साथ चैट जीपीटी में जीपीटी-5.5 इन्स्टेंट ने पुराने जीपीटी -5.3 इन्स्टेंट की जगह लेनी शुरू कर दी है। ओपन एआई के अनुसार नया मॉडल रोजमर्रा के सवालों को बेहतर समझ सकेगा। मेमोरी और पर्सनलाइजेशन फीचर्स में भी सुधार किए गए हैं, जिससे यूजर्स को जरूरत के हिसाब से जवाब मिल सकेंगे।

## जीपीटी-5.5 में नया क्या है

■ **ज्यादा भरोसेमंद जवाब :** ओपन एआई के अनुसार जीपीटी -5.5 इन्स्टेंट पहले से ज्यादा भरोसेमंद बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि मेडिकल, कानून व फाइनेंस जैसे संवेदनशील मामलों में इसके इस्तेमाल से गलत जवाब पाने की संभावना 52.5% तक कम हो जाएगी। वहीं, कठिन सवालों और और बातचीत में भी कम गलतियां करता है।

■ **रोजमर्रा के कामों में बेहतर समझ :** जीपीटी-5.5 इन्स्टेंट STEM से जुड़े सवालों, फोटो एनालिसिस और वेब सर्च जैसे रोजमर्रा के कामों को पहले से बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। कंपनी का यह भी कहना है कि नए मॉडल के जवाब अब ज्यादा सीधे और संक्षिप्त होंगे, लेकिन जरूरी जानकारी बनी रहेगी।

### कब कर सकेंगे इस्तेमाल

ओपन एआई ने जीपीटी-5.5 इन्स्टेंट को सभी यूजर्स के लिए धीरे-धीरे उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह पुराने जीपीटी-5.3 इन्स्टेंट की जगह ले लेगा। प्लस और प्रो यूजर्स के लिए अभी एक सुविधा है कि वे अगले 3 महीनों तक जीपीटी-5.3 इन्स्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यह विकल्प पूरी तरह हटा दिया जाएगा।

■ **कम सवाल, सीधा जवाब :** ओपनएआई के अनुसार नया मॉडल अब बेवजह ज्यादा सवाल नहीं पूछता और जरूरत से ज्यादा इमोजी का इस्तेमाल भी नहीं करता है। इसके जवाब पहले के मुकाबले ज्यादा सीधे, संक्षिप्त और कामकाजी जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं।

■ **पहले से ज्यादा समझदार :** ओपनएआई के अनुसार नया मॉडल अब पुरानी चैट, अपलोड की गई फाइल्स और आपके ईमेल अकाउंट से जानकारी बेहतर तरीके से समझ सकेगा। इसके जवाब यूजर की जरूरत और पिछली बातचीत के हिसाब से ज्यादा व्यक्तिगत होंगे। साथ ही, पुरानी जानकारी ढूंढ़ने की क्षमता भी तेज हुई है, जिससे बार-बार वही बातें दोहराने की जरूरत कम पड़ेगी।

■ **नया 'मेमोरी सोर्सेज' फीचर :** चैट जीपीटी में नया 'मेमोरी सोर्सेज' फीचर जोड़ा जा रहा है। इसके तहत एआई बताएगा कि किसी व्यक्तिगत जवाब के लिए उसने कौन-सी पुरानी जानकारी का इस्तेमाल किया है। यूजर्स चाहें तो पुरानी या गैरजरूरी जानकारी को आसानी से एडिट या डिलीट कर सकेंगे। साथ ही, किसी चैट को शेयर करने पर ये मेमोरी सोर्सेज दूसरों को दिखाई नहीं देंगे।

mint

---

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

**मेष :** मन परेशान रहेगा। संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं।

**वृष :** आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

**मिथुन :** आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

**कर्क :** आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

**सिंह :** आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। किसी पारिवारिक कारोबार की पुनः शुरुआत हो सकती है। पिता का सान्निध्य मिलेगा।

**कन्या :** मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

**तुला :** मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय के साधन भी बन सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

**वृश्चिक :** आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा।

**धनु :** पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है।

**मकर :** मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।

**कुंभ :** मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

**मीन :** धैर्यशीलता बनाए रखें। आत्मसंयत रहें। पिता का साथ मिलेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।

## व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

**09 मई,** शनिवार, **शक संवत्:** 19,वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग:** 26, वैशाख मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम:** 21, जिल्काद, 1447 **विक्रमी संवत्:** ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02.03 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11.25 मिनट तक पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, शुक्ल योग रात्रि 02.36 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग। चंद्रमा मकर राशि में (दिन रात)।

**सूर्य उत्तरायण।** सूर्य उत्तर गोल। वसन्त ऋतु। प्रात: 09 बजे से प्रात: 10.30 मिनट तक राहुकालम्। कालष्टमी।

## वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

**कृपया यह बताएं कि दैनिक जीवन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा भाग्योदय हो सके।** - कृति नारायण, मथुरा

■ अटका हुआ धन पाने के लिए शुक्रवार को अपने लॉकर, गल्ले को साफ करना चाहिए।

■ जिस घर में आए हुए मेहमान का स्वागत मुस्कान के साथ किया जाता है, वहां पर खुद बरकत होने लगती है। शाम के समय दीपक जलाने से दरिद्रता एवं डर खत्म होते हैं।

■ रात को सोते समय यदि जूते-चप्पल उल्टे पड़े हों, तो धन की चाल भी उल्टी होती है।

■ खाना खाते समय शिकायत करने की आदत हो, तो वहां बेवजह परेशानी बनी रहती है।

■ फटे वस्त्र पहनकर पूजा करने से भाग्य खराब होता है। पूजा साफ वस्त्र पहनकर करें।

## वर्ग पहेली: 8323

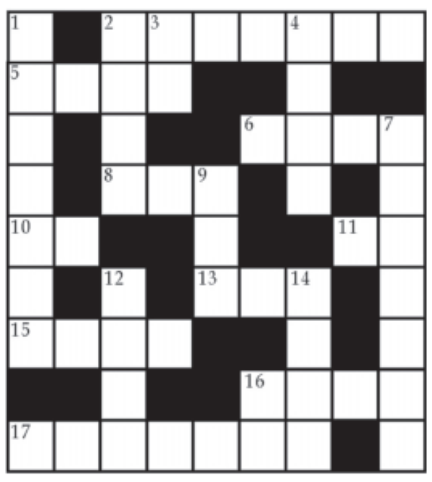

**बाएं से दाएं**

2. राज सभा बुलाना; बैठक करना; गपबाजी करना (4,3)
5. अन्न जिसकी दाल बनाई जाती है (4)
6. पृथ्वी; धरती; सतह; क्षेत्र (4)
8. अबोध; अनाड़ी; नासमझ (3)
10. डाह; दाह; दग्ध करने की क्रिया; लांछन (2)
11. वस्त्र; परदा; आड़; दरवाजा; पट्टिका (2)
13. जिसका कथन या वर्णन हुआ हो; जो कहा तो गया हो, पर ठीक न सिद्ध हो (3)
15. प्रलय; विपदा (4)
16. कपाल संबंधी; मनुष्य का कपाल रखने वाला साधु; तंत्र साधक (4)
17. विवेचन करना; मंत्रणा करना (4,3)

**ऊपर से नीचे**

1. मन को कष्ट पहुंचाने वाला; दिल दहलाने वाला (3,4)
2. तपना; धधकना; लपट फेंकते हुए जलना (4)
3. झील; ताल; युद्ध; कछार; रण (2)
4. आनंदित होना; उत्साहित होना; ध्वजारोहण करना; हिलना-डुलना (4)
7. भाग्य का जोर मारना; भाग्य चमकना (3,4)
9. औषर, करकच; खारी; लवण (3)
12. दृढ़ता; जीवनी शक्ति; उत्साह; साहस (4)
14. शारीरिक या मानसिक कष्ट देना; व्याकुल करना; तंग करना (4)
16. काज; काम; कार्य; क्रिया (2)

**हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली**

(उत्तर अगले अंक में)

## वर्ग पहेली: 8322

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 म | ■ | 2 घ | र | 3 का | न | घा | 4 ट | का |
| द | ■ | ट | ■ | न | ■ | ■ | र | ■ |
| 5 द | र्द | ना | क | ■ | 6 ह | र | का | रा |
| गा | ■ | क्र | ■ | 7 क | ■ | ■ | ना | ■ |
| र | ■ | 8 म | सा | ले | दा | 9 र | ■ | 10 री |
| ■ | 11 चु | ■ | ■ | वा | ■ | ग | ■ | ग |
| 12 चि | प | का | ना | ■ | 13 भ | ड़ | क | ना |
| ■ | चा | ■ | ■ | 14 डं | ■ | वा | ■ | श |
| 15 जे | प | त | प | क | र | ना | ■ | क |

## सुडोकू: 8305

*कठिन

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | 6 | 2 | | |
| | 8 | 1 | | 7 | | | 5 | 3 |
| 7 | | | | 5 | | | | |
| | | 2 | | | 8 | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | 6 | | 1 | | | 3 | | |
| | | | | 8 | | | | 5 |
| 1 | 7 | | | 4 | | 9 | 6 | |
| | | 8 | 7 | | | | | 1 |

**खेलने का तरीका :** दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

## सुडोकू: 8304

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 |

*तारों को छू लेने की चाह एक महत्त्वाकांक्षा है, जबकि दिलों को छू लेने की चाह अक्लमंदी है।*

*– माया एंजिलो*

# अपराध का दायरा

देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा चाक-चौबंद होगी और यहां अपराध को ज्यादा सक्षम तरीके से काबू में किया जाएगा। मगर समय-समय पर आने वाले अपराध के आंकड़ों में यही विडंबना सामने आती है कि दिल्ली में अपराधियों का दुस्साहस उफान पर है और उन पर पूरी तरह लगाम लगा पाना पुलिस-प्रशासन के लिए संभव नहीं हो सका है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दर्ज हुए आपराधिक मामलों के संदर्भ में देश के अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली की दशा ज्यादा खराब है। सवाल है कि हर स्तर पर कानून-व्यवस्था के पुख्ता होने के दावों के बावजूद स्थिति ऐसी क्यों है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 'भारत में अपराध 2024' रपट में यह उजागर हुआ है कि देश के उन्नीस महानगरों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा संज्ञेय अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि पिछले दो वर्ष में अपराधों में गिरावट देखी गई है, इसके बावजूद एनसीआरबी के आंकड़े यही बताते हैं कि अपराध और अपराधियों पर काबू पाने में यहां की पुलिस को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है।

आंकड़ों के मुताबिक, देश के उन्नीस महानगरों में कुल पांच लाख तिरानबे हजार छियानबे मामले दर्ज हुए, जिनमें अकेले दिल्ली की भागीदारी छियालीस फीसद से ज्यादा रही। कहा जा सकता है कि देश के कुल महानगरों में जितने अपराध होते हैं, उनमें से हर दूसरा दिल्ली में दर्ज हुआ। हालांकि एनसीआरबी की मानें तो एक पहलू यह है कि जिन राज्यों में आनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा है, वहां लोग जघन्य से लेकर छोटे-बड़े सभी अपराधों की शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं। जिन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम दर्ज हो सकते हैं। यानी यह स्वीकार किया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में आज भी सुविधा न होने या फिर प्रक्रिया की जटिलता की वजह से बहुत सारे लोग पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर पाते। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराध के कितने पीड़ित इंसाफ का इंतजार करते रह जाते होंगे। इस लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में एक तंत्र के काम करने के ढांचे में बेहतरी लाई गई है। मगर सवाल है कि अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार और संबंधित महकमे क्या करते हैं।

इसके अलावा, वक्त के साथ एक नई जटिलता यह पैदा हुई है कि रोजमर्रा की गतिविधियों के संदर्भ में जैसे-जैसे लोगों की निर्भरता डिजिटल माध्यमों पर बढ़ रही है, अब अपराधियों की नजर उधर भी खिसक रही है। मसलन, खुद एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराधियों के गिरोह अब डिजिटल संसार में अपनी दखल बढ़ा रहे हैं। साइबर अपराधों में करीब अठारह फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें आनलाइन ठगी, 'डिजिटल अरेस्ट' और भयादोहन जैसे मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। यह हाल के वर्षों में उपजी नई चुनौती है, जिससे निपटना बेहद जरूरी है। महानगरों में सुविधाओं से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब कुछ अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर और दुरुस्त होने की उम्मीद की जाती है। उसमें भी अगर अपराध के मामले में दिल्ली कई महानगरों को पीछे छोड़ रही है, तो यह सोचने का वक्त है कि आखिर यहां सरकार, पुलिस और खुफिया तंत्र तथा अन्य एजंसियों के बीच किस स्तर पर तालमेल और सक्रियता में कमी है, जिसमें तत्काल सुधार की जरूरत है।

# सेहत से खिलवाड़

स्वस्थ रहने के लिए फल और हरी सब्जियों का सेवन जरूरी माना जाता है। चिकित्सक भी लोगों को अपने रोजमर्रा के आहार में इन्हें शामिल करने की सलाह देते हैं। मगर इनकी पैदावार में जहरीले रसायनों का बढ़ता इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फलों को समय से पहले पकाने, चमकदार बनाने और हरी सब्जियों का आकार जल्दी बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मनुष्य के लिए घातक हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल में मुंबई के पायधोनी इलाके में सामने आया, जहां तरबूज खाने के बाद एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। फोरेंसिक जांच रपट के मुताबिक, मृतकों के आंतरिक अंगों और तरबूज के नमूनों में चूहे मारने की दवा के अंश पाए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तरबूज के अंदर यह दवा कैसे आई। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं तरबूज को पकाने के लिए तो इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया!

इस मामले में पुलिस की जांच के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर परिवार के चार सदस्यों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? फसलों को कीटों और अन्य जंतुओं से बचाने के लिए कीटनाशक तैयार किए गए हैं, लेकिन इनका अंधाधुंध और अवैज्ञानिक इस्तेमाल अब मानव के स्वास्थ्य तथा जीवन पर भारी पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि कच्चे फल-सब्जियों को पकाने और उनका आकार जल्दी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन से उनके भीतर रसायन डाला जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से कीटनाशकों की खरीद-बिक्री और इनके इस्तेमाल को लेकर नियम-शर्तें लागू की गई हैं, लेकिन इन पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करने में विभिन्न स्तरों पर लापरवाही साफ नजर आती है। ऐसे में इसकी नितांत जरूरत है कि संबंधित महकमे की ओर से नियमित तौर पर फल-सब्जियों की जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से सेहत पर दुष्प्रभाव को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो।

# सियासी विसंगतियों में उलझा समाज

**किसी वक्त राजनीति का अर्थ राज्य की वह नीति होती थी जो लोक कल्याण और जनसेवा पर आधारित होती थी। मगर आज यह तस्वीर बदल गई है।**

**सुरेश सेठ**

राजनीति विज्ञान को जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल से जोड़ते हैं, तो हम पाते है कि उस समय नैतिक मूल्यों और आदर्शों की नींव पर राजनीति होती थी। यह इतनी शिक्षाप्रद थी कि वर्षों तक भारतीय राजनीति का सैद्धांतिक मार्ग बनी रही। किसी वक्त राजनीति का अर्थ राज्य की वह नीति होती थी जो लोक कल्याण और जनसेवा पर आधारित होती थी। यह शोषित और प्रताड़ित लोगों की मदद करती थी। राजनीति में मूल्यों और ईमानदारी का पाठ नेताओं को सही रास्ता दिखाता था। वे देश के उज्ज्वल भविष्य की नई तस्वीर गढ़ते थे। सच तो यह है कि वर्षों तक ऐसे नेताओं के संघर्ष और बलिदान की कहानियां आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकाशस्तंभ बनती रहीं। तब करोड़ों लोगों को यह लगता था कि उनका भविष्य बेहतर हाथों में है।

प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम उसी राजनीति की देन थे। राजनीति में अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए राजनीतिज्ञ साम, दाम, दंड, भेद की नीति का सहारा लेते हैं, लेकिन जब लक्ष्य ही बिगड़ जाए, तो यह नीति भी एक दिन काम नहीं जाएगी। इसके अलावा पासा पलटने की नीति भी नेताओं ने अपना ली। इससे देशहित पीछे छूटने लगा। लोक कल्याण की भावना खत्म होने लगी। राजनीति में अपने और परिवार का हित देखा जाने लगा, तो दोहरा चेहरा भी उभरने लगा। परिवारवाद को गाली देने वाले खुद परिवार के पोषक बन गए। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की बात करने वाले 'महाभ्रष्ट' साबित हुए। नतीजा यह कि राजनीति का कुरूप चेहरा सामने आने लगा। कहीं न टिकने वाले नेता पासा पलट नीति का समर्थन करते हैं और इसी के बल पर देश में क्रांति के नारे लगाते हैं।

आज राजनीतिक पटल पर दिन-रात इस तरह के तमाशे होते हैं। संघर्ष कर खड़ी हुई आदर्शवादी पार्टियां टूटती हैं और दल-बदल करने वाले नेता समय की जरूरत बन जाते हैं। सरकार ने राजनीति का चेहरा संवारने के लिए कानून बनाए। नेता अपनी सुविधा की सियासत न करें, जन कल्याण की बात करें, कुर्सी के लिए पार्टियां न बदलें और फिर पार्टियों के बदलने को न्यायसंगत न ठहराएं, इसके लिए दल-बदल विरोधी कानून भी बने। उनमें सख्ती भी लाई गई। इतनी सख्ती कि अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य बदलेंगे, तभी इसे माना जाएगा। मगर इस कानून को भी झांसा देने वाले नेताओं के चेहरे सामने आ गए। दल-बदल विरोधी कानून का अस्तित्व ही नहीं रहा। हाल में आम आदमी पार्टी से जुड़े राज्यसभा के सात सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी छोड़ कर भाजपा में चले गए। उनके इस कदम पर खूब राजनीति हुई। कानून विशेषज्ञ अपनी राय देने लगे। दूसरी ओर खुद दल बदलने वाले दूसरों को गद्दार कहने लगे। मगर यह कड़वी सच्चाई है कि कुछ भी हो जाए, उसे बाद में स्वीकार कर ही लिया जाता है। कुछ समय बाद बदलाव की भूमिका बना दी जाती है।

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दस सांसदों में से सात सांसदों के पार्टी छोड़ने पर सवाल तो उठे, लेकिन राजनीति में मूल्यों की कसौटी धरी रह गई। अलबत्ता, उनके इस कदम के गैर-कानूनी होने पर बहस तो चली, लेकिन वह कानूनी रूप से प्रमाणित सिद्ध हुई और सातों सांसदों को भाजपा में विलय की इजाजत दे दी गई। ये सांसद दल-बदल कानून के दायरे में नहीं पाए गए। एक कसौटी होती है तकनीकी और एक कसौटी होती है नैतिकता की। जो बात तकनीकी कसौटी पर पूरी उतरे, वह जरूरी नहीं है कि नैतिकता की कसौटी पर भी पूरी उतरे। आप के बागी नेताओं के भाजपा में जाने के बाद उनके बयान भी आने लगे, जिनमें वे अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते रहे। यह सही ठहराने की कोशिश भी जैसे राजनीति बन गई है।

> आज की नई राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप प्रमुख हो गया है। बाकी बातें गौण हो रही हैं। यह चिंता की बात है। देश की राजनीति में सैद्धांतिक आधार गुम हो जाते हैं, जातीय आधार प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए जाति जनगणना को युगप्रवर्तक फैसला कहा जाने लगा है। आजादी के बाद से हम पिछड़े नागरिकों को नया जीवन देने की बात करते आए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करते रहे हैं। मगर पिछड़े हुए फिर भी पिछड़े ही रहते हैं। जब अति पिछड़े लोग भी नजर आने लगे, तो इनके तुष्टिकरण की भी राजनीति होने लगी और उसी की पक्षधरता जनसेवा बन गई।

जब भ्रष्ट नेता पकड़ा जाता है, तो वह इसे बदले की राजनीति कहता है और किसी भी अपराध में पकड़ा गया नेता हिरासत में रहने पर जमानत पर छूटता है, तो उसका ऐसे स्वागत होता है जैसे वह किला फतह करके आया हो। राजनीति का यह नया पाठ हमें कहां ले जाएगा? जनता के हित जिस तरह से हाशिये पर जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इस नई राजनीति को केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं। अब वैश्विक स्तर पर हथियार बेचने के लिए वर्षों और महीनों तक युद्ध होते हैं या कराए जाते हैं। चाहे इससे दुनिया भर में अराजकता ही क्यों न फैल जाए। वैश्विक नेताओं की नीतियों में सिवाय उनके अहम के कुछ भी नजर नहीं आता।

आज की नई राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप प्रमुख हो गया है। बाकी बातें गौण हो रही हैं। यह चिंता की बात है। देश की राजनीति में सैद्धांतिक आधार गुम हो जाते हैं, जातीय आधार प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए जाति जनगणना को युगप्रवर्तक फैसला कहा जाने लगता है। आजादी के बाद से हम पिछड़े नागरिकों को नया जीवन देने की बात करते आए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करते रहे हैं। मगर पिछड़े हुए फिर भी पिछड़े ही रहते हैं। जब अति पिछड़े लोग भी नजर आने लगे, तो इनके तुष्टिकरण की भी राजनीति होने लगी और उसी की पक्षधरता जनसेवा बन गई। राज्यों में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सैद्धांतिक कसौटी का भी तो कोई ख्याल रखना चाहिए। परिस्थितियों के बदल जाने का लाभ उठाने की कोशिश ने विचारधारा को गायब कर दिया है। दलबदलू नेताओं के लिए अब दल-बदल कानून कोई बाधा नहीं रही। ऐसी हालत में सात सांसदों का अपनी पार्टी का दामन छोड़ कर चले जाना और उनको दूसरे दल में स्वीकृति मिल जाना, एक गंभीर संकेत है। कल को किसी राज्य में अगर सत्तारूढ़ दल का स्पष्ट बहुमत है और वहां भी दो-तिहाई नेता उसका दामन छोड़ कर चले जाते हैं, तो काम करती अच्छी भली सरकार के गिरने का अंदेशा पैदा हो सकता है।

अब ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से नैतिकता और आदर्श गायब हो चुके हैं। उनके स्थान पर स्वार्थपरकता और हित हावी होने लगे हैं। दल-बदल की ऐसी घटनाएं एक पार्टी या एक राज्य तक सीमित नहीं है। ज्यादातर पार्टियों को अपने आधार हिलते नजर आते हैं। मजबूत संगठन वाली पार्टियां भी दूसरे दलों से आए लोगों का स्वागत करने लगी हैं, बिना परवाह किए कि उनके पास वह प्रशिक्षण है भी या नहीं जो वे अपने कार्यकर्ताओं को देती हैं। हर नेता जनकल्याण के नाम पर अपने गुट का कल्याण करता हुआ नजर आता है। अब युवा पीढ़ी क्या इस तरह की राजनीति करेगी?

देश की आर्थिक गति उत्थान पर है। विकास दर की गति तेजी से बढ़ रही है। मगर दूसरी ओर बड़ी आबादी सस्ते और मुफ्त अनाज पर पल रही है। वहीं अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की बात कोई नहीं करता। ऐसे माहौल में साम, दाम, दंड और भेद का नीतिविहीन चेहरा स्थापित होता नजर आता है। इस विसंगति से कैसे बचा जाए, इस पर सोचना होगा?

# घर का परिवेश

**मोनिका भाम्भू कलाना**

दुनिया मेरे आगे

घर हम सबके लिए एक 'व्यवस्था' का नाम है। किसी भी व्यक्ति के लिए घर केवल भावनात्मक जुड़ाव से महत्त्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और निर्धारित व्यवस्था की वजह से खास बनता है। घर सबके लिए एक ऐसी जगह है, जहां हम अपनी जैविक घड़ी को व्यवधान दिए बिना चला सकते हैं, हमें जरूरतों की फिक्र कम रहती है, रूठना हमारा अधिकार है और मांगी हुई चीज अधिकतर मिल जाती है। इस तरह घर केवल भावना का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी आकांक्षीय स्थिति का प्रतीक है, जहां अपनी मर्जी से चीजों को चलाया जा सकता है।

'घर' शब्द हमारे लिए ऐसी यादों से जुड़ा है, जिसमें अपनों का साथ और प्रेम मिला होता है। जहां हमारे आराम के लिए जगह होती है। भले ही हम कितने ही मकान बदल लें, घर बदल लें, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए घर का अर्थ ऐसा परिवेश है, जिसमें उनका बचपन गुजरा होता है, जिसमें वे बड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसी समय में हम अनुभवों को प्रथमतया और तीव्रता से महसूस करना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में जो परिवेश और व्यवस्था हमारे साथ चलती है, वह घर है। इसलिए घर बचपन की सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक होती है।

घर एक ऐसी जगह है, जहां इंसान तैयार किए जाते हैं। परवरिश के साथ अपनी आदतों और प्रवृत्तियों को मनुष्य यहीं से ग्रहण करता है। घर केवल सुविधाओं के लिए नहीं होता, बल्कि यह सीखने के लिए और बहुत कुछ अर्जित करने के लिए भी होता है। यह केवल हमारे सुविधाजनक घेरे तक सीमित नहीं होता, यह मन माफिक माहौल न मिलने पर अनुकूलन के लिए तैयार भी करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि घर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बच्चों के लिए घर के जो मायने हैं, वही माता-पिता के लिए नहीं रहते। घर नाम की जिस व्यवस्था के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, वह घर बच्चों वाले अर्थ का 'घर' है। मां-पिता के लिए तो यह घर जिम्मेदारी बन जाता है। इस व्यवस्था को चलाने में जो लोग अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उनके लिए 'घर' का मतलब बेफिक्री नहीं होकर हाड़तोड़ मेहनत है। वे बच्चों के लिए घर को घर बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत और चिंतित रहते हैं।

इन सबमें घर नाम की व्यवस्था प्रत्येक सदस्य के साथ कैसे अलग-अलग व्यवहार करती है, इस पर गौर करना जरूरी है। घर एक लड़की और लड़के के लिए भी बराबर नहीं होता। यह बड़े और छोटे के लिए एक जैसा नहीं होता। तमाम तरह के भेदभावों और पूर्वाग्रहों को हम अपने घरों से ही ग्रहण करते हैं। हम यहां से अघोषित शोषण की एक ऐसी परंपरा के अंग हो जाते हैं, जिसमें अधिकतर पुरुष मुखिया होते हैं। उनकी मर्जी सबकी मर्जी होती है और महिलाओं को काम करते रहने और मुंह बंद रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हमें घर की एक सामाजिक व्यवस्था की तरह छानबीन करनी चाहिए। घर का महिमामंडन जितना होता है, उसमें स्मृति अधिक तर्क कम होता है। जो मां घर को घर बनाती है, उनके उस घर में दूसरी महिलाओं को नियंत्रित करने के अलावा क्या अधिकार होते हैं? दूसरी महिलाओं को नियंत्रित करते हुए कोई भी महिला किसका प्रतिनिधित्व कर रही होती है? स्मृतियों के बड़े घर में महिलाओं की समान अधिकारों वाले व्यक्ति के रूप में कोई जगह नहीं होती। वे अक्सर परंपरा निभाने वाले प्रवाह का अंग भर होकर रह जाती है। हमारे आदर्श और सपनों के घर में किसके लिए कितनी जगह है. इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? एक के विरोध में या किसी की जगह दूसरे को खड़ा करने से घर नहीं बनते। घर अलग-अलग लोगों के एक साथ होने से बनता है।

> आवासीय सुरक्षा के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बहसों में घर सदैव से केंद्र में रहा है, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। शहरी दुनिया के वैश्विक रुझान दिखाते हैं कि 'घर' अब केवल निवास स्थान भर नहीं रह गया है, बल्कि उसका एक रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है।

अनिश्चितता से भरी आज की दुनिया में 'घर' की अवधारणा एक गहन परिवर्तन से गुजर रही है। 'घर', जो सदैव से भौतिक आश्रय और सुरक्षा रहा था, आज की पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत से लोगों के लिए स्थायित्व का प्रतीक भी बन गया है। एक ऐसी जगह, जहां कभी भी लौटा जा सकता है। ऐसा स्थान, जो हमारे साथ खड़ा होने को प्रस्तुत रहता है। आवासीय सुरक्षा के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बहसों में घर सदैव से केंद्र में रहा है, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। शहरी दुनिया के वैश्विक रुझान दिखाते हैं कि 'घर' अब केवल निवास स्थान भर नहीं रह गया है, बल्कि उसका एक रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। समाज जैसे-जैसे शहरीकरण, डिजिटलीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, 'घर' का अर्थ विस्तारित हो रहा है। यह परिवार के लिए एक नींव है, जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा है और एक ऐसा प्रतीक है, जहां हम खुद को अरक्षित महसूस करने से बच जाते हैं।

घर को हमारे लिए विशेष बनाने में उसमें निहित सुविधाओं और भौतिक संसाधनों की भी बड़ी भूमिका होती है। संबंधों के बदलते आधार के मद्देनजर हमें घर नाम की व्यवस्था के बारे में विस्तृत चिंतन करना चाहिए। यह सही है कि हमें घर की अवधारणा को विस्तृत करने की जरूरत है। साथ ही उसमें निजी के लिए भी जगह बनानी होगी। आज निजता को मान्यता दिए बगैर कोई सामूहिकता संभव नहीं हो सकती। घर अब रूढ़ियों से नहीं सम्मान, स्वीकार्यता और बराबरी की अवधारणा से ही टिक सकते हैं वरना वे आधुनिकता की आंधी को झेल नहीं पाएंगे। कुंठारहित संबंधों और घरों के लिए दूसरे के व्यक्तित्व की स्वीकार्यता प्राथमिक शर्त है।

'घर' को भावना और स्मृति से अलग करके एक व्यवस्था की तरह सोचे जाने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था, जिसमें जितनी विशेषताएं हैं, उतनी ही कमियां भी हैं। हमें उन कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी घर उसमें रहने वाले सभी सदस्यों के लिए 'घर' बन सकेगा।

## कथनी और करनी

भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में कई दृश्य ऐसे हैं जो केवल घटनाएं नहीं, बल्कि लोकतंत्र की दिशा, विपक्ष की क्षमता और सत्ता की लोलुप प्रवृत्ति के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल का हालिया राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा ही हमारे सामने है। हर लंबे शासन में थकान, विवाद और असंतोष पैदा हो ही जाते हैं। मगर आज सवाल यह नहीं है कि कमियां थीं या नहीं? सवाल यह है कि पिछले पंद्रह वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सत्ता को सीधी और प्रभावी चुनौती देने का साहस किसने दिखाया? ममता बनर्जी ने न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी एक ऐसी लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें संसाधनों का असंतुलन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक तरफ केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी, प्रशासनिक तंत्र, एजंसियां और रणनीति, तो दूसरी ओर एक क्षेत्रीय नेता सीमित संसाधनों के साथ मैदान में अकेले डटी रही। विचित्र है कि सत्ता में बैठे लोग 'स्त्री शक्ति' का उद्घोष करते हैं, संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के विधेयक को गिराने के लिए विपक्ष को कोसते हैं। वहीं जीत के बाद एक स्त्री नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में उनकी कथनी और करनी के बीच फर्क दिखता है।

*– उमेश व्यास, इंदौर*

## असुविधा के आयोजन

देश में वीआइपी संस्कृति आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं के आगमन के समय आम जनता को यातायात बाधित होने, घंटों जाम में फंसने और दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर पटना में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इससे आम नागरिकों को भारी असुविधा हुई। कई मार्गों को घंटों पहले बंद कर दिया गया तथा अनेक रास्तों को बदल दिया गया। हवाई अड्डे से गांधी मैदान तक पूरे मार्ग को होर्डिंग, बैनर, गुब्बारों और तोरण द्वारों से सजाया गया। इस आयोजन में बड़े पैमाने पर सरकारी संसाधनों और धन का बेजा इस्तेमाल हुआ। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में शपथ ग्रहण समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च करना कितना उचित है।

*– हिमांशु शेखर, गयाजी*

## जवाबदेही की जरूरत

'लापरवाही का दायरा' (संपादकीय, 7 मई) पढ़ा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में खुले नाले और पानी से भरे हुए गड्ढे सभी के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। इनके कारण जब कोई हादसा हो जाता है, तब स्थानीय प्रशासन जागता है। अधिकारियों का समय रहते सचेत न होना दुखद ही है। बच्चों से लेकर बड़े तक इन नालों में गिर जाते हैं। मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई के नाम पर छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरती है। बड़े अधिकारी साफ बच निकलते हैं। धीरे-धीरे मामले को फाइलों में दबा दिया जाता है। ठेकेदारों और कर्मियों पर ठीकरा फोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। सवाल है कि निर्माण कार्यों के समय बिना निगरानी के और काम पूरा कराए बिना भुगतान कैसे हो जाता है। ऐसे में बड़े अधिकारी भी स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार हैं। जवाबदेही तो उनकी भी तय होनी चाहिए। बरसात के दिनों में तो इस तरह की लापरवाही आम बात है।

*– एमएम राजावत राज, शाजापुर*

## घटती सहिष्णुता

दिल्ली में पिछले दिनों मामूली कहासुनी में एक युवक की जान ले ली गई। यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि तेजी से बिगड़ती शहरी मानसिकता का संकेत है। जरा-सी कहासुनी हिंसा में बदल जा रही है। यह सहनशीलता की कमी से उपजा संकट है। आज हर व्यक्ति 'मैं सही, बाकी सब गलत' की मानसिकता में जी रहा है। पहले जहां लोग झगड़े के दौरान बीच-बचाव करते थे, अब किनारा कर लेते हैं। समाज की यह चुप्पी भी हिंसा को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फ्लैट संस्कृति में एक ही परिवार के पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। स्थिति यह है कि लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हैं। आज पूरी दिल्ली अवैध पार्किंग के जाल में उलझ चुकी है और यह जाल अब झगड़े और हत्याओं तक फैल चुका है।

*– चंद्रप्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली*

जयप्रकाश नारायण ने पांच जून 1974 को गांधी मैदान की एक विशाल जनसभा में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जेपी ने कहा, 'संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है'। संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों में चुनाव सुधार भी अहम था। साथ ही भ्रष्टाचार समाप्त करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता की भागीदारी बढ़ाना और सत्ता का विकेंद्रीकरण आंदोलन का उद्देश्य था। इसके उद्देश्यों में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण भी था। जेपी किसी भी तरह की हिंसक क्रांति के पक्ष में नहीं थे।

जेपी...जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने सत्तर के दशक में देश की राजनीति का चरित्र बदल दिया था। कांग्रेस के एकल प्रभुत्व को नकार कर क्षेत्रीय क्षत्रपों का उदय हुआ। बिहार से 'संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस' ट्रेन चलती है, जो दिल्ली पहुंचती है। पर अब इस 'संपूर्ण क्रांति' का इंजन बदल गया है। इस इंजन के बदलने के पीछे भी एक जेपी (नड्डा) का ही एलान है। 2014 के बाद राज्यों के चुनाव में भाजपा की लगातार जीत के मद्देनजर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि बहुत जल्द क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सत्तर के दशक की 'संपूर्ण क्रांति' के जरिए जनता ने कांग्रेस के अखिल भारतीय राजनीतिक प्रभुत्व को नकारा तो इक्कीसवीं सदी की 'संपूर्ण क्रांति' के बाद भाजपा के अखिल भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार रहे हैं। क्षेत्रीय क्षत्रप जहां बचे हैं वे भी 'संपूर्ण क्रांति' के इंजन के डिब्बे में ही जुड़े हुए हैं, या जुड़ने के इच्छुक हैं। अब इंजन की मर्जी है कि वह कब तक इन डिब्बों को अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। जेपी से जेपी तक की राजनीति के जरिए क्षेत्रीय क्षत्रपों के क्षय पर बेबाक बोल।

**बेबाक बोल**

# क्षयत्रप

**मुकेश भारद्वाज**

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगुआ रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजाद देश में सत्ता की स्वतः दावेदार हुई। आजाद भारत के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा भी किया। सत्ता के स्वाभाविक चरित्र की तरह कांग्रेस अहंकारी हुई और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर अपना अधिकार माना। देश के जर्रे-जर्रे का राजनीतिक फैसला दिल्ली से जारी होने लगा। इस विशालकाय देश के बहुत बड़े हिस्से को लगने लगा था कि उनके लिए दिल्ली दूर है। उनके अधिकारों के फैसले इतनी दूर से नहीं लिए जा सकते हैं।

कांग्रेस की राजनीतिक निरंकुशता के आरोप के बीच आया 1970 का दौर। उसी वक्त उदय होता है जयप्रकाश नारायण का। आपातकाल और केंद्र सरकार के निरंकुश रवैए के खिलाफ एक विचारधारा का निर्माण हुआ। जयप्रकाश नारायण मजबूत और तानाशाही केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने के लिए कई छोटे, विपक्षी और क्षेत्रीय विचारधारा वाले गुटों (भारतीय लोकदल, कांग्रेस (ओ), जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी) को साथ लेकर आए। कांग्रेस की विशालकाय राजनीतिक शक्ति के सामने छोटे दलों ने एक साथ मिलकर मुट्ठी तानी। अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग जनता पार्टी के छाते के नीचे एकजुट हुए।

कभी दलविहीन लोकतंत्र की वकालत करने वाले जयप्रकाश नारायण की विचारधारा ने क्षेत्रीय दलों की पौधशाला खोली। इस पौधशाला में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव जैसी कोपलें फूटीं जिन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में वटवृक्ष सरीखा विस्तार पाया। अब दिल्ली की सरकार को हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई नेता चुनौती दे सकता था। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और दिल्ली की शक्ति को क्षेत्रीय अस्मिताओं ने प्रभावित करना शुरू कर दिया।

सत्तर के बाद भारतीय राजनीति में ऐसा ही मोड़ 2014 में आया। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और भारत को एक और जेपी मिला। ये थे जगत प्रकाश...जेपी नड्डा।

केंद्र के बाद भाजपा का विधानसभा चुनावों के जीतने का दौर शुरू हुआ। भाजपा की लहर में डूबने से बचने के लिए जब क्षेत्रीय दल भाजपा से ही समझौता कर रहे थे, तब नए जेपी ने कहा कि भारत में बहुत जल्द क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। यह बयान बहुत साधारण तरीके से देकर उस पर चुप्पी साध ली गई थी। लेकिन इस पर अति आक्रामक तरीके से काम शुरू कर दिया गया था। इस बार छाता था हिंदुत्व का। क्षेत्रीय विविधता की काट खोजने के लिए बनी प्रयोगशाला ने हिंदुत्व का उत्पाद निकाला। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का मुहावरा पुराना हुआ और हिंदुत्व की राजनीति का नया भूगोल गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक है। गंगा के उद्गम से समुद्र में उसके मिलन तक की पट्टी पर क्षेत्रीय क्षत्रपों का क्षय हो चुका है। जो बचे हैं उनका सहारा भी नए जेपी वाली पार्टी ही है। अब उसकी मर्जी कि वह अपने हिंदुत्व की राजनीति में कितना क्षेत्रीय रहने देगी।

जम्मू कश्मीर में पीडीपी, पंजाब में शिरोमणी अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में जद (एकी), उत्तर प्रदेश में बसपा, हरियाणा में जजपा, आंध्र में वाईएसआर, उत्तर प्रदेश में रालोद, कर्नाटक में जनता दल (सेकु) इन सबों को लगा था कि हिंदुत्व के छाते की छांव पा लेने के बाद उनका क्षेत्र बचा रह सकता है। लेकिन नए जेपी की पार्टी का हिंदुत्व राजनीति का ऐसा 'सुपर फूड' है कि उसके बाद राजनीतिक विचारधारा के शरीर को किसी अन्य खुराक की जरूरत ही महसूस नहीं होती है।

दो पारी के चुनावों ने कलिंग, अंग और बंग के क्षेत्रीय क्षत्रपों को धराशायी कर दिया है। कभी बसपा अध्यक्ष मायावती को देश की भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। मुलायम सिंह यादव की भी ऐसी ही छवि बनाई गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को विपक्ष का राष्ट्रीय चेहरा बनाने की कवायद शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने बहुत हद तक हिंदुत्व की राजनीति को रोका था। लेकिन अपना क्षेत्रीय अस्तित्व बचाने के लिए वे हिंदुत्व की राजनीति के साथ आए और विलीन हो गए। ममता बनर्जी ने बहुत मजबूती से अपनी पहचान बनाई थी और गाहे-बगाहे उन्हें भी देश के प्रधानमंत्री के लिए योग्य चेहरों में माना जाता रहा। नवीन पटनायक ने अपने हिस्से का राजनीतिक इतिहास लिखा। लोजपा के रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था तो आज उनके पुत्र ने अस्तित्व बचाने के लिए 'विज्ञान' को छोड़ 'हनुमान' बनना चुना। शरद पवार, नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा की शपथ लेने के लिए मजबूर हुए। याद करें चौधरी चरणजीत सिंह का जलवा जो केंद्रीकरण, नौकरशाही और बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में आने का आरोप लगा नेहरूवादी ढांचे के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने मध्यवर्ती कृषक जातियों को जो राजनीतिक शक्ति दी थी, उसी विरासत के तहत भाजपा सरकार को अपने कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन आज उनके पोते जयंत चौधरी राजग सरकार के सहयोगी हैं। अब मध्यवर्ती किसान के पास भी हिंदुत्व की पहचान है। हरियाणा के 'लाल' भगवा के आगे विलुप्तप्राय राजनीतिक प्रजाति के दायरे में हैं।

भारत के वृहत्तर भूगोल ने ही क्षेत्रीय राजनीति की जरूरत को पैदा किया था। पहाड़ की आबादी और मैदान की आबादी दोनों की जरूरतें अलग होंगी। आदिवासी इलाके चाहते थे कि मुख्यधारा के अतिक्रमण से उनकी रक्षा हो। इन्हीं आकांक्षाओं ने कई नई राज्य बनाए। झारखंड में शिबू सोरेन जैसे नेता ने दिल्ली तक अपनी दखल बनाई। लेकिन पहाड़, समुद्र से लेकर जंगल तक को हिंदुत्व की पहचान के दायरे में लाया गया। हेमंत सोरेन ने पिछली बार भले ही आदिवासी अस्मिता के आधार पर अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन अब हिंदुत्व की पहचान के आगे उनका टिका रहना भी मुश्किल ही दिख रहा है। भाषाई और क्षेत्रीय पहचान की अतिवाद वाली द्रमुक सत्ता से दूर जा चुकी है। वहां एक ऐसे नेता का उदय हुआ है, जिसने चुनाव में समावेशी रुख रखा।

क्षेत्रों ने जिस दिल्ली को कभी दूर कह कर खारिज किया था, आज उन्हें ही दिल्ली में समा लिया गया है। दिल्ली के मुख्यालय से क्षेत्रीय पहचान खान-पान और परिधान तक सीमित हो गई है। जब बात बिहार की थी तो लिट्टी-चोखा और गमछा को ही उसका पर्याय मान लिया गया। बंगाल का समय आते ही भाजपा मुख्यालय में झाल-मूड़ी की दुकान सज गई, मछली राष्ट्रीय भोजन सरीखी हो गई। हिंदुत्व की राजनीति ने दिल्ली में ऐसा 'बड़ा बाजार' खोल दिया है, जहां एक छत के नीचे रसम से लेकर पायसम तक है।

कभी एक जेपी के जरिए भारत के क्षेत्रों ने कांग्रेस के एकल प्रभुत्व को नकारा तो आज दूसरे जेपी ने दिल्ली की सत्ता को वह इंजन बना दिया, जिसके पीछे सभी क्षेत्रीय दलों के डब्बे एक-एक कर जुड़ने लगे। अस्तित्व बचाने के क्षेत्रीय दलों के भय और समझौतों ने उनका और क्षय कर दिया है। फिलहाल क्षेत्रीय दलों के खिलाफ भाजपा के जेपी की 'संपूर्ण क्रांति' सफल हुई है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के क्षय के साथ एक देश, एक पार्टी का रुझान बढ़ता ही नजर आ रहा है। भविष्य में मौजूदा सत्ता के सामने जो भी शक्ति खड़ी होगी निश्चय ही उसका चरित्र राष्ट्रीय होगा।

## डर का असर!

पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने आई-पैक से अपना अनुबंध खत्म करने का एलान कर दिया। आई-पैक के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। यह कंपनी चुनावी रणनीति बनाने और प्रबंधन का काम करती है। पीके के नाम से प्रसिद्ध प्रशांत किशोर ने पहली बार 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम किया था। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का शिल्पकार भी उन्हें ही माना गया। उसके बाद तो उन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों ने काम दिया। दो साल पहले पीके ने अपनी पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आई-पैक से नाता तोड़ लिया। अब विनेश चंदेल, प्रतीक जैन और ऋषिराज सिंह आदि हैं आई-पैक के स्वामी।

बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने आई-पैक के दफ्तर पर छापेमारी की तो ममता बनर्जी ईडी की टीम से उलझ गई थीं। इस कारण विवाद भी बढ़ा था। आई-पैक के विनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। अखिलेश को लगा कि अगर 2027 में आई-पैक उनका चुनाव प्रबंधन करेगी और ईडी ने उसे तंग किया तो चुनाव प्रबंधन पर खराब असर पड़ सकता है। करार तोड़ने का कारण अखिलेश ने पार्टी के पास पैसे की तंगी होना बताया है, पर जानकार कह रहे हैं कि ईडी के डर से उन्होंने यह कदम उठाया है।

## गुम नाम

सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो हर किसी को यह देखकर हैरानी हुई कि उसमें मंगल पांडेय का नाम नहीं था। जबकि वे न केवल बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं बल्कि बिहार की भाजपा गठबंधन वाली हर सरकार में मंत्री रहे हैं। भाजपा कोटे से मंत्री बनने वाले संभावित नेताओं में उनका नाम पक्का माना जा रहा था। पार्टी आलाकमान के भरोसेमंद भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी वही थे जहां पार्टी ने नया इतिहास रचा है। हो सकता है कि जीत का ज्यादा श्रेय सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव को मिले पर सूबे के प्रभारी तो पांडेय ही थे। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को मंत्रिपद दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि मंगल पांडेय को नितिन नवीन की टीम में महासचिव या उपाध्यक्ष जैसा पद देकर संगठन में उनका उपयोग करेगी पार्टी।

**राजपाट**

## चर्चा में आ गई रायशुमारी

पांच राज्यों के चुनाव के बाद राजनीतिक दल सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ऐसी प्रक्रिया एक बड़े दल की ओर से केरलम में भी शुरू की गई है। लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए पार्टी ने इसके लिए रायशुमारी की। रायशुमारी का नतीजा आलाकमान तक आता, इससे पहले ही रूझान मीडिया के बीच पहुंच गए। आलाकमान के लिए तो यह असहज करने वाली स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि इस काम का जिम्मा दो बड़े नेताओं के पास था। अब सवाल यह है कि रायशुमारी की जानकारी जानबूझकर लीक हुई या फिर गलती थी। हालांकि, एक नेता जी ने पहले ही सार्वजनिक हुए आंकड़े को फर्जी करार दिया है। फिर भी रायशुमारी तो चर्चा में आ ही गई।

## मंत्री चुनाव हारे

केंद्रीय मंत्री का कद और पद छोटा नहीं होता पर भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारती रही है। वे हार भी जाते हैं। इस बार भी भाजपा ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया। दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। अपने नहीं, दूसरे राज्यों से। एल मुरुगन को तमिलनाडु से और जार्ज कुरियन को केरलम से विधानसभा चुनाव लड़ाया। दोनों अपनी सीटों से चुनाव हार गए। तमिलनाडु में पिछली बार भाजपा 20 सीटों पर लड़ी थी और चार सीटें जीत ली थी। इस बार उसने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सीट एक ही आ पाई उसके खाते में। केरलम में उल्टा हुआ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार उसने तीन सीटें जीत लीं। तमिलनाडु में तो पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भी इस बार विधानसभा चुनाव हार गईं। याद दिलाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बंपर सफलता मिली थी, पर उसके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। रही भाजपा की बात तो उसके अपने तर्क हैं। उसका कहना है कि कभी उसे उत्तर भारत के कुछ राज्यों की पार्टी माना जाता था पर आज उसका प्रभाव उत्तर से दक्षिण तक सारे भारत में है। चुनाव की हार से डरने लगते तो पार्टी का इतना प्रभाव हो ही नहीं पाता।

## सिद्धरमैया को राहत

असम में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार पहले से भी ज्यादा खराब रहा। इसका पार्टी को भले नुकसान हुआ हो पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर मंडराता खतरा फिलहाल टल गया है। वजह है, उनके प्रतिद्वंद्वी और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का असम का प्रभारी होना। शिवकुमार को भी माना जाएगा असम के खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेह। असम में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो शिवकुमार आलाकमान पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव बनाते। डीके खेमे का कहना है कि कर्नाटक में जब सरकार बनी थी तो आलाकमान ने सिद्धरमैया और डीके के बीच ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहने का अघोषित फामूर्ला माना था। सिद्धरमैया ने एक और मोर्चे पर भी इम्तिहान पास किया है। राज्य की जिन दो सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था दोनों कांग्रेस ने जीती हैं। हालांकि ये दोनों सीटें कांग्रेस की ही थीं। पर एक भी सीट पार्टी के कब्जे से निकल जाती तो हार का ठीकरा सिद्धरमैया के सिर ही फूट जाता और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी।

*संकलन : मृणाल वल्लरी*

## रेत का टीला

कहानी इतनी पुरानी भी नहीं कि याद ही न हो। रामलीला मैदान से उस भागती एंबुलेंस के पीछे खबरनवीसी का अजीब-ओ-गरीब अंदाज किसे याद नहीं! उखड़ते तंबू, बंद कैमरों, सिमटते दरी-गद्दों के बीच हम उन चेहरों को तलाश रहे थे जिनके बारूदी जज्बातों के गोले माहौल को आतिशी बना रहे थे। बहरहाल भीड़ का हर-एक चेहरा उसी ताजगी के साथ आज भी याद है। लोकपाल के सैलाब से निकला एक चेहरा जज्बाती लिबास में चुपके से सियासत के रास्ते चल पड़ा। सियासत की ऊंची मुंडेर से ऐलान होते जम्हूरियत के पैगाम रिश्तों की नई इबारत लिखते रहे। इस जादुई ऐलान के तिलिस्म में लोग आते गए और कारवां बनता गया। सियासत को करवट बदलते देख हैरान दुनिया को क्या पता था कि रेत की ढेर पर खड़ा वह किला एक तूफान में दरक जाएगा। दरकी हुई दीवार से आती रिश्तों में छिपे जख्मों की टीस है 'रिसता (रा) घाव'। 'खांटी ईमानदार' के नाम से लिखी गई किताब का हर पन्ना लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। हैरानी की इंतहा तब हो गई जब ना पैमाना छलका ना ही घुंघरू टूटे। मगर शराब ऐसी छलकी की कई रिश्ते टूट गए। भला हो दुनिया की सबसे बड़ी धुलाई मशीन का जिसने गहरे दागों को झक्क सफेदी दी है। सियासत में बिखराव के घाव के दर्द का अहसास गहरा होता है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

## गलती किसकी?

हाल ही में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी बदल कर सत्ताधारी दल भाजपा का दामन ऐसे थामा कि दलबदल कानून भी इन्हें रोक नहीं पाया। इन सभी सांसदों पर बेहिसाब संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ खोजबीन चल रही थी। नतीजतन वही हुआ। अब ये धुलाई मशीन में धुल कर एक बेहतर नेता के रूप में माने जाने लगे। खैर, जांच एजंसियां अपने औपचारिक कार्य करती रहेंगी, जिसकी रिपोर्ट देखने लायक होगी। क्या यहां पर आम आदमी पार्टी की गलती है जो अपने नाम और सिद्धांतों से हट कर ऐसे रसूखदार उम्मीदवारों को राज्यसभा में पीछे के दरवाजे से लाई थी। या ऐसे नेताओं की गलती जो अपनी मूल पार्टी के सिद्धांतों को गलत बता कर उसके ही पद पर दूसरे खेमे में चले जाते हैं? या फिर देश की भोली-भाली जनता के विश्वास की? पंजाब की राजनीति में भाजपा की सबसे बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा।

-दिनेश शाह, सिंगरौली (मप्र)।

**आपके पत्र**

## भविष्य की चिंता

एक-दो-तीन, और सात वाले अपने तर्क को अकाट्य मानते हुए राघव चड्ढा ने खुद को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास तो किया, लेकिन संख्या अधिक होने से कोई बात सही नहीं हो जाती। मुझे 1957-58 का सत्र याद है जब आठवीं की परीक्षा पहली बार पंजाब शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई थी। शिमला का जाना-माना सरकारी स्कूल, और उस वर्ष आठवीं कक्षा के प्रथम योद्धाओं की हमारी पूरी पलटन का तीसरा दर्जा आया, यानी सारे के सारे नालायक घोषित हुए थे। आज अपने ही खिलाफ खड़े एक व्यक्ति को ऐसा बहुत कुछ सामान्य लगने लगा, जो इससे पहले नहीं लगा था। अचानक सभी को गांधी भी याद आ गए, सबके महानायक रह चुके केजरीवाल को भी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नोटों पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर होने का सुझाव दिया था। गांधी को तब भी खारिज कर दिया गया था। गद्दार या कुछ भी कहकर कितनी भी भड़ास निकालते रहें, सच्चाई यह है कि पंजाब के भविष्य को लेकर, खासकर बंगाल के घटनाक्रम के बाद राज्य के ज्यादातर वासियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं।

-शोभना विज, पटियाला, पंजाब।

## सत्ता की विचारधारा

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों की सर्वाधिक चर्चा जिन कारणों से हो रही है, उनमें से एक विचारधारा भी है। इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की विशेष चर्चा इसी विचारधारा के प्रतिस्थापित होने के कारण है तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि केरलम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की हार एक खास विचारधारा का अंत है। तमिलनाडु में एक नवोदित पार्टी की जीत की तुलना दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी के सत्तारूढ़ होने से की जा रही है। इससे पहले 'आप' के सात सांसदों ने पाला बदल लिया। पाला बदलने वालों ने इसे उचित करार दिया। 'आप' प्रमुख केजरीवाल राजघाट की शरण में चले गए। तब शायद उन्हें सिद्धांतों व विचारधारा की राजनीति की याद आई होगी वरना आम दिनों में उन्हें राज्यसभा सांसद सीटों के लिए पैसे की गठरी ही दिखाई दी। सभी राजनीतिक दल, नए और स्थापित का एक कतार में आना तय है क्योंकि राजनीतिक दलों की एक ही विचारधारा है, हर हाल में सत्ता।

-मुकेश कुमार मनन, पटना।

## निवेश का गणित

कांग्रेस की परिवारवादी एवं भ्रष्टाचारयुक्त राजनीति और भाजपा की धार्मिक उन्माद की राजनीति से त्रस्त लोगों को केजरीवाल ने 'नई तरह की राजनीति' का विकल्प दिया था। सत्ता में आने पर जनता ने 'आप' की राजनीति को इनके ही आंदोलन वाले मापदंडों पर परखा और खोट मिलने पर ये जनता की नजर से उतरने लगे। 'आप' अपने पतन के लिए विरोधियों को जिम्मेदार ठहराने लगी। पार्टी आम आदमी को भुलाकर सत्ता के वैभव और उसे कायम रखने में जुट गई और केजरीवाल का व्यक्तित्व, उनकी महत्त्वाकांक्षा और विचारधारा सर्वोपरि हो गई। पंजाब में कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया गया। चाटुकारिता 'आप' की संस्कृति बन गई। ऐसे में राघव चड्ढा ने सोचा होगा कि जब आलाकमान की चाटुकारिता की ही राजनीति करनी है, तो क्यों न यह भाजपा जैसे बड़े और सत्तारूढ़ दल में की जाए। पैसे के दम पर राज्यसभा सदस्य बने सांसदों को अपने निवेश पर वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा था, उल्टे उन पर ईडी की तलवार भी लटक गई। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था ने 'आप' के क्रिकेटर सांसद से दूरी बना ली थी। ऐसे नुकसान देख दलबदल हो गया। इसका तात्कालिक फायदा व्यवसायी सांसदों की ईडी से मुक्ति और क्रिकेटर सांसद को तुरंत पंजाब क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआइ का सदस्य बनने से मिला। सात सांसद मुट्ठी में होने से राघव जी अचानक से बहुत बड़े नेता बन गए।

-बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

**विशेष पन्ना कैसा लगा**

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

अमर उजाला

# प्रवाह

78

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ शनिवार, 9 मई 2026

मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का ज्ञान होना, शरीर में दूसरी आत्मा होने के समान है। -शारलेमेन

# बंगाल में नई शुरुआत

शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना महज एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि राज्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक यात्रा तकरीबन शून्य से शुरू की थी। लेकिन, पिछले एक दशक में उसने अपने संगठन और जनाधार का जिस तरह से विस्तार किया, वह भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में गिना जाएगा। बंगाल में इस उभार के केंद्र में अगर किसी एक नेता का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, तो वह शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। यह शुभेंदु ही हैं, जो 34 वर्षों के वामपंथी शासन के बाद 2011 में सत्ता में आईं ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती देकर और नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक सीधी लड़ाई में उन्हें परास्त कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों का सबसे अहम चेहरा बनकर उभरे। हालांकि, उनके लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि जो सड़क जीत लेता है, वह चुनाव जीत लेता है। पिछले करीब पांच वर्षों से शुभेंदु पूरी आक्रामकता के साथ बंगाल की सड़कों से लेकर विधानसभा तक दिखे हैं, शायद यही वजह है कि जनता ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। दूसरी ओर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला असुरक्षा जैसे मुद्दों पर ममता सरकार की नाकामियों ने भी उनके लिए जगह तैयार की। लिहाजा, आज जब वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो औपचारिक रूप से उस परिवर्तन का चेहरा भी बनेंगे, जिसका वादा भाजपा वर्षों से करती आ रही है। बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा और दलगत टकराव के लिए बदनाम रहा है। ऐसे में, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि नई सरकार प्रतिशोध की राजनीति में न उलझे, क्योंकि ऐसा होने पर परिवर्तन का विचार ही कमजोर होगा। कभी देश का औद्योगिक केंद्र रहा यह राज्य अब निवेश आकर्षित करने में दूसरे राज्यों से काफी पीछे छूट चुका है। जाहिर है कि नई सरकार के सामने ठोस आर्थिक सुधारों की राह पर बढ़ने की भी चुनौती होगी। इसमें

विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। चुनावी हार-जीत स्थायी नहीं होती। ममता बनर्जी बड़ी नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी को लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर ही विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। बंगाल ने हमेशा देश की राजनीति को दिशा दी है। अब देखना यह होगा कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यह राज्य परिवर्तन का कौन-सा नया मॉडल प्रस्तुत करता है।

# ऐतिहासिक संयोग और भाषाओं का समाजशास्त्र

**ट्रंप व ब्रिटिश नरेश चार्ल्स की हालिया टिप्पणियों ने दुनिया को याद दिलाने की कोशिश की है कि किसी समाज या देश की भाषा उसके सांस्कृतिक चुनाव से ज्यादा राजनीतिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। भारत में अंग्रेजी के प्रति मोह और भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा को समझने के लिए इतिहास की इन्हीं परतों को पढ़ना जरूरी है।**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश नरेश चार्ल्स के बीच हाल ही में हुई एक चुटीली चर्चा ने संघर्षों से भरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चार्ल्स ने अपनी बात तो मजाक में कही, पर उसे ट्रंप के बड़बोलेपन का जवाब माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में चार्ल्स ने ट्रंप से कहा था कि अगर ब्रिटेन नहीं होता, तो अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। चार्ल्स ने एक तरह से ट्रंप के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता, तो आज यूरोप जर्मन भाषा बोल रहा होता। ईरान युद्ध में ट्रंप की अपील के बावजूद यूरोप ने उनका साथ नहीं दिया, इससे ट्रंप चिढ़े हुए थे। उन्होंने एक तरह से दूसरे विश्वयुद्ध की याद दिलाई, जब जर्मन तानाशाह हिटलर ने यूरोप पर कब्जा शुरू कर दिया था, तब जर्मनी और जापान की सेनाओं को हराने के पीछे अमेरिकी कार्रवाई की बड़ी भूमिका रही।

**उमेश चतुर्वेदी**
*वरिष्ठ पत्रकार*

अंग्रेजी की नाभिनाल ब्रिटेन से जुड़ी है। ब्रिटिश होते हुए भी अगर अंग्रेजी आज अमेरिका की जुबान बनी हुई है, तो इसकी वजह अठारहवीं सदी में 1756 से 1763 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चले संघर्ष के बाद फ्रांस की पराजय रही है। चार्ल्स ने ठीक ही कहा कि अमेरिका पर वर्चस्व की इस लड़ाई में यदि फ्रांस को जीत मिलती, तो अमेरिका में अंग्रेजी राज नहीं कर रही होती। तब फ्रेंच का वर्चस्व होता। इस युद्ध में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के कई इलाकों से फ्रांस को हटना पड़ा तथा वहां ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इसके बाद से अमेरिका में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। अमेरिका ब्रिटिश राज से भले ही अलग हुआ, पर आज भी वहां की भाषा व सांस्कृतिक परंपराओं में ब्रिटेन की झलक साफ दिखाई देती है।

हर शासक की अपनी एक भाषा होती है। उसी में वह अपना राजकाज चलाता है और उसका रोजाना का व्यवहार भी उसी में होता है। जब किसी भाषा का उपयोग शासन में होने लगता है, तो वह उस क्षेत्र में धीरे-धीरे फैलने लगती है। फिर वही भाषा आम बोलचाल की भाषा बन जाती है। अगर कोई देश या इलाका दूसरी भाषा का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है

कि वह उसे प्यारी है, बल्कि वह अपने अस्तित्व और शासन व्यवस्था से समायोजन के लिए उसे सीखता है और पारंगत होना चाहता है। पहली पीढ़ी तक तो यही कारण होते हैं, बाद की पीढ़ियों के लिए यह आदत बन जाती है। इस तरह देखें, तो हर देश की अपनी भाषा के अलावा वहां प्रचलित विदेशी भाषा को उस इलाके या देश की पहली पीढ़ी संयोगों और ऐतिहासिक संयोगों से सीखती है और अगली पीढ़ी अपनी सहूलियत, जीवनशैली व शासन में हिस्सेदारी के लिए।

आज भारत में एक वर्ग ऐसा है, जिसे इन ऐतिहासिक संयोगों और विकासक्रम से कुछ लेना-देना नहीं है। वे अंग्रेजी से बेइंतहा प्यार करते हैं, पर क्या उनका यह प्यार अंग्रेजी के लिए वैसा ही रहता, अगर 1749 से 1754 के बीच चले द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बजाय फ्रांसीसी डुप्ले को जीत मिली होती? सोचिए, अगर ऐसा हुआ होता, तो क्या होता? तब देश में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित होता। फ्रेंच लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर आज भी बेहद संजीदा हैं। फ्रांस में आज भी अंग्रेजी का प्रयोग सीमित है। 1994 में तो वहां की संसद ने बाकायदा कानून पारित करके देश में अंग्रेजी के बिना वजह के प्रयोग पर रोक लगा रखी है। फ्रांस जाने वालों को पता है कि होटल की लॉबी और हवाईअड्डे से बाहर फ्रेंच जाने बिना वहां रोजाना के कार्य निपटाना कितना कठिन होता है। साफ है कि करीब तीन सौ साल पहले देश पर फ्रांस का कब्जा हो गया होता, और भारतीय अंग्रेजी के बजाय फ्रेंच से प्यार कर रहे होते। तब उन्हें शायद अपने फ्रेंच ज्ञान और धाराप्रवाह फ्रेंच बोलने को लेकर गुमान होता। एक साक्षात्कार में इतिहासकार और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सतीश चंद्रा ने भी कहा था कि बेहतर होता क्लाइव की जगह डुप्ले को जीत मिलती। तब भारत फ्रेंच बोल रहा होता। उनका मानना था कि ब्रिटिश की तुलना में फ्रेंच लोग कहीं ज्यादा संस्कारी होते हैं, इसलिए भारत में आज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर नागरिक बोध होता, अपनी भाषाओं से प्यार होता और उपनिवेशवाद व वैश्विक हालात को लेकर भारतीयों का नजरिया कुछ और ही होता।

मध्य काल यूरोपीय उपनिवेशवाद के विस्तार का काल है। इस दौरान यूरोप के देशों ने बाहर निकलकर एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू किए थे। तकरीबन पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर स्पेन का कब्जा रहा। भौगोलिक प्रसार के लिहाज से देखें, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर स्पेनिश ही बोली जाती है। साफ है कि जहां-जहां स्पेन ने अपना उपनिवेश बनाया, वहां-वहां स्पेनिश पहुंच गई। कुछ इसी तरह ब्रिटेन का जहां-जहां उपनिवेश रहा, वहां अंग्रेजी प्रमुख भाषा बनती गई। इसी तरह, फ्रांस के प्रभाव वाले इलाकों में फ्रेंच बोली जाने लगी। मॉरीशस पर फ्रांस का कब्जा रहा, इसलिए वहां की भोजपुरी पर फ्रेंच का असर दिखता है, जिसे स्थानीय भाषा में 'क्रियोल' कहा जाता है।

शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को अपनी भाषाओं के सांस्कृतिक विकासक्रम की पढ़ाई कम ही कराई है। भाषाओं को राजनीतिक हथियार बनाने के दौर में भी जब स्थानीय और पड़ोसी भाषाओं के खिलाफ अपने ही लोग तलवार निकालते हैं, तो उसकी वजह ऐतिहासिक संयोगों की समझ न होना ही है। ऐतिहासिक संयोगों के साथ आई विदेशी भाषा के जरिये मिलने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक ताकत ने दरअसल इस सोच को कहीं नेपथ्य में डाल रखा है। भारतीय संदर्भ में देखें, तो भारतीय भाषाएं एक-दूसरे की बहनें हैं। इस लिहाज से सबकी अपनी स्थानीय भाषा मातृभाषा और दूसरी भाषा मौसी है। पर ज्यादातर लोग इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। शासन-सत्ता और वैचारिक प्रतिष्ठान भी इस नजरिये से लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास नहीं दिखाते।

भूमंडलीकरण के दौर में किसी विदेशी भाषा को त्याज्य नहीं बनाया जा सकता, उनसे दुश्मनी की सोचना भी बेमानी है। पर अपनी भाषाओं से प्यार होना ही चाहिए। ऐतिहासिक संयोगों के साथ विकसित भाषा की कीमत पर अपनों से बैर का कोई तुक नहीं। बेहतर होगा कि हम सब इसे उसी तरह समझें, जैसे चार्ल्स ने ट्रंप को दिए चुटीले जवाब के जरिये अमेरिका को समझाने की कोशिश की है। चार्ल्स का मजाक भाषाओं के नाम पर लड़ती दुनिया के लिए मानीखेज संदेश है कि हर भाषा के साथ संयोग जुड़े होते हैं और इतिहास भी। इस इतिहास और संयोग को लोग समझें और यह भी सोचें कि भाषाओं के नाम पर आखिर संघर्ष की जरूरत ही क्या है?

edit@amarujala.com

मुद्दा

# अदृश्य कण बन रहे सांसों के दुश्मन

**एक अध्ययन के अनुसार, बढ़ता तापमान पौधों के परागण चक्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे दिल्ली जैसे महानगरों में 'एलर्जिक सीजन' की अवधि पहले के मुकाबले चार सप्ताह तक बढ़ गई है।**

मई के पहले हफ्ते में दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सरकारी एमएमजी अस्पताल में आए 100 में से दस मरीज अस्थमा से पीड़ित मिले। इनमें बच्चों व बुजुर्गों की संख्या अधिक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी की आहट के साथ ही हवा का मिजाज बदलने लगा है। हाल के वैज्ञानिक शोधों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि इस दौरान केवल धूल और धुआं ही नहीं, बल्कि हवा में तैरने वाले अदृश्य परागकण भी सांसों के दुश्मन बन रहे हैं।

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और अन्य शोध संस्थानों के आंकड़े बताते हैं कि मार्च से जून के बीच दिल्ली की हवा में परागकणों की सांद्रता सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है, जो अस्थमा और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों को न्योता दे रही है। द लैंसेट के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, बढ़ता तापमान पौधों के परागण चक्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे दिल्ली जैसे महानगरों में 'एलर्जिक सीजन' की अवधि पहले के मुकाबले चार सप्ताह तक बढ़ गई है। कैसी विडंबना है कि जो पेड़ पर्यावरण सुधारने के इरादे से सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए, वे ही आज लोगों के दम घुटने का कारक बन रहे हैं।

**पंकज चतुर्वेदी**

वैज्ञानिकों के अनुसार, परागकणों की असली ताकत उनके भीतर मौजूद प्रोटीन और ग्लाइकॉल प्रोटीन में निहित होती है। जब ये कण सांस के जरिये अंदर जाते हैं, तो मनुष्य के बलगम के साथ मिलकर और भी जहरीले हो जाते हैं। जैसे ही यह प्रोटीन हमारे खून में मिलता है, तो एक तीव्र एलर्जी को जन्म देता है, जो गंभीर श्वसन रोगों का कारण बनती है। दिल्ली के रिज क्षेत्र और शहरी जंगलों में मौजूद विलायती कीकर जैसे पेड़ भी इस मौसम में भारी मात्रा में परागकण छोड़ते हैं। शुष्क हवा के कारण ये सूक्ष्म कण घंटों वातावरण में तैरते रहते हैं, पर जैसे ही जून-जुलाई में हवा में नमी का स्तर बढ़ता है, ये और भी जहरीले होकर रक्त में अवशोषित होने लगते हैं। यही कारण है कि इन महीनों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तापमान और प्रदूषण का मेल इस स्थिति को और भयावह बना देता है। शोध बताते हैं कि जब तापमान चालीस डिग्री के पार जाता है, तो हवा में मौजूद जहरीली गैसें परागकणों की बाहरी परत को तोड़ देती हैं, जिससे एलर्जी पैदा करने वाले तत्व और भी सक्रिय हो जाते हैं। उन लोगों के लिए खतरा अधिक है, जो पहले से ही दमा या सांस की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे न केवल छींकें और आंखों में जलन होती है, बल्कि अचानक अस्थमा का दौरा पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। फिलहाल, हवा में परागकणों के प्रकार और उनके सटीक घनत्व का पता लगाने की कोई पुख्ता तकनीक भी उपलब्ध नहीं है।

बचाव के लिए केवल मास्क ही काफी नहीं है, बल्कि जीवनशैली में बदलाव की भी जरूरत है। वृक्षारोपण के वक्त यह भी देखना होगा कि हम किन प्रजातियों को चुन रहे हैं। भविष्य में यह संकट और गहरा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का मौसम लंबा होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम विभाग को वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ-साथ 'पराग सूचकांक' भी जारी करना चाहिए, ताकि लोगों को पहले से जानकारी मिल सके कि किस दिन हवा में एलर्जी का खतरा अधिक है और वे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रह सकें।

**मशीन लर्निंग अक्सर खामोशी से ही काम करती है।** - जेफ बेजोस

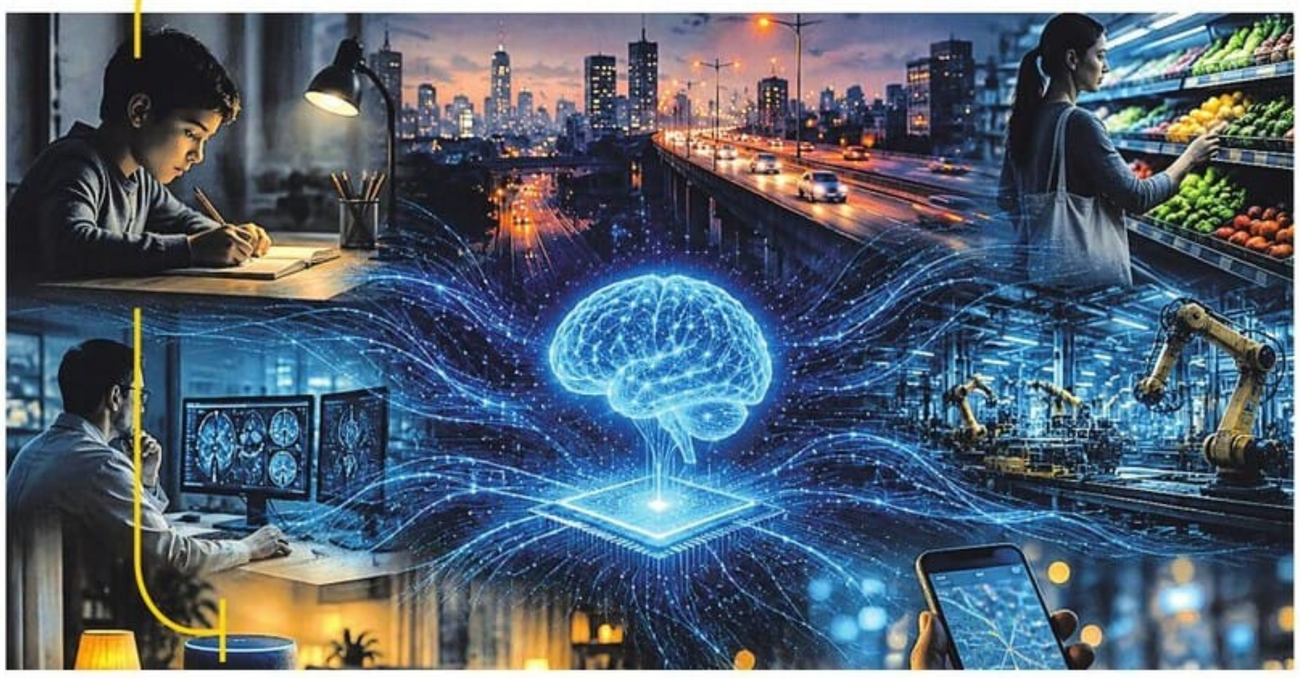

# समय अपने आप में रहस्य है

**मनुष्य समय की गहराई को तभी समझ सकता है, जब शाश्वत सत्य उसके भीतर प्रकाश फैलाए। यही समझ मनुष्य को शांत व जागरूक बनाकर अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है।**

जो व्यक्ति वास्तव में जीवन का आनंद लेना चाहता है और स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है, उसे अपने वर्तमान दिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि मनुष्य केवल बीते हुए कल के बारे में सोचता रहेगा, तो वह पछतावे और निराशा में डूब सकता है। दूसरी ओर, यदि वह आने वाले कल के सपनों में खोया रहेगा, तो कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति बन जाएगा और वास्तविक कर्म से दूर हो जाएगा।

**जे सी मैक्सवेल**

मनुष्य को केवल उन छोटे कार्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जो दिन समाप्त होने के साथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन केवल सांसारिक व्यस्तताओं तक ही सिमट कर रह जाएगा। हालांकि, केवल अनंत और शाश्वत विषयों में खो जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि तब मनुष्य अपने दैनिक जीवन तथा व्यावहारिक कर्मों को दिशा नहीं दे पाएगा। सच्चा संतुलन इसी में है कि मनुष्य अपने आज के कार्यों में अपने पूरे जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग देख सके और उनमें अनंत सत्य की झलक पहचान सके। वास्तव में सुखी वही व्यक्ति है, जो अपने प्रत्येक छोटे कार्य को किसी बड़े और शाश्वत उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान को महत्व देता है, क्योंकि यही वह समय है, जो वास्तव में उसके हाथ में है। वह पूरे मन, परिश्रम और ईमानदारी से अपने दैनिक कार्यों को पूरा करता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसका हर कर्म जीवन के किसी गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है।

जीवन धारा

मनुष्य को प्रकृति की दिव्य प्रक्रिया का एक जीवंत रूप बनना चाहिए। उसमें सीमित और असीम, दोनों का सुंदर मेल दिखाई देना चाहिए। उसे अपने सांसारिक जीवन को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्म करने का अवसर केवल इसी जीवन में मिलता है। उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का अंतिम सत्य केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। समय अपने आप में एक रहस्य है, और मनुष्य उसकी गहराई को तभी समझ सकता है, जब शाश्वत सत्य उसके भीतर प्रकाश फैलाए। यही समझ मनुष्य को शांत, जागरूक और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है।

# चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त

**बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं को अभिव्यक्ति का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे भी सामने आने लगे हैं।**

साल 2022 में चैटबॉट स्टार्टअप कैरक्टर.एआई के संस्थापकों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जहां कोई भी एआई संचालित ऐसे किरदार बना सकता था, जो हमसे संवाद कर सकें। देखते ही देखते इसके दो करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने एक करोड़ से अधिक और चैटबॉट किरदार बना डाले। इन्हें बनाने वाले ज्यादातर उपयोगकर्ता युवा ही थे। मगर फिर स्थिति बदलने लगी।

**एन्नाबेल ब्लेके**
द कन्वर्सेशन

नवंबर 2025 में जब इनके उपयोग से जुड़े किशोरों व नौजवानों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ने लगीं, तो कैरक्टर.एआई ने 18 साल से कम उम्र के किशोरों पर इसके इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। इसका असर यह हुआ कि इस कदम से युवाओं द्वारा किए जा रहे रचनात्मक व भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त एआई प्रयोग दब गए।

हमने युवाओं के एआई के साथ किए जा रहे नए प्रयोगों पर शोध किया, ताकि बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ा जा सके। शोध के मुताबिक, 2026 में अमेरिका के दस में से तीन किशोर रोजाना एआई का उपयोग करेंगे। यह दो बड़ी आशंकाओं को उजागर करता है। पहली, युवा असली मानवीय दोस्ती को एआई से बदल देंगे। दूसरी, वास्तविक लोगों के बजाय चापलूस चैटबॉट से बातचीत करने से किशोरों के सामाजिक विकास और कौशल में कमी आने लगेगी। ये चिंताएं अपनी जगह वाजिब भी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार, 57 फीसदी किशोर एआई का इस्तेमाल सूचना पाने, 54 फीसदी होमवर्क, 47 फीसदी मनोरंजन, 12 फीसदी भावनात्मक समर्थन या सलाह और 8-11 फीसदी अकेलेपन से राहत पाने के लिए करते हैं।

हमारी टीम ने जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच आठ महीने से अधिक समय कैरक्टर.एआई के आधिकारिक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म 'डिस्कॉर्ड' समुदाय में बिताया, जिसके पांच लाख से ज्यादा सदस्य हैं। हमने 13 से 17 वर्ष के युवाओं द्वारा किए गए 2,236 पोस्ट का विश्लेषण किया। इन किशोरों से चर्चा के विश्लेषण के आधार पर हमने कैरक्टर.एआई के साथ जुड़ने के तीन मुख्य उद्देश्य पहचाने। हमने पाया कि युवा लोग भावनात्मक सुकून, मन की भड़ास निकालने, तनाव से मुक्ति पाने और मनोदशा को नियंत्रित करने के लिए किरदारों का उपयोग करते थे। औपचारिक नैदानिक अभ्यास की नकल करने के बजाय हमने युवाओं को 'कंफर्ट बॉट्स' पर चर्चा करते हुए देखा। युवाओं ने सीमाओं का पता लगाया, रचनात्मक दुनिया बनाई और अपने पसंदीदा किरदारों के प्रति प्रेम बढ़ाया। एक किशोर ने किरदारों की आपसी बातचीत के जरिये तीन पुस्तकें लिख डालीं। दूसरे ने रंगमंच के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले थिएटर किरदारों का एक समूह बनाया। उन्होंने बताया कि इससे उनके कौशल दुनिया के सामने आए, उनकी रचनात्मकता बढ़ी और लेखन में भी सुधार हुआ।

कई युवाओं ने एआई का उपयोग करके वास्तविक जीवन के रिश्तों को समझा और वास्तविक जीवन की कठिन परिस्थितियों को नए सिरे से गढ़ा। कुछ लोगों ने अपने ही 'क्लोन' बनाए। हकीकत से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसे किरदार बनाए, जो वास्तविक दुनिया के चुनौतीपूर्ण रिश्तों को दर्शाते हैं, जैसे कुटिल दोस्त, परेशान करने वाली बहन आदि। हमने उन सात विशिष्ट किरदारों के पैटर्न का भी विश्लेषण किया, जिन्हें युवा बना रहे थे और जिन पर चर्चा कर रहे थे। ये थे- भावनात्मक सहारा देने वाले किरदार, मजाक उड़ाने, चुनौती देने और बे-सिर पैर की बातें करने वाले किरदार, भावनात्मक रूप से जटिल पात्र, वास्तविक लोगों पर आधारित किरदार आदि। युवा जानबूझकर ऐसे किरदार बना रहे थे, जो व्यथित, सीमा से परे, चंचल, रचनात्मक और चिंतनशील हैं।

**सुपरह्यूमन**

*यह अत्याधुनिक एआई-आधारित ई-मेल और उत्पादकता टूल है, जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिन्हें हर दिन बड़ी संख्या में ई-मेल भेजना या देखना होता है। यह टूल एआई की मदद से ई-मेल लिखने, जवाब देने, सारांश तैयार करने और इनबॉक्स व्यवस्थित करने का काम बेहद तेज बना देता है। इसमें एआई ड्राफ्ट्स फीचर है, जो केवल कुछ शब्दों या बुलेट पॉइंट्स से पूरा ई-मेल तैयार कर देता है। इंस्टैंट फीचर आने वाले ई-मेल के लिए स्वतः ड्राफ्ट जवाब बनाता है, जबकि ऑटो समराइज फीचर लंबे ई-मेल थ्रेड का छोटा सारांश दिखाता है।*

यह दर्शाता है कि हमें 'साथी एआई' को एक सजातीय वस्तु की तरह मानना बंद करना होगा। एआई चैटबॉट्स को एक जैसा मानना वैसा ही है, जैसे हर तरह के स्क्रीन टाइम को एक ही अनुभव समझ लेना। जबकि इसमें फर्क होता है कि बच्चा परिवार के साथ कोई एनिमेशन सीरीज देख रहा है या फिर रात में सोने के बजाय अकेले फोन पर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। युवाओं के अनुभव, प्रयोग और विचार मायने रखते हैं। प्रतिबंध लगाने जैसे कदम से तो किशोरों के लिए बेहतर और सुरक्षित एआई उत्पाद बन ही नहीं पाएंगे।

इसका समाधान युवाओं को एआई से दूर रखना नहीं, बल्कि ऐसा एआई बनाना है, जो उनके भरोसे के लायक हो, उनकी रचनात्मकता को और बढ़ावा दे तथा उन्हें परिवार, मित्रता व समुदाय के साथ भौतिक दुनिया से भी जोड़े रखे। *-साथ में एदुआर्दो वेल्लोसो और मार्कस कार्टर*

# दुनियाभर में खाद्य कीमतें तीन साल के शीर्ष पर, देश में महंगाई बढ़ने का खतरा

## एफएओ का खाद्य कीमत सूचकांक तीसरे माह भी बढ़ा, 130.7 अंक पहुंचा

बोनस डेस्क

**नई दिल्ली।** अगर आप महंगाई को राशन के पर्चे में ढूंढ रहे हैं, तो आंकड़े आपकी चिंता को सही ठहरा रहे हैं। चिंता सिर्फ आपके मोहल्ले या शहर की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की थाली फिर महंगाई की आंच में तपने लगी है, क्योंकि अप्रैल में खाद्य पदार्थों की वैश्विक कीमतें बढ़कर तीन साल से ज्यादा समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। यह देश के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत की रसोई का बजट अब सिर्फ भारतीय खेत और मंडी से तय नहीं होता। दुनिया के बाजार भी थाली का हिसाब बदलते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक, ईरान युद्ध और होर्मुज के बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से खाद्य कीमतों का सूचकांक लगातार तीसरे महीने बढ़ा और बीते माह 1.6 फीसदी चढ़कर 130.7 अंक पर पहुंच गया। यह फरवरी, 2023 के बाद सबसे ज्यादा है और सालाना आधार पर दो फीसदी अधिक है। हालांकि, मार्च, 2022 के 160.2 अंक की ऊंचाई से 18.4 फीसदी नीचे है।

सबसे बड़ी आग खाद्य तेल में लगी है। एफएओ का खाद्य तेल सूचकांक अप्रैल में 6 फीसदी उछलकर 193.9 अंक पर पहुंच गया, जो जुलाई, 2022 के बाद सर्वाधिक है। पाम, सोया, सूरजमुखी समेत लगभग सभी खाद्य तेल में तेजी आई। वजह सिर्फ खाने की मांग नहीं है। महंगे कच्चे तेल ने बायोफ्यूल की मांग बढ़ा दी है। यानी ऊर्जा बाजार की गर्मी रसोई तक पहुंच रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में उत्पादन घटने की आशंका से पाम तेल पांचवें माह भी महंगा हुआ।

**15 माह के उच्च स्तर पर पहुंचेगी महंगाई**

*अब तक काबू में रहीं कीमतों का दबाव अगले सप्ताह आने वाले खुदरा महंगाई के आंकड़े में दिख सकता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, अप्रैल के आंकड़ों में खुदरा महंगाई मार्च के 3.4 फीसदी से बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर 3.8 फीसदी पर पहुंच सकती है। हालांकि, यह अब भी आरबीआई के 4 फीसदी लक्ष्य के आसपास है।*

### अनाज के मोर्चे पर भी राहत नहीं

*अनाज भी राहत नहीं दे रहा। एफएओ का अनाज सूचकांक अप्रैल में 0.8 फीसदी बढ़ा। अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखे की चिंता और ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश की आशंका से गेहूं के दाम बढ़े। मक्का भी इथेनॉल की मांग और तंग आपूर्ति से महंगा हुआ। चीनी में 4.7 फीसदी और डेयरी में 1.1 फीसदी की गिरावट से राहत जरूर मिली, लेकिन मीट इंडेक्स 1.2 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।*

### घर में पकने वाली थालियां भी महंगी

**क्रिसिल की रिपोर्ट**

अप्रैल की रसोई ने महंगाई का पहला संकेत दे दिया है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक, घर में पकने वाली थालियों की कीमत सालाना आधार पर दो फीसदी बढ़ी हैं। शाकाहारी थाली की कीमत 26.7 रुपये पहुंच गई, जबकि मांसाहारी थाली 55.1 रुपये की हो गई।

- टमाटर ने सबसे ज्यादा झटका दिया। इसका भाव सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़कर 29 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। खाने के तेल और रसोई गैस सिलिंडर भी 7-7 फीसदी तक महंगे हुए।
- चिकन की कीमत दो फीसदी बढ़ गई, क्योंकि तेज गर्मी से पक्षियों की मृत्यु दर बढ़ी और आपूर्ति पर असर पड़ा।
- राहत सिर्फ प्याज, आलू एवं दालों से मिली, जिनकी कीमतों में सालाना आधार पर 14 फीसदी तक नरमी ने थाली को और ज्यादा महंगा होने से बचा लिया।

# एसबीआई : लाभ 6 फीसदी बढ़ने के बाद भी 7 फीसदी टूटा शेयर

## देश के सबसे बड़े बैंक को मार्च तिमाही में 19,684 करोड़ का मुनाफा, बाजार को 20,300 करोड़ से ज्यादा की थी उम्मीद

बोनस डेस्क

**नई दिल्ली।** शेयर बाजार में शुक्रवार को सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने दिया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़ाया, लाभांश भी घोषित किया, लेकिन शुक्रवार को शेयर करीब 7 फीसदी तक टूट गया। वजह साफ थी...नतीजे अच्छे थे, लेकिन बाजार की उम्मीद से कमजोर थे।

मार्च तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 5.6 फीसदी बढ़कर 19,684 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि बाजार को 20,300 करोड़ से ज्यादा के लाभ की उम्मीद थी। बैंक ने 17.35 रुपये प्रति शेयर लाभांश भी घोषित किया। शुद्ध ब्याज आय 4 फीसदी बढ़कर 44,380 करोड़ रही, लेकिन निवेशकों की नजर कमजोर ट्रेजरी इनकम और उम्मीद से कम ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर अटक गई। इसलिए, मुनाफे के बावजूद शेयर में तेज बिकवाली हुई।

एसबीआई की गिरावट ने सरकारी बैंकिंग क्षेत्र का मूड बिगाड़ दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.06 फीसदी गिरकर 8,371.95 पर बंद हुआ। इंडेक्स में एसबीआई 6.66 फीसदी, पंजाब एंड सिंध बैंक 3.65 फीसदी और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.39 फीसदी टूटे। बैंक निफ्टी और वित्तीय शेयरों पर भी दबाव दिखा।

### सेंसेक्स 516 अंक टूटा, पर साप्ताहिक बढ़त

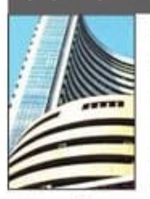

बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी दिन कमजोर रहा। ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने और कच्चे तेल में उछाल ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। सेंसेक्स 516.33 अंक गिरकर 77,328.19 और निफ्टी 150.50 अंक टूटकर 24,176.15 पर बंद हुआ। हालांकि, पूरे हफ्ते के हिसाब से बाजार ने बढ़त बचा ली। निफ्टी 0.7 फीसदी और सेंसेक्स 0.54 फीसदी चढ़े। यानी, शुक्रवार की गिरावट के बावजूद हफ्ता पूरी तरह खराब नहीं रहा।

■ **अगले सप्ताह इन पर रहेगी बाजार की नजर :** बाजार की नजर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर होगी। अप्रैल की खुदरा-थोक महंगाई के आंकड़े, एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग एवं सिप्ला, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावरग्रिड जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे तेल पर भी नजर रहेगी। निवेशकों के लिए संकेत साफ है कि बाजार में दुविधा है। बैंकिंग, तेल और वैश्विक तनाव किसी भी समय मूड बदल सकते हैं।

## रुपया नुकसान से उबरा, 71 पैसे मजबूती के साथ 93.51 पर बंद

**मुंबई।** रुपया शुक्रवार को नुकसान से उबरते हुए डॉलर के मुकाबले 71 पैसे मजबूत होकर 93.51 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिति के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ताजा चिंताओं के बावजूद स्थानीय मुद्रा में यह मजबूती दर्ज की गई।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा, पश्चिम एशिया में समझौते को लेकर उम्मीद कम होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर करीब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इससे पहले ब्रेंट क्रूड गिरावट के साथ 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.58 पर खुला। बंद होने से पहले कारोबार के दौरान यह 94.68 तक फिसल गया था। उधर, डॉलर सूचकांक 0.15 फीसदी गिरावट के साथ 97.91 पर आ गया।

मिरै एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ईरान तनाव के फिर बढ़ने बीच रुपये में कमजोर रुख रहने का अनुमान है। डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 94.10 से 94.90 के दायरे में रह सकता है। एजेंसी

## ई-वे बिल 11.8 फीसदी बढ़ा वृद्धि छह माह में सबसे कम

**नई दिल्ली।** देश में माल की आवाजाही अप्रैल में जरूर बढ़ी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक, बीते माह 13.33 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए। यह पिछले साल के मुकाबले 11.8 फीसदी ज्यादा है, लेकिन इसकी वृद्धि छह महीनों में सबसे धीमी रही। मार्च में रिकॉर्ड 14.06 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट हुए थे और सालाना वृद्धि 12.9 फीसदी थी।

अप्रैल के आंकड़े तो मजबूत है, लेकिन मार्च जैसी तेजी नहीं है। मार्च में वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कंपनियों की बिलिंग, डिस्पैच और इन्वेंटरी क्लियरेंस तेज होती है। इसलिए, उस माह रिकॉर्ड ई-वे बिल बनना असामान्य नहीं था। अप्रैल में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ यह दबाव घटा और ई-वे बिल में मार्च के मुकाबले 5 फीसदी कमी आई। ■ बोनस डेस्क

## न्यूज डायरी

### विदेशी मुद्रा भंडार 7.79 अरब डॉलर घटा

**मुंबई।** देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक मई को समाप्त सप्ताह में 7.79 अरब डॉलर घटकर 690.69 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले हफ्ते भी 4.82 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में यह कोष बढ़कर 728.49 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक मई वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 2.79 अरब डॉलर घटकर 551.82 अरब डॉलर रह गई। स्वर्ण भंडार 5.02 भी अरब डॉलर की गिरावट के साथ 115.22 अरब डॉलर रहा। एजेंसी

### जेप्टो समेत 6 कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी

**नई दिल्ली।** जेप्टो समेत छह कंपनियों को आईपीओ से पूंजी जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। अन्य कंपनियों में धूत ट्रांसमिशन, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, सर्जीवियर, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और होटल पोलो टावर्स शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, जेप्टो आईपीओ के जरिये करीब 11,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। अगर यह सूचीबद्ध होने में सफल रही, तो कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों जोमैटो और स्विगी की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जो पहले से बाजार में सूचीबद्ध हैं। एजेंसी

## घाटे वाले मार्गों पर उड़ानें कम या सेवाएं निलंबित करेगी एअर इंडिया

### कंपनी ने एक तिमाही टाली सालाना वेतन वृद्धि, खर्च में कटौती करने पर जोर

**नई दिल्ली।** एअर इंडिया ने पश्चिम एशिया संकट से पैदा चुनौतियों और बढ़ते परिचालन खर्च के बीच लागत में कटौती करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत, कंपनी उन मार्गों पर उड़ानों की संख्या घटाने या सेवाएं निलंबित कर सकती है, जहां हवाई क्षेत्र से जुड़ी बाधाओं के कारण लगातार घाटा हो रहा है।

विमानन कंपनी के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को टाउनहॉल बैठक में कहा, मौजूदा हालात में हर संसाधनों की बर्बादी और फिजूलखर्ची रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। कंपनी ने सालाना वेतन वृद्धि को कम से कम एक तिमाही के लिए टालने का फैसला किया है। इसके बावजूद, बीते वित्त वर्ष के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान और तय प्रमोशन प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने कर्मियों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल छंटनी की योजना नहीं है। एयरलाइन ने अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती शुरू की थी, जो मई में भी जारी है। जून और जुलाई के लिए उड़ान कार्यक्रम में और कटौती हो सकती है। एजेंसी

## तिमाही लाभ को पूंजी की गणना में जोड़ सकेंगे बैंक

**मुंबई।** आरबीआई ने बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में चालू वित्त वर्ष के तिमाही मुनाफे को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। अब बैंक कुछ शर्तों के तहत हर तिमाही के मुनाफे को अपनी कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी में जोड़ सकेंगे।

बैंकों को पहले तिमाही मुनाफा पूंजी में शामिल करने की अनुमति तो थी, लेकिन एनपीए से जुड़ी एक अतिरिक्त शर्त पूरी करनी होती थी। पहले, बैंक तिमाही लाभ को तभी पूंजी में जोड़ सकते थे, जब एनपीए का प्रावधान एक निश्चित सीमा में हो। एजेंसी

## पेट्रोलियम कंपनियों को 30,000 करोड़ का नुकसान सरकार हर महीने उठा रही 14,000 करोड़ का बोझ

**नई दिल्ली।** ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को मार्च मध्य से अब तक यानी डेढ़ माह में करीब 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क में कटौती से राहत जरूर मिली है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को कहा, अप्रैल में पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान दर्ज किया गया। इस तरह, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को प्रतिदिन 700-1,000 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा, सरकार ने अगर पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती नहीं की होती, तो नुकसान बढ़कर 62,500 करोड़ तक पहुंच सकता था। हालांकि, उत्पाद शुल्क में कटौती की वजह से सरकार खुद भी हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान उठा रही है। ब्यूरो

### पेट्रोल-डीजल की नहीं हो रही राशनिंग

शर्मा ने ईंधन की कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, पेट्रोल और डीजल की न तो राशनिंग हो रही है और न ही कमी है। तेल कंपनियां बाजार से महंगा क्रूड, गैस और एलपीजी खरीद रही हैं। इसके बावजूद सरकार कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। शर्मा ने कहा, दो दिनों में ग्राहकों को 97 लाख एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराए हैं। पांच किलो वाले 1.11 लाख एफटीएल सिलिंडर बेचे गए हैं। ईंधन और एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।

## सर रतन टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक 16 मई तक स्थगित

**नई दिल्ली।** सर रतन टाटा ट्रस्ट की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक 16 मई तक के लिए रद्द कर दी गई। बैठक में टाटा सन्स के बोर्ड में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर दोबारा विचार किया जाना था।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक रद्द करने की कोई वजह नहीं बताई गई है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 23.6 फीसदी हिस्सेदारी है। इसका कुल मूल्यांकन 180 अरब डॉलर से ज्यादा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैठक पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। एजेंसी

Job Alert अमर उजाला
Real-time job alerts amarujala.com/jobs

**बिहार तकनीकी सेवा आयोग**
अनुदेशक के पदों पर निकली भर्ती

726 पद
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : btsc.bihar.gov.in

**एमसीएल में करें आवेदन ■ 500 पद**
असिस्टेंट फोरमैन, टेक्नीशियन व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 28 मई, 2026
पात्रताएं : मैट्रिक, आईटीआई व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : mahanadicoal.in

**बिहार लोक सेवा आयोग ■ 44 पद**
शुगर केन ऑफिसर के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष
यहां आवेदन करें : bpsc.bihar.gov.in

**एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया ■ 34 पद**
कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : edcilindia.co.in

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम ■ 28 पद**
विशेषज्ञ व वरिष्ठ रेजिडेंट के पदों पर मौके
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 14 मई, 2026
योग्यताएं : एमबीबीएस, पीजी डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : esic.nic.in

**बीईएमएल लिमिटेड में अवसर ■ 18 पद**
उप-महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 14 मई, 2026
वेतनमान : रुपये 50,000 से रुपये 2,40,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : bemlindia.in

**यहां भी हैं रोजगार की संभावनाएं...**
अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, भोपाल : स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं भ्रूणविज्ञानी के पद रिक्त।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 16 मई, 2026
■ aiimsbhopal.edu.in
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड : ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर मौके।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 13 मई, 2026
■ becil.com

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

# एजुकेशन & कॅरिअर

सोच बड़ी रखिए, सफलता अपने आप बड़ी हो जाएगी।

## आज तुमने क्या नया सीखा

*बच्चों से यह सवाल पूछते रहने से उन्हें बेहतर तरीके से सीखने, अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने में मदद मिलती है*

मेलिसा बार्न्स
एसोसिएट प्रोफेसर
ला ट्रोब विश्वविद्यालय

जब माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा के विषय में सोचते हैं, तो वे अक्सर बुनियादी कौशल, परीक्षा परिणाम, उसके प्रयास और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। लेकिन स्कूल में उनके बच्चे की सफलता को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक भी है, जिसे मेटाकॉग्निशन (परासंज्ञानात्मक क्षमता) कहा जाता है। इसका अर्थ है-अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझना और नियंत्रित करना। यह कौशल बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने, अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चे में इस क्षमता को विकसित करने के लिए अवश्य विचार करना चाहिए।

**■ अपने विचार खुलकर व्यक्त करें**

माता-पिता अपने विचार और निर्णय लेने के तरीके बच्चे के सामने खुलकर व्यक्त करें। जैसे यदि आप किसी काम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे से कह सकते हैं, "पहले मैं आसान काम पूरा करूंगा, फिर मुश्किल काम करूंगा, ताकि समय अच्छे से व्यवस्थित हो सके।" इससे बच्चा सीखता है कि किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाना जरूरी है।

**■ गलतियों को सामान्य मानें**

बच्चे को यह समझाएं कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब हम कोई गलती करते हैं, तो इससे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला है। इसलिए गलती पर परेशान होने के बजाय उसे सुधारने के लिए अलग और बेहतर तरीका अपनाना चाहिए। इससे बच्चा धीरे-धीरे समझदार बनता है और अगली बार वही गलती दोहराने से बचता है।

**■ नियमित दिनचर्या है जरूरी**

नियमित दिनचर्या बच्चे में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करती है। जब बच्चा रोज अपना स्कूल बैग खुद पैक करता है या होमवर्क की योजना बनाता है, तो वह अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करना और पहले से तैयारी करना सीखता है। इससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन-सी चीज जरूरी है, क्या करना बाकी है और किसी बदलाव की स्थिति में कैसे खुद को उसके अनुसार ढालना है। धीरे-धीरे यह आदत बच्चे को अधिक आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाती है।

- *बच्चे से रोज उसके सीखने के बारे में सवाल करें, जैसे कि आज तुमने क्या नया सीखा?*
- *यह पूछें कि कौन-सी चीज उसे समझने में मुश्किल लगी, ताकि वह अपने सीखने पर ध्यान दे सके।*
- *गलती करने पर डांटने के बजाय उसकी वजह को समझें और सुधार के लिए चर्चा करें।*

**■ चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें**

बच्चे को अपने सीखने और अनुभवों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना उसकी समझ और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। स्कूल से आने के बाद, यदि आप उससे पूछते हैं कि आज तुमने क्या नया सीखा? या कौन-सी चीज समझने में कठिनाई आई? तो बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और खुद का मूल्यांकन करना सीखता है। इसी तरह, अगर वह स्कूल के लिए कोई जरूरी चीज भूल जाए, तो डांटने के बजाय उससे पूछें कि अगली बार ऐसा न हो, इसके लिए क्या अलग कर सकते हो? इससे बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है। **-द कन्वर्सेशन**

### इंटर्नशिप प्रोग्राम

**डीआरडीओ-डीएलआरएल इंटर्नशिप**
- पात्रताएं : शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 में बीई/बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्र।
- लाभ : रुपये 30,000 का वजीफा और इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र।
- अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
- आधिकारिक वेबसाइट : drdo.gov.in/drdo/en

### आवेदन आमंत्रित

**गांधी फेलोशिप प्रोग्राम**
- संस्था : पिरामल फाउंडेशन
- पात्रताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन आदि।
- शैक्षणिक योग्यताएं : दसवीं, बारहवीं, ग्रेजुएशन व पोस्ट-ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
- आयु-सीमा : अधिकतम 25 साल
- आधिकारिक वेबसाइट : gandhifellowship.org/about-fellowship/

### एग्जाम अलर्ट

**एचएसएससी कॉन्स्टेबल पीएमटी परीक्षा**
- परीक्षा की तिथि : 11 से 18 मई, 2026
- पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेमी होनी चाहिए और छाती का माप 83 सेमी (बिना फुलाए) तथा 87 सेमी (फुलाने पर) होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेमी निर्धारित की गई है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें adv012026.hryssc.com/

**एमपीईएसबी नर्सिंग ऑफिसर व सिस्टर ट्यूटर परीक्षा**
- परीक्षा की तिथि : 15 मई, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य अभिरुचि और संबंधित विषय पर आधारित कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें esb.mp.gov.in

### खुद को परखें

1. यूफोरबिया अनंतपुरामेंसिस और यूफोरबिया चालमेंसिस क्या हैं?
   (a) नव-खोजी गईं पादप प्रजातियां
   (b) आक्रामक खरपतवार
   (c) कवक
   (d) नव-खोजी गईं मछली की प्रजातियां
2. यूडीजीएएम पोर्टल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था?
   (a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
   (b) भारतीय रिजर्व बैंक
   (c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
   (d) वित्त मंत्रालय
3. इंडोपोटामोन अलीपुरदुआरेंस नामक मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी?
   (a) पश्चिम बंगाल (b) आंध्र प्रदेश
   (c) तमिलनाडु (d) कर्नाटक
4. दोरजिलुंग जलविद्युत परियोजना किस देश में स्थित है?
   (a) बांग्लादेश (b) म्यांमार
   (c) भूटान (d) नेपाल

*उत्तर-1.a, 2.b, 3.a, 4.c*

09 मई, 1960

### आज का दिन

अमेरिका के एफडीए ने पहली बर्थ कंट्रोल पिल इनोविड-10 को मंजूरी दी थी। यह महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक विकल्पों में ऐतिहासिक कदम साबित हुई।

- 1689 : ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की।
- 1866 : स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था।
- 1874 : मुंबई (तब बंबई) में पहली बार घोड़ों से खींची जाने वाली ट्राम शुरू हुई थी।
- 1986 : माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे का निधन हुआ था।

**व्रत त्योहार**

आज : ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी।
कल : ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : सायं 16.30 से 18.00 तक

### कल का पंचांग

सूर्योदय : 05.38
सूर्यास्त : 18.57
(भारतीय मानक समयानुसार)

विक्रमी संवत 2083, 20 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 27 प्रविष्टे, 22 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी 15.06 तक उपरांत नवमी, धनिष्ठा नक्षत्र 24.49 तक उपरांत शतभिषा नक्षत्र, ब्रह्म योग 26.08 तक उपरांत ऐंद्र योग, कौलव करण 15.06 तक उपरांत तैतिल करण, चंद्रमा कुंभ राशि में 12.06 बजे।

### राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

**मेष :** आत्मबल बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ संभव है। व्यवसाय में उन्नति होगी। घर में शांति रहेगी।

**वृष :** स्वविवेक से अटका कार्य बन सकता है। व्यावसायिक स्थिति में सुधार आएगा। यात्रा संभव है।

**मिथुन :** दिनमान प्रतिकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

**कर्क :** मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। भौतिक इच्छा की पूर्ति संभव है।

**सिंह :** आरोग्य सुख उत्तम रहेगा। राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में नूतन पद भार संभव है।

**कन्या :** किसी परेशानी में घिरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान बना रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

**तुला :** आलस्य पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है।

**वृश्चिक :** भाग्य सहायक रहेगा। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ कम होगा।

**धनु :** मानसिक उत्तेजना से बचें। स्वजनों से मतभेद बढ़ सकते हैं। संतान से मतभेद रहेंगे।

**मकर :** समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। माता से सुख मिलेगा। उदर कष्ट संभव है।

**कुंभ :** सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी। व्यावसायिक लाभ से संतुष्ट रहेंगे।

**मीन :** लोकप्रियता में वृद्धि होगी। संपत्ति में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें।

**सुडोकू**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 2 | | |
| 9 | 1 | | | | | | | 7 |
| | | 6 | | 3 | 4 | 9 | | |
| 7 | | 1 | | | 3 | | 5 | |
| | 9 | | | 4 | | | 6 | |
| | 8 | | 9 | | | 1 | | 3 |
| | | 9 | 4 | 2 | | 8 | | |
| 4 | | | | | | | 9 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 |

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

चिंतन

# शुभेंदु को मिला ताज, साथ ही उम्मीदों का भी बोझ

मंथन
कृष्ण प्रताप सिंह

शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह राज्य के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा उनके शपथ समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भवानीपुर में ममता बनर्जी को पटकनी देकर शुभेंदु ने पहले ही दिखा दिया था कि वह इस पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद शुभेंदु के नेता चुने जाने का ऐलान किया। भाजपा ने इस मौके पर सभी विपक्षी दलों का आह्वान किया कि वे राज्य के विकास में सहयोग करें। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देगी। यह दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिसने बंगाल की प्रगति को बाधित किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे प्रशासन को ही पार्टी कैडर में बदल दिया था। यही नहीं, अपराधी और असामाजिक तत्व पार्टी की रीढ़ बन गए थे। भाजपा की यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। बंगाल इस समय जिस दशा में है, वह भाजपा के लिए एक अवसर भी है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। गरीबी चरम पर है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं या तो लागू नहीं हुई या लोगों तक उसका आधा-अधूरा लाभ ही पहुंचा। कट मनी एक बड़ी समस्या रही। वाम शासन की यह कुप्रथा तृणमूल कांग्रेस के शासन में भी बदस्तूर जारी रही। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। बंगाल कभी देश की सांस्कृतिक धुरी था। राज्य की यह पहचान लौटाना भी जरूरी है। अब सत्ता संभालने के बाद शुभेंदु सरकार के सामने कानून-व्यवस्था, खराब नागरिक सुविधाओं और राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति जैसी कई चुनौतियां होंगी। केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही दबाव में थी। नई सरकार की पहली प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बहाल करना और हाल के दिनों में हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाना होगी। नई सरकार को भाजपा के कई वादों को भी पूरा करना होगा। इनमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल है। भाजपा ने बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने का भी वादा किया है। साथ ही अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की योजना भी सरकार के एजेंडे में होगी, ताकि बड़े पैमाने पर पलायन रोका जा सके। नई भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और बांग्लादेश सीमा से होने वाले अवैध प्रवासन पर रोक लगाने की दिशा में भी काम करेगी। भाजपा ने यह भी वादा किया है कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी और लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अदालत में दिए गए हलफनामे के अनुसार इस पर अतिरिक्त 42,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शुभेंदु राज्य के नौवें मुख्यमंत्री होंगे। तीन बार सांसद रहे शिशिर अधिकारी के पुत्र शुभेंदु ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से की थी। उस समय वामपंथी दलों का प्रभुत्व चरम पर था। शिशिर अधिकारी यूपीए-2 सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रह चुके थे। ममता बनर्जी और टीएमसी से शुभेंदु की दूरी तब बढ़ने लगी, जब ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी और नंबर दो नेता बनाना शुरू किया। 2021 में नंदीग्राम और फिर इस बार भवानीपुर में ममता को हराने के बाद शुभेंदु भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बड़े नेता बनकर उभरे। 2021 के बाद विपक्ष के नेता के रूप में टीएमसी के भारी बहुमत के बावजूद उनका आक्रामक रुख पार्टी में उनकी स्थिति को और मजबूत करता गया।

# वामपंथ ने आखिरी सरकार भी गंवाई

पश्चिम बंगाल के शोर में केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर देश का कुछ कम ही ध्यान जा रहा है। हालांकि राजनीतिक लिहाज से वे भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हाथों वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की करारी हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे के साथ ही देश में वामपंथी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। यह पांच साल पहले ही खत्म हो जाता, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में विजयन के कामकाज से खुश केरल के मतदाता उन्हें 'बख्श' नहीं देते।

इस बार 'केरल के धोती पहनने वाले मोदी' की छवि भी उनकी सत्ता नहीं बचा पाई और वे 'अब तक के आखिरी वामपंथी मुख्यमंत्री' के रूप में भूतपूर्व हो गए। यहां याद किया जिनका चाहिए कि ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के मुख्यमंत्रित्व में देश की पहली वामपंथी सरकार भी 5 अप्रैल, 1957 को इसी राज्य में बनी थी, उसके राज्य बनने के बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में। इस मायने में अभूतपूर्व थी कि उसके रूप में न केवल भारत, बल्कि दुनिया में कहीं भी पहली बार किसी कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में सत्ता हासिल हुई थी। नम्बूदरीपाद सरकार द्वारा व्यापक भूमि सुधारों और महत्वपूर्ण शैक्षिक बदलावों के आगाज के बीच 31 जुलाई, 1959 को तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों उसको बर्खास्त करा दिया तो नेहरू की तीखी आलोचनाएं की गई थीं। कारण यह कि उस दौर में वामपंथ को सत्ता का सबसे प्रतिबद्ध वैचारिक प्रतिपक्ष माना जाता था। बंटवारे और बिखराव के बावजूद उसने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे अपने सुरक्षित गढ़ बना रखे थे। इसलिए वे गढ़ ढहे तो उसकी सही-गलत रीति-नीति और बढ़ते-घटते प्रभावों से जुड़े बहुत से प्रश्न खासी तेजी से पूछे जाने लगे थे। उनमें सबसे बड़ा यह था कि वे चुनावों में लगातार पराभव की ओर क्यों जाने लगे हैं? उनके विरोधियों को उन्हें चिढ़ाते हुए यह तक कहने का मौका क्यों हाथ लग रहा है कि आगे चलकर वे विलोपीकरण के शिकार हो जाएंगे? निस्संदेह, अब, उनके अपनी अंतिम सरकार तक गंवा देने के बाद इन प्रश्नों को नए सिरे से और ज्यादा तेजी से पूछा जाएगा। साथ ही यह प्रश्न भी कि उस हिंदी प्रदेश में उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति भी क्यों मुश्किल होती जा रही है, जिसे देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है और जिसकी जमीन को वे एक समय अपने लिए बेहद अनुकूल और उर्वर मानते थे? क्यों यह उम्मीद लगातार नाउम्मीद होती चली आ रही है कि कौन जाने सुरक्षित गढ़ खो देने के बाद ही सही, वे अपनी संभावनाओं के देशव्यापी विस्तार को जीवन-मरण का प्रश्न मानकर उसके लिए नई मुहिमों का मन बनाएं? सच कहें तो वामदलों के नेताओं के लिए इन सवालों के जवाब इसलिए भी कठिन हो चले हैं कि वे संसदीय कहें अथवा चुनावी राजनीति में उतरे तो उसे अपनी क्रांति कामना के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे से थे, मगर समय के साथ खुद उसके हाथों इस्तेमाल होकर रह गए हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद जतन से विकसित की गई 'सारी मध्यवर्गी पार्टियों के सबसे प्रतिबद्ध वैचारिक प्रतिपक्ष' की अपनी छवि भी वे नहीं

बचा पाए हैं। इसलिए कि सत्ता संघर्षों में मध्यमार्गी पार्टियां विचारधाराओं को लात मारकर अपना तकिया जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र आदि की विडंबनाओं पर रखने लगी तो ये दल उनसे अलगाव का खतरा उठाने का साहस प्रदर्शित नहीं कर पाए और तत्कालीन परिस्थितियों के नाम पर कभी इस तो कभी उस बड़ी पार्टी या गठबंधन की पालकी के कहार की भूमिका में दिखने लगे। तिस पर स्थितियों और परिस्थितियों के आकलन में उन्होंने लगातार गलतियां कीं। मिसाल के तौर पर आजादी के पहले अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इस निर्देश पर अमल के बजाय कि उसे पूरी शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, लगातार ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे पर चलती रही। इसके फलस्वरूप स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भूमिका को तार्किक परिणति नहीं दे सकी। आजादी के बाद माकपा को ज्योति बसु के रूप में देश को पहला वामपंथी प्रधानमंत्री देने का अवसर हाथ लगा तो भी उसने साफ इनकार कर दिया। तब वामदलों के विरोधियों व शुभचिंतकों दोनों को कहना पड़ा कि वामदलों की ट्रेन छूट गई है। ज्योति बसु को भी बाद में इसे हिमालय जैसी भूल बताना पड़ा। यह भी वामपंथ द्वारा स्थितियों के गलत आकलन के कारण ही हुआ कि जब उन्हें राजीव गांधी व मनमोहन सिंह प्रवर्तित नई आर्थिक नीतियों से लड़ना चाहिए था, उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस सांप्रदायिकता से लड़ने में ही लगा दी, जो जनविरोधी आर्थिक नीतियों का ही उत्पाद थी, इस अर्थनीति के साथ ही स्वतः खत्म हो जाती। आश्चर्य है कि उनके लड़ते-लड़ते नई अर्थनीति और सांप्रदायिकता दोनों 'अजेय' हो गईं और मनमोहन के राज में अमेरिका से परमाणु करार के विरोध में सरकार से समर्थन वापस लेने का नुकसान भी अकेले वामपंथ को ही उठाना पड़ा। वामपंथी ऐसी भूलें नहीं करते तो आज प्रायः सारी मध्यवर्गी पार्टियों से निराश देश उन्हें खासी उम्मीद के साथ निहारता। वे कह पाने की स्थिति में होते कि अब हमारी बारी है। अभी तो वे विरोधियों की लगातार बढ़ती जा रही घृणा के साथ अपने गढ़ों तक में जनता का कोप झेल रहे हैं और फिर भी अपने अंतर्विरोध नहीं सुलझा पा रहे। आज भी, नवपूंजीवादी नीतियों से पूरे दम-खम के साथ दो-दो हाथ करने के बजाय इन संघर्ष विमुख दलों ने अपनी क्रांतिकामना को भी कर्मकांड बना डाला है। उनके शिविरों में कर्मकांडों के तौर पर ऐसी कई और चीजें चलती रहती हैं। मसलन, देश को वामजनवादी विकल्प देने के लिए काम करना, व्यापक वामपंथी एकता के प्रयास तेज करना और गैरवामपंथी दलों से न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर रणनीतिगत समर्थन व सहयोग के रिश्ते बनाना आदि। इन कर्मकांडों का सच यह है कि वामदलों में एका के बजाय बिखराव बढ़ता जा रहा है और कई कम्युनिस्ट पार्टियां अपने महासचिवों की जेबों में रहकर उनकी बौद्धिक भूख के शमन का जरिया भर रह गई हैं। सच तो यह है कि आज वामदलों को पुनर्जीवन के लिए नए फार्मूलेशनों और रणनीतियों की सख्त जरूरत है क्योंकि पुरानी कम्युनिस्ट थीसिसों का नए बदलावों के परिप्रेक्ष्य में युगानुरूप परीक्षण किए बिना उनकी बात नहीं बनने वाली है। इस परीक्षण के अभाव का ही नतीजा है कि लगभग एक साथ सक्रिय होने वाली दो जमातों में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि वह राजनीति से परे रहकर संस्कृति के ही क्षेत्र में काम करेगा, उसने काम करते-करते अपनी राजनीतिक फ्रंट की मार्फत लगभग सम्पूर्ण देश की राजनीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और संस्कृति के क्षेत्र में काम से परहेज कर चौबीसों घंटे जनपक्षधर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीति के हाशिये पर चली जा रही हैं।

पश्चिम बंगाल के शोर में केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर देश का कुछ कम ही ध्यान जा रहा है। हालांकि राजनीतिक लिहाज से वे भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हाथों वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की करारी हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे के साथ ही देश में वामपंथी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। यह पांच साल पहले ही खत्म हो जाता, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में विजयन के कामकाज से खुश केरल के मतदाता उन्हें 'बख्श' नहीं देते। संस्कृति के क्षेत्र में काम से परहेज कर चौबीसों घंटे जनपक्षधर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीति के हाशिये पर चली जा रही हैं।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सियासत
रोहित कौशिक

# पार्टियों को समझना होगा विपक्षी एकता का महत्व

भाजपा द्वारा चुनाव में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने और विशेष तौर से बंगाल का चुनाव जीतने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा जिस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, क्या उस तैयारी के साथ अन्य दल चुनावी मैदान में उतर पाते हैं ? बंगाल का चुनाव हारने के बाद अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करूंगी। सवाल यह है कि अभी तक ममता ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्या किया? सच्चाई तो यह है कि समय-समय पर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में अपनी अकड़ दिखाती रहीं। कई मुद्दों पर तो उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली। गठबंधन में यदि हर कोई अपनी अलग-अलग राह पकड़ ले तो क्या कोई भी गठबंधन मजबूत हो सकता है? आज ममता बनर्जी भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया को हथिया लेने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन क्या इस दौर की व्यवस्था से वे वाकिफ नहीं हैं ? क्या उन्हें इसका अनुमान नहीं था? ममता बच्ची नहीं हैं, वे एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेत्री हैं। यानी उन्हें यह आभास था। इसके बावजूद उन्होंने कई बार इंडिया गठबंधन को मजबूत न कर स्वयं अपनी अलग चाल चली। नतीजा सबके सामने है। अब सवाल केवल ममता का नहीं है, सवाल विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं का है? क्या विपक्ष के एक राज्य तक सिमटे छोटे दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़े हो पाएंगे। विपक्षी दलों को यह सोच लेना चाहिए कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर भाजपा के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। अगर गंभीरता के साथ भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़नी है तो अपने क्रियाकलापों में भी गंभीरता लानी होगी। आज भाजपा की आप कितनी भी आलोचना करें लेकिन यह विपक्षी दलों को ही सोचना पड़ेगा कि आज भाजपा यहां तक कैसे पहुंची है? कमरों में बैठकर अगर भाजपा की सफलता का राज ढूंढ़ा जाएगा तो विपक्षी दल भी कमरों तक ही सीमित रह जाएंगे। भाजपा ने लंबा संघर्ष किया है। इस पर अलग चर्चा हो सकती है कि भाजपा का यह संघर्ष सकारात्मक था या नकारात्मक? अगर आप कहते हैं कि भाजपा हर हथियार इस्तेमाल करना जानती है तो यह भी आपको ही सोचना होगा कि भाजपा इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई कि वह हर हथियार इस्तेमाल करने लगी। बंगाल में भाजपा का कोई वजूद नहीं था लेकिन आज भाजपा ने बंगाल में भी जीत हासिल कर ली। भाजपा जमीन पर मेहनत करना जानती है, लेकिन कितनी विपक्षी ऐसा कर रही हैं? चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस आरोप के सहारे विपक्ष अपनी कमजोरियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। इस दौर में पहले तो विपक्ष को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा और इसके साथ ही विपक्षी एकता पर भी बल देना होगा। विपक्षी एकता तभी संभव हो पाएगी, जब राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्यागकर एक बड़े उद्देश्य पर ध्यान केन्दित कर पाएंगे। भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव जीतने के बाद इस समय तो विपक्षी दलों को एकता की बात ध्यान आ रही है, लेकिन विपक्ष की एकता की भावना जल्दी ही खत्म हो जाती है। एक राज्य तक सिमटे दलों को कांग्रेस का महत्व समझना होगा। भले ही किसी एक राज्य में क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही समूचे विपक्ष को प्रतिनिधित्व दे सकती है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है इसलिए छोटे दलों को कांग्रेस को वह सम्मान देना होगा। इसके साथ ही कांग्रेस को भी छोटे दलों को सम्मान देकर विपक्षी एकता को मजबूत करना होगा। विपक्षी दलों को यह समझना होगा कि भाजपा से मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। छोटे दलों को यह लगता है कि कांग्रेस कहीं उनकी सीटों पर कब्जा न कर ले और छोटे दल सिमट न जाएं। इसलिए ऐसे दल कांग्रेस को सीट देते हुए घबराते हैं। जब तक विपक्षी दल आपसी समझ को बढ़ा नहीं पाएंगे, तब तक इस स्थिति में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को देर-सबेर यह समझना ही होगा कि विपक्षी एकता के बल पर ही उनका अस्तित्व बच सकता है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में विपक्षी एकता संभव हो पाएगी? दरअसल इस दौर में विचारधारा की राजनीति खत्म होती जा रही है। कुछ छोटे दल तो एक विचारधारा पर टिक ही नहीं पाते हैं। ऐसे दल समय आने पर हर तरह की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कुछ समय बाद विपक्षी एकता एक खोखला आदर्शवाद लगने लगती है। यह तो विपक्षी दलों को ही तय करना होगा कि वे कि रास्ते पर चलना चाहते हैं?

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# जितने भक्त, उतने ही भक्ति के रूप

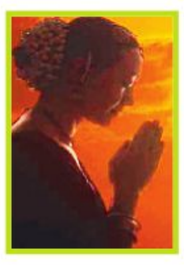

संकलित
दर्शन

मानस में भक्त के चार प्रकार बताए गए हैं- ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं आर्त। चार प्रकार के भक्तों की बात कह देना बहुत सरल है। भक्ति में वास्तविकता-अवास्तविकता का प्रश्न पहले नहीं उठाया जाता। जब तैरना सीख जाएंगे, तभी नदी में उतरेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका तो श्रीगणेश ही व्यक्ति की अपनी मान्यता से होता है। संसार सत्य है या असत्य? विषय को चाहना उचित है या अनुचित? प्रारंभिक स्थिति में इन विवादों की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तो सीधा आमंत्रण है। तुम संकट से त्राण पाना चाहते हो! ये सब प्रभु से ही संभव है। ब्रह्म-सुख पाना चाहते हो, तो आओ, प्रारंभ कर दो प्रभु के चरणों में भक्ति। अर्थ और अभिलाषाओं की पूर्ति चाहते हो! रहस्य जानना चाहते हो! सब सर्वदा प्रभु द्वारा साध्य होगा।भय और लोभ की सहज वृत्ति से भक्ति का श्रीगणेश होता है। भगवान की जिज्ञासा भक्ति का मध्यभाग है। भगवान का सुख पाना, उसमें एक हो जाना, भक्ति की चरम परिणति है। भय से संत्रस्त आर्त हैं। लोभ से प्रेरित अर्थार्थी हैं। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु है। जान पाने वाला ज्ञानी है। मानस में-'ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा' कहकर गोस्वामीजी ने पुष्ट कर दिया है। मानस में भक्तों की ओर देखें, तो साधारण से लेकर असाधारण चरित्र वाले अनेक पात्र हमारे सामने आते हैं। दशरथ, गीध, वाल्मीकि, शबरी, कोल, भील, वानर, निशाचर आदि सब वहां (भक्ति में) एक पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसी उदारता, जो कि अन्यत्र असंभव है।

# स्वयं को जीतना सिखाते स्वामी महावीर

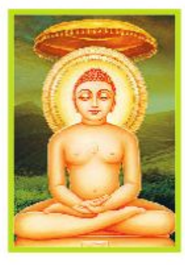

संकलित
प्रेरणा

स्वामी महावीर जैसी आत्माएं अपनी यात्रा पिछले जन्म में ही पूरी कर चुकी होती हैं। इस जन्म में इस संसार में आने की प्रेरणा के पीछे उनकी अपनी कोई वासना नहीं है। सिर्फ करुणा कारण है। तीर्थंकर का अर्थ है, वह आत्मा जो राह दिखाने के लिए पैदा हुई है। साधारण आत्मा तीर्थंकर नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्वयं मार्ग खोज रहा हो, वह मार्ग नहीं दिखा सकता। मार्ग क्या है, यह मंजिल पर पहुंच कर ही पता चलता है। मंजिल पर पहुंच जाना इतना कठिन नहीं है, जितना मंजिल पर पहुंच कर मार्ग पर वापस लौटना। ऐसी आत्माएं तीर्थंकर कहलाती हैं। तीर्थंकर का अर्थ है- वह मल्लाह, जो घाट से पार होने का रास्ता बताए। सच में जो विशिष्ट होता है, उसका प्रारंभिक जीवन घटना शून्य होता है, इसलिए क्योंकि वह लौटा है औरों के लिए, अपने लिए नहीं। बस वह चुपचाप बढ़ता चलता जाता है। चारों तरफ चुप्पी होती है और वह बड़ा होता जाता है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जो वह देने आया है, वह दे दे। मेरी दृष्टि में उनको वर्धमान नाम ही इसलिए मिला कि जो चुपचाप बढ़ने लगा। जिसके आस-पास कोई घटना ही नहीं घटी, यानी जिसका बढ़ना इतना चुपचाप था, जैसे पौधे चुपचाप बड़े होते हैं, कलियां फूल बनती हैं। कहीं कोई शोर नहीं होता। शिक्षक पढ़ाने आए, तो उसने मना कर दिया और शिक्षकों ने भी पाया कि जो पढ़ाया जा सकता है, वह उसे पहले से ज्ञात है। दूसरी बात ध्यान में रख लेने जैसी है, अर्थपूर्ण है, जो मिथ, जो कहानी है, वह तो यह है कि वे ब्राह्मणी के गर्भ में थे और देवताओ ने गर्भ बदल कर क्षत्रिय गर्भ में पहुंचा दिया।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### मां में देख सकते हैं ईश्वर का रूप

मां का छोटा-सा शब्द अपने भीतर भावनाओं का महासागर समेटे है। मां केवल जन्मदात्री नहीं होती, वह जीवन की प्रथम शिक्षिका, प्रथम मित्र और प्रथम मार्गदर्शिका भी होती है। जब एक शिशु पहली बार रोता है, तो मां अपनी गोद और अपने स्पर्श से उसे पहली सुरक्षा देती है। मां की गोद ही बच्चे का पहला आश्रय बनती है। मां के लिए वैदिक और पौराणिक काल के ग्रंथों ने जो कहा है, वो आज भी यथावत है। वेदों ने मां को मानव जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वेदों से संहिताओं तक, वाल्मीकि रामायण से महाभारत तक, सारे ग्रंथों ने निर्विवाद रूप से माता को ही देवताओं से भी ऊपर माना है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं उमड़ने लगती हैं, तब मन अचानक ही मां को याद करता है। 11 मई को मदर्स डे पर मां की महती भूमिका को स्वीकार करने की जरूरत है। – *विजय कुमार, भिलाई*

## ट्रेंड

### 'सोनार बांग्ला' का संकल्प

पश्चिम बंगाल भाजपा विधानसभा की बैठक में भाजपा विधानसभा दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी नेता, सुवेंदु डब्ल्यूबी को शुभकामनाएं। निस्संदेह, आप 'सोनार बांग्ला' के संकल्प को पूरा करेंगे और विकास का एक नया अध्याय लिखेंगे।
- **शिवराज सिंह चौहान,** केंद्रीय कृषिमंत्री

### जनहित में काम

प्रत्येक सार्वजनिक सुनवाई जनता के विश्वास, आशाओं और भावनाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आम जनता का यही स्नेह और विश्वास हमें जनहित में काम करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है।
- **सुखविंदर सिंह सुखू,** सीएम, हप्र

### आवास जनगणना

'आवास जनगणना' के तहत स्व-गणना प्रपत्र लखनऊ स्थित सरकारी आवास में भरा गया। यह प्रक्रिया सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
-**केशव प्रसाद मौर्य,** डिप्टी सीएम, उप्र

### सत्ता के घमंड में भाजपा

भाजपा समर्थकों के कुकर्मों का एक और घिनौना उदाहरण। सत्ता के घमंड में भाजपा समर्थक दरिंदे बन गए हैं। आज किसी की बहन-बेटी सुरक्षित नहीं है। जब जनता न्याय की मांग करे तो किससे? भाजपा ने अपने भ्रष्ट लोगों को हर जगह बिठा रखा है।
-**अखिलेश यादव,** सांसद, सपा

## करंट अफेयर

# पोप 14वें के साथ स्थायी शांति के प्रयासों पर की चर्चा

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पोप लियो 14वें से मुलाकात की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। रुबियो की वेटिकन यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना है। रुबियो ने पोप 14वें और वेटिकन के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की जो करीब ढाई घंटे तक चली। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि रुबियो और पोप 14वें ने पश्चिम एशिया की स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध में परस्पर हित के विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, इस बैठक ने अमेरिका और पोप के बीच मजबूत संबंधों और शांति एवं मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पिगोट ने पैरोलिन से हुई मुलाकात के बारे में एक अलग बयान में कहा कि दोनों राजनयिकों ने पश्चिमी गोलार्ध में चल रहे मानवीय प्रयासों और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि इस चर्चा में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अमेरिका और पोप के बीच अटूट साझेदारी प्रदर्शित होती है।

## ऑफ बीट

# 92 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना का किया उपयोग

जनगणना के पहले चरण के दौरान अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 92 लाख से अधिक परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (एसई) सुविधा का उपयोग किया है। अधिकारियों ने बताया कि स्व-गणना सुविधा भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की प्रथम पहल है, जो नागरिकों को जनगणना के पहले चरण के दौरान जनगणना से संबंधित प्रश्नों का ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा प्रदान करती है। भारत के पंजीयक और जनगणना आयुक्त ने को दिल्ली में जनगणना के पहले चरण - गृह सूचीकरण और आवास जनगणना (एचएलओ) - के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत छह जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी क्षेत्रों के लिए एचएलओ चरण 15 मई को समाप्त हुआ, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के शेष हिस्सों में यह 14 जून, 2026 तक जारी रहेगा। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ' 'जनगणना जागरूकता वाहन दिल्ली भर जायेंगे तथा जनगणना में भागीदारी, स्व-गणना (एसई) सुविधा, जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताओं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान गणनाकर्ताओं के साथ जनता के सहयोग के महत्व के बारे में संदेश देंगी।

## अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

# केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने नैफेड-एनसीसीएफ को लक्ष्य आधारित खरीद के दिए निर्देश

किसान एमएसपी से नीचे उपज बेचने को मजबूर न हो : उपार्जन समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह का कड़ा संदेश

उपार्जन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, 72 घंटे में भुगतान और जिला-स्तरीय लक्ष्य तय करने के दिए निर्देश

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में नैफेड और एनसीसीएफ के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव एमएसपी से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

चौहान ने दो टूक कहा कि किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। चौहान ने शुक्रवार को कृषि भवन में नैफेड और एनसीसीएफ की उपार्जन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपार्जन को केवल औपचारिक स्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने वाले मिशन मोड दायित्व के रूप में लिया जाए। उन्होंने

कहा कि यदि बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं और फिर भी खरीद अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है तो यह स्थिति किसानों के हित में नहीं मानी जा सकती। मंत्री उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियां अपने-अपने जिलों और केंद्रों के स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि राज्यवार आवंटन के साथ-साथ जिला-स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25 प्रतिशत खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके।चौहान ने दलहन-तिलहन, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि जहां किसानों को एमएसपी से कम दाम मिल रहे हैं, वहां खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपार्जन केंद्रों की संख्या, खरीद क्षमता, जिला-स्तरीय बाधाएं, राज्य सरकारों के निर्देश, गुणवत्ता संबंधी स्थानीय समस्याएं और भुगतान व्यवस्था इन सभी पहलुओं की रोजाना निगरानी की जाए और जहां भी बाधा हो, उसका समाधान तत्काल केंद्रीय स्तर पर रखा जाए। मसूर उपार्जन की समीक्षा के दौरान शिवराज सिंह ने राज्यों में वास्तविक बाजार भाव की ताजा जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कीमतें एमएसपी के आसपास या नीचे हैं, वहां खरीद तंत्र और अधिक चुस्त किया जाए। चौहान ने किसानों को समय पर भुगतान को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान व्यवस्था को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। समीक्षा में यह मुद्दा सामने आया कि किसानों को भुगतान में विलंब की शिकायतें हैं, जिस पर मंत्री ने 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त एसओपी तैयार करने और राज्यों से चर्चा कर इसे प्रभावी रूप से लागू करने को कहा।बैठक में राज्य पोर्टलों और सीएनए पोर्टल के एकीकरण, भुगतान में देरी, बिहार में डीबीटी व्यवस्था की कमी, गुजरात में भुगतान विलंब, महाराष्ट्र में डेटा लंबित रहने और आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा के लिए आंकड़े प्राप्त होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य के निर्देश, प्रक्रियाएं या स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें किसानों से खरीद में बाधा बन रही हैं तो केंद्र सरकार सक्रिय समन्वय के जरिए उनका समाधान सुनिश्चित करेगी।

## खबर संक्षेप

### माता-पिता, 3 बच्चों की मौत, ट्रक ने कुचला

**बुलंदशहर।** उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों

की मौत हो गई। हादसे में माता-पिता और उनके तीन मासूम बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक धमेडा कीरत गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिवार किसी काम से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

### अलीगढ़ में मगरमच्छ से भिड़ी लड़की, खुद को बचाया

**अलीगढ़।** बचपन की कविता वो याद आ रही है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक लड़की गुरुवार

को बड़ी ही बहादुरी से खूंखार मगरमच्छ से भिड़ गई। लड़की ने न सिर्फ मगरमच्छ को हराया बल्कि उसकी जबड़े से अपना हाथ भी बचा लिया। घटना सीमा के पास काली नदी के किनारे घटी।

### पटना में तेज बारिश और आंधी से 7 मौत

**पटना।** पटना में तेज बारिश,आंधी से भीषण तबाही मचाई। कई जगह

अब भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि पूरे पटना की लगभग सभी सड़कें जाम हैं और उन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पटना में पेड़ के नीचे 5लोग दब गए, जिसमें 1 की मौत हो गई। अलग-अलग 7 के मौत की खबर है।

### भाजपा ने राउत को बताया भारतीय राजनीति का जोकर

**नई दिल्ली।** शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित पोस्ट पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने राउत को भारतीय राजनीति का जोकर बताते हुए उन पर भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का आरोप लगाया।भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो संदेश में यह कहा।

## तमिलनाडु में सरकार बनने का रास्ता साफ, राज्यपाल से फिर मिले

# टीवीके ने बहुमत का आंकड़ा कर लिया पार अब इस राज्य में बनेगी 'विजय सरकार'

एजेंसी ⏭ चेन्नई

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर बड़ी खबर है। 2 दिनो की सियासी रस्साकसी के बाद खबर है कि सीपीआईएम, सीपीआई और वीसीके ने थलापति विजय की अगुवाई वाली टीवीके का समर्थन देने का फैसला किया है। इन 3 दलों के समर्थन देने से अब राज्य में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। कहा गया है कि इसी सिलसिले में विजय तीसरे दिन तीसरी बार राज्यपाल से मुलाकात की।

यह मुलाकात शाम 4.30 बजे थी। इन दलों के समर्थन देने के बाद अब विजय को कुल 118 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है जो 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है। टीवीके के पास 107 विधायक हैं। विजय दो सीटों से चुनाव जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़नी होगी। इनके अलावा कांग्रेस के 5 विधायक हैं, जो पहले ही समर्थन दे चुकी है। आज समर्थन देने वाले तीनों दलों के 2-2 विधायक हैं। इस तरह विजय को अब बहुमत यानी 118 विधायकों का समर्थन हासिल है।

**कांग्रेस के बाद 3 छोटे दलों ने भी दिया समर्थन**
**विजय ने बहुमत के लिए संख्या बल प्राप्त किया**

**सियासी रस्साकसी के बाद**
**आखिरकार राज्य में बजी सीटी**

**पार्टी में दिखी खुशी**

### बहुमत की चिंता नहीं

कहा गया है कि करीब उसी समय के आसपास, समर्थन देने वाले सभी दल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वे अपने फैसले की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसी बीच, मायलापुर के नवनिर्वाचित टीवीके विधायक पी वेंकटरमनन ने तमिलनाडु में सरकार गठन की पार्टी की क्षमता पर शुक्रवार को पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए आवश्यक संख्या बल है। सरकार गठन को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच उन्होंने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में पार्टी के पास बहुमत न होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या पार्टी ने स्थिर सरकार के लिए आवश्यक निश्चित आंकड़े हासिल कर लिए हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से 'हां' में जवाब दिया। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर पार्टी कोषाध्यक्ष वेंकटरमनन ने कहा कि जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम आपको एक घंटे में जानकारी देंगे।

### सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

2 दिन की राजनीतिक अनिश्चितता और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ जारी टीवीके के गतिरोध खत्म होने के आसार हैं। साथ ही अगली सरकार बनाने के उनके दावे को और मजबूती मिली है। टीवीके के अनुसार विजय ने शुक्रवार शाम 4.30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था और उम्मीद है कि प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के बाद वे एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

### तीसरी बार राज्यपाल से मुलाकात

राज्यपाल आरवी आर्लेकर के साथ विजय की ये तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों की मुलाकात बुधवार और गुरुवार को भी हुई थी। दोनों बार आर्लेकर ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज करते हुए तर्क दिया कि टीवीके नेता को सदन में बहुमत के लिए जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं है। विजय की तमिलगा वेट्री कझगम ने पिछले महीने के चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। पार्टी ने चुनावी मुकाबले में 234 में से 107 सीटें जीती हैं।

**कांग्रेस ने मांगे 2 मंत्री पद और राज्यसभा सीट**

*तमिलनाडु कांग्रेस परिषद के अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि कांग्रेस विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की नई सरकार का हिस्सा होगी और दावा किया कि उसे दो मंत्री पद और एक राज्यसभा सीट की पेशकश की गई है। सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वर्तमान में अपनी भागीदारी के विवरण को अंतिम रूप दे रहे हैं। उन्होंने (टीवीके) दो मंत्रियों और एक राज्यसभा सदस्य की मांग की है। हालांकि, विभागों की संख्या और विशिष्ट मांगों पर अंतिम निर्णय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का है।*

**मणिशंकर ने कांग्रेस पर उठाए सवाल**

### विजय के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने अनैतिकता-मूर्खता की

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणि शंकर अय्यर ने शुक्रवार को तमिलनाडु में अभिनेता विजय और उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस कदम को भयानक, नैतिक रूप से संदिग्ध और राजनीतिक रूप से गैरजिम्मेदाराना बताया। अय्यर ने कहा कि नवंबर 1925 में, सौ साल पहले, महात्मा गांधी ने अपने गुजराती पत्रिका 'नवजीवन' में यह सिद्धांत दिया था कि स्वराज का अर्थ नैतिकता पर आधारित शासन होना चाहिए और महात्मा गांधी की ही पार्टी, कांग्रेस ने हाल ही में टीवीके के साथ गठबंधन करने का जो निर्णय लिया है, उसी सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जबकि पिछले चुनाव में हमने टीवीके का विरोध किया था। यह मूर्खता है।

## नोएडा हाउसिंग घोटाला- सीबीआई कार्रवाई

# शुभकामना बिल्डटेक और निदेशकों पर छठी चार्जशीट

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

देशभर में हजारों होमबायर्स के साथ कथित धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में एम/एस शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशकों के खिलाफ अदालत में छठी चार्जशीट दाखिल कर दी है।

सीबीआई के अनुसार जांच में सामने आया है कि बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने कथित आपराधिक साजिश के तहत भोले-भाले घर खरीदारों और निवेशकों को आकर्षक वादों, भ्रामक दावों और झूठे आश्वासनों के जरिए निवेश करने के लिए प्रेरित किया। एजेंसी का आरोप है कि परियोजना से जुड़े लोगों ने होमबायर्स से धन एकत्र कर आर्थिक लाभ हासिल किया, जबकि खरीदारों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। सीबीआई ने सक्षम अदालत में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मुख्य रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, तथा अपराध में सहयोग (एबेटमेंट) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

**सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही व्यापक जांच:** सीबीआई फिलहाल देशभर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कुल 50 मामलों की जांच कर रही है। ये सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दर्ज किए गए थे। जांच का मुख्य केंद्र बिंदु उन आरोपों की पड़ताल करना है जिनमें बिल्डर कंपनियों पर होमबायर्स के पैसे की कथित हेराफेरी, परियोजनाओं में देरी, फंड डायवर्जन और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका के आरोप लगे हैं। सीबीआई का कहना है कि कई परियोजनाओं में खरीदारों से वसूले गए धन का उपयोग निर्धारित निर्माण कार्यों में करने के बजाय अन्य उद्देश्यों में किया गया, जिससे हजारों परिवार वर्षों से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पहले भी कई बड़ी बिल्डर कंपनियों पर कार्रवाई इससे पहले सीबीआई निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

फॉलोअप

उनमें जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एम/एस ड्रीम प्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम शुमार है। इन मामलों में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

**होमबायर्स में बढ़ी उम्मीद:** सीबीआई की इस कार्रवाई को लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हजारों होमबायर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के कई प्रोजेक्ट वर्षों से अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण खरीदारों को ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ उठाना पड़ रहा है।

## 11 मई को देशभर में मनाया जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

# खुल्लर ने सभी जिला उपायुक्तों को वीसी के माध्यम से दिए दिशा निर्देश

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से प्रदेश के सभी जिलाउपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि 11 मई को भव्य तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाए। इसे लेकर जिलास्तर पर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। सोमनाथ मंदिर भारत की अजेय सभ्यता का

प्रतीक है। विनाशकारी प्रहारों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज हमारे आत्म-सम्मान और साहस की मिसाल बनकर खड़ा है। 75 वर्ष पहले आधुनिक मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस दिन देशभर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान कलश यात्रा, आध्यात्मिक आयोजन, भारत की विरासत परंपरा पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खुल्लर ने सभी जिला उपायुक्तों को इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए।

**प्रधानमंत्री का संबोधन सोमनाथ से रहेगा लाइव:** खुल्लर ने कहा कि 11 मई को प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर से लाइव संबोधन रहेगा। यह लाइव टेलिकास्ट प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले जिलास्तरीय कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। जिलास्तर पर कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसका समापन शिव मंदिर में जलाभिषेक से होगा।

**बिहार में लीची फसल बचाने के लिए विशेषज्ञ कार्यबल को मिली जिम्मेदारी**

# केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिखाई गंभीरता, लीची संकट पर बनी विशेषज्ञ कमेटी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लीची किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और संवेदनशील पहल की है।

किसानों द्वारा लीची स्टिंग बग से फसल को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाए जाने के बाद सिंह के निर्देश पर तुरंत एक विशेषज्ञ कार्यबल गठित किया गया, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट और समाधान देगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में 7 मई को कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों ने लीची स्टिंग बग के कारण फसल को हो रहे भारी नुकसान का मुद्दा केंद्रीय मंत्री चौहान के समक्ष उठाया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश के अनुसार, यह टास्क फोर्स लीची स्टिंग बग की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, फसल क्षति का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तात्कालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाएगा। यह कार्यबल किसानों के लिए जरूरी परामर्श, विस्तार गतिविधियों और राज्य व केंद्र स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप संबंधी सुझाव भी देगा। इस विशेषज्ञ कार्यबल का गठन विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल कर किया गया है। इसमें राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है।

**इसमें निम्न सदस्य लिए गए हैं** उद्यान-सह-बिहार राज्य बागवानी मिशन के निदेशक, बिहार सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, पौधा संरक्षण, कृषि विभाग, बिहार सरकार के निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कीट वैज्ञानिक द्वारा नामित प्रतिनिधि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) द्वारा नामित प्रतिनिधि, एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि, पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप-अनुसंधान परिसर और पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र, रांची के वैज्ञानिक डॉ. जयपाल सिंह चौधरी, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलुरु के डॉ. एम. सम्पत कुमार, भाकृअनुप-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) डॉ. इप्सिता सामल तथा प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) डॉ. विनोद कुमार (सदस्य सचिव)। यह यह टीम एक सप्ताह में रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के समक्ष प्रस्तुत करेगी, ताकि समय रहते जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

## लांबा बोलीं- मोदी सरकार के पहले 10 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 42,85,888 मामले दर्ज हुए

# महिला कांग्रेस ने कहा- एनसीआरबी आंकड़ों ने खोली महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार के दावों की पोल

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

महिला कांग्रेस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के शासन में देश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भयावह हो चुकी है और अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 42,85,888 मामले दर्ज किए

गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 42 लाख से अधिक वो महिलाएं और बच्चियां हैं जो एक दशक में दरिंदगी का शिकार हुई हैं और न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जहां सालाना अपराध का आंकड़ा 3 लाख 40 हजार था, वहीं 2024 में यह बढ़कर लगभग 4 लाख 42 हजार हो गया है। देश में रोजाना 10 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हर 70 मिनट में एक बच्ची या महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। लांबा ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का उल्लेख करते हुए महिला सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा का 'बेटी बचाओ' का नारा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का 'नारी वंदन' तो बहाना है, उसे नारी सुरक्षा के नाम पर मात्र घड़ियाली आंसू बहाना है, अपने खास नेताओं को सजा से बचाना है और साथ ही एपस्टीन फाइल्स से भी ध्यान भटकाना है।

लांबा ने महिला अपराधों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले राज्यों का विवरण देते हुए भाजपा की डबल इंजन सरकार के मॉडल को विफल बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध के 66,000 मामलों के साथ देश में नंबर एक पर है। इसके बाद महाराष्ट्र लगभग 48,000 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान करीब 36,000 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश व बिहार में महिला अपराध के क्रमशः लगभग 32,000 और 27,000 मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है और अपराध के मामले में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक अपराध दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। अलका लांबा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भाजपा नेता समेत तीन पर मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस दबाव बना रही है और परिवार को समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया और बच्ची को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि आरोपी खुले घूम रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन-बल से सरकार की छवि बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं; अंकिता भंडारी हो या चंपावत की बच्ची, उन्हें उत्तराखंड की भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल सकता, इसीलिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए राज्य से बाहर मामले की निष्पक्ष जांच करवानी होगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंसराज पर दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा उसे बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है।

उन्होंने बिहार के पटना में हाल ही में नाबालिग लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बिहार की एक अन्य दिल दहला देने वाली घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था।लांबा ने यह भी कहा कि 2002 के बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफ करने वाला गुजरात मॉडल अब पूरे देश में लागू हो गया है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में फांसी की बजाय उम्रकैद होती है और बाद में रिहाई हो जाती है।अलका लांबा ने मांग की कि जुलाई में होने वाले संसद के आगामी मॉनसून सत्र में एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा हो और सरकार केवल अपराध के आंकड़े न दे, बल्कि यह भी बताए कि अब तक कितनी पीड़िताओं को न्याय मिला है और विशेषकर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कितने अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है।

दैनिक जागरण

मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनने लगता है

# विपक्षी गठबंधन में दरार

तमिलनाडु में अभिनेता जोसेफ विजय की नई बनी पार्टी टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरते ही कांग्रेस ने जिस तरह उसके साथ जाने के संकेत दिए और फिर बिना किसी संकोच ऐसा ही किया, उससे डीएमके का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। डीएमके नेताओं ने कांग्रेस के छिटकने को केवल धोखेबाजी ही नहीं बताया, बल्कि यह भी फैसला किया कि अब संसद में उसके सांसद कांग्रेस सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे। यह आइएनडीआइए से नाता तोड़ने की घोषणा ही है। कांग्रेस की तरह डीएमके संग मिलकर चुनाव लड़ने वाली माकपा, भाकपा और वीसीके नामक दल ने भी जिस प्रकार विजय के साथ जाना पसंद किया, वह अवसरवाद के अलावा और कुछ नहीं। चूंकि अब माकपा और भाकपा की कोई खास राजनीतिक अहमियत नहीं, इसलिए उनके डीएमके से अलग होने का कोई अधिक महत्व नहीं, लेकिन कांग्रेस का अलगाव विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को और अधिक कमजोर करने वाला है। यह एक तथ्य है कि आइएनडीआइए से छिटकने वाले दलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले जदयू अलग हुआ, फिर आम आदमी पार्टी। अब एक तरह से कांग्रेस ही उससे किनारा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि वे चुनाव से पहले ही टीवीके के साथ जाने पर विचार रहे थे, लेकिन यह कथित विचार उन्हें चुनाव बाद गठबंधन तोड़ने का लाइसेंस नहीं देता। आखिर राजनीतिक नैतिकता और गठबंधन धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं?

आने वाले समय में आइएनडीआइए के बिखरने की आशंका इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की घटक दलों से खटपट होती रहती है, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। यह भी ध्यान रहे कि हाल के विधानसभा चुनावों में बंगाल और केरलम में इस गठबंधन के घटक आमने-सामने ही थे। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि कांग्रेस को उसी गठबंधन के भविष्य की परवाह नहीं, जिसका नेतृत्व वह अपने हाथ रखना चाहती है। पहले भी इस गठबंधन का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं दिख रहा था, पर अब तो वह और स्याह दिखने लगा है। डीएमके संग चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सत्ता की मलाई खाने जिस तरह एक झटके में टीवीके के साथ चली गई, उससे यही साफ हुआ कि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का साथ दो दशक से भी अधिक पुराना था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए इस लंबे साथ को कोई अहमियत नहीं दी। अब इसके भरे-पूरे आसार हैं कि इस गठबंधन के अन्य घटक भी मौका देखते ही कांग्रेस से अलग होने में देर नहीं करेंगे। इसकी अनदेखी न की जाए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पलटी मारने पर यह कहकर उस पर तंज ही कसा है कि हम वे नहीं, जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें।

# जनस्वास्थ्य से खिलवाड़

देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सुसवा नदी के किनारे कूड़े के ढेर में आयरन एवं फोलिक एसिड सिरप की सैकड़ों शीशी मिलना निश्चित रूप से चिंताजनक है। यह पहला मामला नहीं है, जब सरकारी अस्पतालों की दवाइयां इस तरह कूड़े में डाल दी गईं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जांच के बाद विभागीय कार्यवाही की बात होती है और फिर मामला आया-गया हो जाता है। यह विचार करने की जरूरत शायद ही कभी महसूस की गई होगी कि ये दवाइयां आखिर जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच पातीं। जबकि, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व बढ़ते बच्चों में खून की कमी के मामलों की कमी नहीं है। देखा जाए तो इसके लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेदार है। एक ओर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का अभाव किसी से छिपा नहीं है, वहीं जो दवाइयां आ भी रही हैं, उनकी ऐसी बर्बादी हो रही है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि एक्सपायरी होने के कारण दवाइयां अनुपयोगी हो गई थीं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, इसका कभी जवाब नहीं मिलता। यह सीधे-सीधे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है, क्योंकि इन दवाइयों को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बांटा जाना था। इससे साफ है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग जनस्वास्थ्य से जुड़े अभियानों पर पलीता लगा रहा है। विभाग अगर जनस्वास्थ्य को लेकर सचमुच गंभीर है तो इसकी झलक उसकी कार्यप्रणाली में भी दिखनी चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे।

> एक ओर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का घोर अभाव है, वहीं जो दवाइयां आ भी रही हैं, उनकी ऐसी बर्बादी हो रही है

# बंगाल में परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण

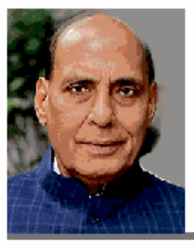

राजनाथ सिंह

**बंगाल में हुआ बदलाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है, जिन्होंने राज्य को उसके मूल से दूर किया**

अवधेश राजपूत

"हे नूतन, देखा दिक आर-बार, जन्मेरो प्रथम शुभोखोन।" इसका अर्थ है-हे नवीन, एक बार फिर से सामने आओ, ठीक उसी तरह जैसे जन्म के समय वह पहला शुभ क्षण आया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां केवल एक कविता का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर स्वतःस्फूर्त और नवीन होने वाली बंगाल के आत्मा का आह्वान भी हैं। गुरुदेव भली-भांति समझते थे कि बंगाल समय के साथ केवल बदलता नहीं है, बल्कि वह बार-बार बेहतर और नए रूप में पल्लवित होता है। गुरुदेव की जयंती पर गाई जाने वाली यह कविता नवजागरण और नवचेतना का प्रतीक है। यह एक सुखद संयोग है कि टैगोर की 165वीं जयंती से कुछ दिन पहले ही बंगाल कई दशकों के बाद नवजागरण का साक्षी बना। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह इस महान भूमि के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर था-एक ऐसा सभ्यतागत आह्वान, जो चुनावी समीकरणों और गणनाओं से कहीं ऊपर है।

आज जब बंगाल की चेतना और गौरव का अरुणोदय हो रहा है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि बंगाल क्या है और उसकी चेतना का पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है? बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र होने से पहले ज्ञान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में नबद्वीप के गंगा तट पर एक युवा संन्यासी निमाई ने अपने कीर्तन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उस युवा संन्यासी को हम संत चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता का अभियान भी था। उनके द्वारा प्रवाहित वैष्णव परंपरा ने समाज में करुणा, समावेशिता, समता और सद्भावना को बल दिया। यही चेतना बाउल परंपरा में भी दिखाई दी। बाउल परंपरा के फकीरों की पहचान जाति, पंथ या कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की भावना थी। बाउल परंपरा के सबसे महान प्रवर्तक लालन फकीर थे। वे किस संप्रदाय से थे, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया तथा मुस्लिम समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे बंगाल की उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे, जिसमें सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का भाव समाहित था।

विगत तीन शताब्दियों में बंगाल और यहां के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। राजा राममोहन राय ने लोगों को आत्मबोध कराकर समाज को भीतर से सुधारने का मार्ग चुना। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को नारी शक्ति के उत्थान, सशक्तीकरण और मुक्ति का साधन बनाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने "वंदे मातरम्" जैसा अमर मंत्र राष्ट्र को दिया। इस गीत ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया और सदियों से सोए हुए देश को जगा दिया। यह गीत आज भी भारत के लोगों के अंतरात्मा का स्वर है। भारत की पहली महिला चिकित्सक डा. कादंबिनी गांगुली ने सभी को और विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया। बंगाल की ही धरती पर जन्मे प्रखर राष्ट्रवादी डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संभवतः बंगाल की धरती ने जितनी विलक्षण प्रतिभाओं और महान लोगों को जन्म दिया, उनमें सबसे देदीप्यमान और प्रबुद्ध स्वामी विवेकानंद को कहा जा सकता है। शिकागो में दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने विश्व को वेदांत और भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों से परिचित कराया।

दुर्भाग्यवश लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझा और उसे हेय दृष्टि से देखा। सभ्यता, धर्म, संस्कृति और बंगाल की चेतना की बात करने वाले लोगों को और उनकी आवाज को दबाया गया। परिणामस्वरूप बंगाल ने दशकों तक विकासहीनता, अराजकता, संस्थागत पतन और वैचारिक जड़ता का दंश झेला। बंगाल में हुआ परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हैं, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है, जिन्होंने बंगाल को उसके मूल से दूर किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बंगाल विधानसभा का चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल के गौरव और विरासत को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ था। बेलूर मठ से प्रधानमंत्री मोदी का आत्मिक जुड़ाव, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और सुशासन को 'सेवा' के रूप में देखने का उनका दृष्टिकोण, ये सभी इसके प्रमाण हैं कि 'प्रधान सेवक' बंगाल के विकास और पुनर्जागरण को एक पावन दायित्व मानते हैं, जिसे वे अपने 'प्रधान धर्म' और 'प्रधान कर्म' के रूप में निभा रहे हैं।

बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण का अर्थ कई दशकों से उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो है ही, साथ ही उन घाटों को पुनर्जीवित करना भी है, जहां चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन ने लोगों को भाव-विभोर किया था। इसका अर्थ उन शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त करना भी है, जिनका स्वप्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा था। इसका अर्थ आदिवासी भाइयों-बहनों को गरिमा, सम्मान और अवसर देना और उपेक्षा झेल रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है।

पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो, किंतु आज बंगाल एक बार फिर नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शांति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बनने वाली पहली भाजपा सरकार गुरुदेव के द्वारा वर्णित 'नूतन' भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रतिष्ठा और समृद्धि के साथ राज्य का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।

(लेखक भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं)

response@jagran.com

# सरकार और देश में अंतर करना जरूरी

प्रो. मनोज कुमार झा

**एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहां नागरिक निर्भीक होकर सवाल पूछ सकें और जहां असहमति को भी सम्मान मिले**

लोकतंत्र की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक यह है कि देश और सरकार एक ही इकाई नहीं होते। यह फर्क केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। देश एक जीवंत, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाली सामूहिक चेतना है और उसकी विविधताओं, संघर्षों, इतिहास, आकांक्षाओं और भविष्य का समुच्चय होता है। इसके विपरीत, सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे जनता समय-समय पर चुनती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर देश बना रहता है। इस सरल-सी प्रतीत होने वाली सच्चाई को धुंधला करना, लोकतंत्र के आत्मा को कमजोर करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत करने लगता है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन आज के दौर में इसका स्वर अधिक मुखर और आक्रामक हो गया है। सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के रूप में चित्रित करना, असहमति को राष्ट्रद्रोह के साथ जोड़ देना और किसी एक नेता की छवि को राष्ट्र की गरिमा के साथ मिला देना, ये सभी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करने के औजार हैं। इससे नागरिकों पर दबाव बढ़ता है कि वे सवाल उठाने से बचें, अन्यथा उन्हें "देश-विरोधी" ठहरा दिया जाएगा। यह माहौल लोकतंत्र की मूल भावना-स्वतंत्र विचार और बहस के सर्वथा प्रतिकूल है।

किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी होती है। सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यशैली पर सवाल उठाना, उनका विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार उनका विरोध करना सक्रिय नागरिकता के अनिवार्य तत्व हैं। यदि यह प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, तो सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता है और जवाबदेही कम होती जाती है। जब-जब सरकार और राष्ट्र को एक मान लिया गया, तब-तब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं, नागरिक अधिकारों पर आघात हुआ और तानाशाही प्रवृत्तियां पनपीं। किसी भी उच्च पदस्थ नेता की गरिमा और प्रतिष्ठा निस्संदेह महत्वपूर्ण होती है,

आलोचना को अवसर माने सरकार। फाइल

लेकिन उसे राष्ट्र की गरिमा का पर्याय बना देना एक खतरनाक सरलीकरण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की छवि पर नहीं, बल्कि उसके संस्थानों की मजबूती, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और समाज की समावेशी संरचना पर निर्भर करती है। जब हम किसी नेता की आलोचना को राष्ट्र के अपमान के रूप में देखने लगते हैं, तो हम अनजाने में लोकतंत्र के उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच स्थापित होना चाहिए। यह याद रखना प्रासंगिक है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होती हैं। हर दल स्वाभाविक रूप से अपने विस्तार, प्रभाव और चुनावी सफलता के लिए काम करता है और यह लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, पर जब इन हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास होता है, तब समस्या पैदा होती है। इससे नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोणों की गुंजाइश कम हो जाती है और निर्णय एकतरफा हो सकते हैं।

लोकतंत्र का सार ही यह है कि विभिन्न विचारों के बीच संवाद हो और उसी से नीतियों का निर्माण हो। इस बहस में सबसे केंद्रीय भूमिका नागरिक की है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सवाल पूछना, जानकारी जुटाना, नीतियों का मूल्यांकन करना और अपनी स्वतंत्र राय बनाना, ये सभी लोकतांत्रिक नागरिकता के आवश्यक तत्व हैं। यदि नागरिक इस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, तो सत्ता का असंतुलन बढ़ता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। समझना जरूरी है कि आलोचना का अर्थ विरोध या नकारात्मकता नहीं होता। रचनात्मक आलोचना वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों में सुधार होता है और शासन अधिक प्रभावी बनता है। एक परिपक्व लोकतंत्र में सरकार आलोचना को अवसर के रूप में देखती है, न कि खतरे के रूप में, पर जब आलोचना को ही शत्रुता के रूप में देखा जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक असुरक्षा का संकेत है। आवश्यक है कि हम देश और सरकार के बीच इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझें और बनाए रखें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन देश स्थायी है। इसलिए हमारी सर्वोपरि निष्ठा किसी दल या व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उन मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, जो इस देश को परिभाषित करते हैं-लोकतंत्र, न्याय, समानता, संप्रभुता और स्वतंत्रता।

एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहां नागरिक निर्भीक होकर सवाल पूछ सकें, जहां असहमति को सम्मान मिले और जहां सरकारें स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह मानें। देश और सरकार के बीच की इस आवश्यक दूरी को बनाए रखना ही लोकतंत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यदि हम इस अंतर को भूल जाते हैं, तो हम न केवल अपनी नागरिक जिम्मेदारी से विमुख होते हैं, बल्कि उस लोकतांत्रिक आत्मा को भी कमजोर कर देते हैं, जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रखा है।

(लेखक राजद के राज्यसभा सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## समय का महत्व

विचारकों ने समय की तुलना धन से की है। जो समय बीत गया, उसके अनुभवों का लाभ तो लेना चाहिए, लेकिन उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ ग्लानि ही हाथ लगती है। यदि अतीत के दिनों में किसी स्तर पर नासमझी हो गई, तो उसे सुधार कर आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए। समय बहुत है। शारीरिक स्तर पर देखा जाए, तो नवजात शिशु बहुत कोमल और सुंदर लगता है। शनैः शनैः वह बड़ा होता है। कोमलता कम होती जाती है। एक समय आता है कि शरीर जर्जर हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कितना भी यत्न कोई कर ले, लेकिन बाल्यावस्था जैसी कोमलता, स्निग्धता और मधुरता को बरकरार नहीं रख पाता है। जहां समय इस तरह के सौंदर्य को अपहृत करता है, वहीं जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, तो बदले में यही समय अनुभव, नई जानकारियों का तोहफा देता है तथा परिचय का दायरा विस्तृत करता है। जब समय की यह गति है, तो इसके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। समय अपहर्ता है, तो वह दाता भी है। बशर्ते उसके द्वारा दी गई विशिष्टताओं को पूंजी की तरह संभाल कर रखा जाए।

समय की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि यदि किसी दिन कोई नया काम न किया गया हो, किसी नए व्यक्ति से परिचय न हुआ हो, तो उस दिन को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि यह उसके जीवन का निरर्थक दिन था। नए काम करते रहने से बहुआयामी प्रतिभा का विकास होता है। नए-नए व्यक्तियों से परिचय होने से जुड़ाव बढ़ता है। इस प्रकार समय को सार्थक ढंग से जीते हुए कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। व्यक्ति जब भी जागृत हो जाता है, तो सामने उपलब्धियों का सूरज दिखाई पड़ने लगता है।

सलिल पांडेय

# जैविक खेती की राह दिखाता सिक्किम

देवेंद्रराज सुथार

**जैविक खेती केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आवश्यकता बनती जा रही है**

हाल में सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के जैविक और प्राकृतिक खेती माडल की सराहना करते हुए उसे पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया। सिक्किम ने वर्ष 2016 में स्वयं को पूर्णतः जैविक राज्य घोषित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसके तहत रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

भारत में हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग हुआ। प्रारंभिक वर्षों में इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन लंबे समय में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और विभिन्न कृषि अनुसंधानों के अनुसार देश की बड़ी कृषि भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5 प्रतिशत से भी कम रह गई है, जबकि उपजाऊ मिट्टी के लिए यह एक से 1.5 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और अधिक उत्पादन के लिए और अधिक रासायनिक इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। रासायनिक खेती का दूसरा बड़ा प्रभाव जल स्रोतों पर पड़ता है। उर्वरकों में मौजूद नाइट्रेट भूजल में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नाइट्रेट युक्त जल का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विशेषकर बच्चों में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कीटनाशकों के अवशेष भोजन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी रासायनिक खेती जैव विविधता को प्रभावित करती है। मधुमक्खियों, केंचुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी देखी गई है, जो प्राकृतिक कृषि चक्र के लिए आवश्यक हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है।

सिक्किम का आकार छोटा है और जनसंख्या कम है, जिससे नीति लागू करना अपेक्षाकृत आसान रहा। बड़े राज्यों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से ही संभव है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश प्राकृतिक खेती की दिशा में लाखों किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी जैविक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अन्य राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे सीधे पूर्ण प्रतिबंध के बजाय मिश्रित और क्रमिक रणनीति अपनाएं। किसानों को प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच, जैविक उत्पादों के लिए उचित मूल्य और संक्रमण काल में आर्थिक सहायता देना आवश्यक होगा। साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि जैविक उत्पादों की मांग स्थिर बनी रहे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## बंगाल में हिंसा क्यों

'चुनाव बाद हिंसा का दुष्चक्र' संपादकीय पढ़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से राज्य में हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चुनाव के बाद हिंसा की यह प्रवृत्ति राज्य में नई नहीं है। आखिर चुनाव समाप्त होने और जनादेश स्पष्ट हो जाने के बाद भी बंगाल में हिंसा क्यों होती है? क्या इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, हार-जीत की प्रतिक्रिया और स्थानीय स्तर पर बढ़ती कटुता जिम्मेदार है? यदि ऐसा है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है, बल्कि लोकतांत्रिक परिवेश को भी प्रभावित करती है। अब इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती टकराहट का लाभ देशविरोधी और असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है और सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी संयम और जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर होने वाली बहसें ऐसी होनी चाहिए, जो शांति और संवाद को बढ़ावा दें, न कि तनाव और उत्तेजना को। कई बार तीखी बयानबाजी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना देती है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, जनादेश के सम्मान और सामाजिक सौहार्द में निहित है। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कभी भी हिंसा का कारण न बने।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

## स्वास्थ्य बिगाड़ते रासायनिक उर्वरक

हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर वर्ष लगभग 38.5 करोड़ अनजाने कीटनाशक विषाक्तता के मामले सामने आते हैं तथा लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। भारत में भी सब्जियों और फलों में अवशेष सीमा से अधिक कीटनाशक पाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे रसायनों से कैंसर, हार्मोन असंतुलन, त्वचा रोग, बांझपन, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं तथा बच्चों में विकास संबंधी विकार बढ़ सकते हैं। भूजल और मिट्टी भी विषैली होती जा रही है, जिससे खाद्य शृंखला प्रभावित होती है। समय की मांग है जैविक खेती को लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित किया जाए।

ओपी चौधरी, रतलाम

## जनादेश का हो सम्मान

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश को स्वीकार करना और आत्ममंथन करना राजनीतिक परिपक्वता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मतदाता चाहते हैं कि उन्हें भयमुक्त वातावरण, बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन मिले। ऐसे में चुनाव परिणामों को केवल राजनीतिक हार-जीत के रूप में नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और संदेश के रूप में भी देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनादेश का सम्मान करें। यदि जनता ने बदलाव का निर्णय दिया है, तो उसे स्वीकार करते हुए भविष्य की रणनीति पर विचार करना अधिक उचित माना जाता है। एक संवैधानिक पद पर लंबे समय तक रहने वाले नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें और राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं। दोषारोपण की राजनीति से आगे बढ़कर जनभावनाओं को समझना ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

yj929282joshi@gmail.com

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें:**

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

**28** प्रतिशत थी तत्कालीन पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार। बंटवारे के बाद वर्ष 1951 की जनगणना में यह संख्या घटकर 22 प्रतिशत रह गई थी, जो निरंतर कम होती गई।

प्रो. एम. एल. मीणा
विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आजकल

# चीन से संबंधित भारत की भूआर्थिक चुनौतियां

**भारत की सामरिक चुनौती और एशियाई शक्ति-संतुलन के बदलते भूगोल और वैश्विक राजनीति में चीन का उभार सबसे निर्णायक घटनाओं में समझा जा रहा है। पिछले चार दशकों में चीन ने जिस गति से आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और भूराजनीतिक शक्ति अर्जित की है, उसने विश्व व्यवस्था की दिशा बदल दी है। कभी पश्चिमी पूंजी और उत्पादन का केंद्र बना चीन अब स्वयं वैश्विक शक्ति-संरचना को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। भारत के लिए यह परिस्थिति सामान्य पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है। लिहाजा भारत को उसी अनुरूप रणनीति बनानी होगी**

समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीति को विस्तार देना सामरिक महत्व के लिहाज से आवश्यक है। प्रतीकात्मक

पिछले कुछ दशकों से चीन निरंतर अपनी भूआर्थिक सीमाओं के सुनियोजित विस्तार में जुटा हुआ है। पिछले एक दशक में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यह एशिया में शक्ति-संतुलन, सीमा सुरक्षा, समुद्री हितों, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। वास्तव में अगर हम अनौपचारिक तरीके से भू-राजनीतिक गणनाओं पर ध्यान दें तो चीन की विदेश नीति का मूल स्वभाव विस्तारवादी प्रकार का ही रहा है। बात चाहे दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, ताइवान पर सैन्य दबाव, जापान के साथ समुद्री विवाद या फिर हिमालयी सीमाओं पर आक्रामक गतिविधियों की हो, ये सब घटनाएं संकेत देती हैं कि चीन एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है।

इसी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में भारतीय संदर्भ शामिल होता है। इसमें सबसे गंभीर चिंता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियां हैं। वर्ष 2020 की गलवन घाटी की घटना ने दोनों देशों के संबंधों को निर्णायक रूप से बदल दिया था। लगभग चार दशकों बाद सीमा पर सैनिकों की मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन सीमा विवाद को स्थायी रूप से जीवित रखना चाहता है। चीन की रणनीति 'सलामी स्लाइसिंग' के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है, जिसमें छोटे-छोटे भूभागों पर धीरे-धीरे दबाव बनाकर सामरिक बढ़त हासिल की जाती है। पूर्वी लद्दाख, देपसांग और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में चीन की बयानबाजी इसी नीति का हिस्सा मानी जा सकती है। भारत के लिए समस्या और गहरी तब हो जाती है, जब चीन सीमाई तनाव को समय-समय पर सक्रिय रखकर जानबूझकर सामरिक दबाव बनाए रखना चाहता है, ताकि भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित रहें।

चीन की विस्तारवादी रणनीति का दूसरा आयाम आर्थिक प्रभाव है। बीआरआइ के माध्यम से चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बंदरगाह, रेलमार्ग, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं का विशाल नेटवर्क तैयार किया है। पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह, म्यांमार का क्याउकफ्यू पोर्ट और अफ्रीकी देशों में चीनी निवेश इस नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। चीन इन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक निर्भरता को सामरिक प्रभाव में परिवर्तित कर रहा है। श्रीलंका में ऋण संकट के बाद हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर चीन को सौंपना इस माडल की वास्तविकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि दक्षिण एशिया लंबे समय तक भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि अब चीन आर्थिक निवेश के जरिये इस क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज करा चुका है।

चीन की बढ़ती सक्रियता का तीसरा आयाम हिंद महासागर क्षेत्र में देखने को मिलता है, जोकि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति के तहत चीन ने भारत के चारों ओर बंदरगाह और लाजिस्टिक नेटवर्क विकसित किए हैं। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हंबनटोटा, बांग्लादेश का चटगांव और जिबूती में सैन्य अड्डा भारत की सामरिक गणनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। हिंद महासागर भारत के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री संचार का प्रमुख मार्ग है। हालांकि भारत भी इस रणनीति को गंभीरता से लेते हुए अपने सैन्य और सामरिक प्राथमिकताओं का पुनरावलोकन कर रहा है। इसी कारण पिछले कुछ समय से भारत ने अंडमान-निकोबार कमांड को मजबूत करने, नौसेना आधुनिकीकरण और क्वाड के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

भारत के लिए सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश राजनीतिक प्रभाव में बदलता दिखाई दे रहा है। नेपाल में आधारभूत परियोजनाएं, श्रीलंका में पोर्ट निवेश और मालदीव में अवसंरचनात्मक सहयोग इस दिशा के प्रयास हैं। चीन इन देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने पक्ष में रणनीतिक वातावरण तैयार कर रहा है।

चीन के उभार का एक महत्वपूर्ण पहलू मनोवैज्ञानिक और वैचारिक प्रभाव भी है। चीन स्वयं को कुशल शासन माडल के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां तेज आर्थिक विकास को लोकतांत्रिक बहस से अधिक महत्व दिया जाता है। कई विकासशील देशों में यह धारणा बन रही है कि अधिनायकवादी व्यवस्था तेजी से निर्णय लेने और बड़े आर्थिक परिवर्तन करने में सक्षम होती है। भारत के लिए यह चुनौती वैचारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक ढांचे के साथ विकास का माडल प्रस्तुत करना चाहता है। यदि भारत आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और अवसंरचनात्मक कमजोरियों को दूर नहीं कर पाता, तो चीन का माडल कई देशों को प्रभावी दिखाई दे सकता है।

इसलिए आने वाले समय में भारत को चीन के साथ अधिक कुशलता और कौशलता के साथ निपटना होगा। अंततः चीन का विस्तार भारत के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी है। चेतावनी इसलिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-संतुलन तेजी से बदल रहा है। अवसर इसलिए कि भारत अपने आर्थिक, तकनीकी और सामरिक ढांचे को पुनर्गठित कर सकता है।

## ग्रेट निकोबार का रणनीतिक महत्व

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

भूराजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और दुनिया के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक मलक्का के मुहाने पर ग्रेट निकोबार द्वीप की अवस्थिति वैश्विक व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली है। चीन के ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, जो चीन की एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी के रूप में मौजूद है। गलाथिया खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित किया जा रहा है। यह बंदरगाह पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग के निकट है तथा इसकी प्राकृतिक जल गहराई 20 मीटर से अधिक है। ग्रेट निकोबार के विकास से पूर्वी-हिंद महासागर में भारत के समुद्री प्रभाव के बढ़ने के साथ ही उसकी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और नई टाउनशिप के विकास से भारत वैश्विक समुद्री व्यापार और लाजिस्टिक्स नेटवर्क में मजबूत स्थिति हासिल कर सकेगा। वही कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर व कोलंबो बंदरगाहों पर उसकी निर्भरता में भी कमी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी हैं।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव के क्रम में बांग्लादेश का दृष्टिकोण तथा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फ्लोरिडा में पिछले वर्ष पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई का नया क्षेत्र खोलने जैसे दावे पूर्वी सीमा पर भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा वर्षों से रणनीतिक चर्चा का केंद्र रहा थाईलैंड का 'क्रा इस्थमुस' की सफलता मलक्का समुद्री मार्ग को बाईपास कर आने वाले समय में सीधे हिंद महासागर में प्रवेश का अवसर दे सकता है। ऐसे समय में जब ईरान ने होर्मुज समुद्र मार्ग के माध्यम से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है, भारत को भी इसकी महत्ता को देखते हुए हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित ग्रेट निकोबार में अपनी एक मजबूत आधुनिक सैन्यीकृत उपस्थिति चीन के 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' रणनीति को कमजोर करने वाला है तथा इसके विस्तारवादी मंसूबे को नाकाम करने के साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया व रूस को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह क्षेत्र भारत के लिए एक नया रणनीतिक सामुद्रिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरने का पर्याप्त अवसर भी देती है।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से ग्रेट निकोबार में बुनियादी ढांचे का विकास इस पूरे परिक्षेत्र का समीकरण बदलने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की लगभग 360 मील लंबी, म्यांमार की लगभग 1385 मील लंबी समुद्री तटरेखा के साथ थाईलैंड की स्थिति मौजूद है। जब दुनिया अंतरराष्ट्रीय कानून पर कम भरोसा कर रही हो, तब सामरिक और आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए देशहित में रणनीति तय करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना उचित है।

क्वाड की वजह से भारत की स्थिति मजबूत प्रतीत जरूर होती है, परंतु ग्रेट निकोबार परियोजना को हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक रणनीतिक वाणिज्यिक एवं सैन्य हब में बदल देगा। यह समुद्र में रेत की हिमालयी दीवार की तरह रक्षक बन सकता है, जो आर्थिक रूप से भारत की दशकों पुरानी रसद और ढांचागत कमियों को दूर करने और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होने वाला है।

## खरी-खरी

### आदमी सड़क का

**मनीष कुमार चौधरी**

सड़क का आदमी सड़क का ही होता है। वह सड़क या सड़कनुमा जैसी किसी जगह पर पैदा होता है, ताउम्र सड़क पर सड़कनुमा जिंदगी जीता है और अंततः सड़क पर ही दम तोड़ देता है। सड़क का यही आम आदमी कुछ लोगों को चुनाव में जिताता है और उन्हें खास बनाता है। फिर वही खास आदमी सड़क के आदमी को कभी खास नहीं बनने देता और उसे सड़क का ही बनाए रखता है। क्योंकि वह जानता है कि यह सड़क का आदमी ही उसे खास बनाता है। सड़क का आदमी जिंदगीभर सिस्टम से लड़ता रहता है, पर सिस्टम उसे कभी भी सड़क के आदमी की औकात से ऊपर उठने नहीं देता। लेकिन यह बात उसे बहुत समय के बाद समझ में आती है।

वह जानता है कि जिस दिन यह सड़क का आदमी अपनी औकात से ऊपर उठ गया तो वह बैठ जाना है। सिस्टम यह भी जानता है कि इसी सड़क के आदमी से देश चलेगा, इसलिए अपनी ठसक बनाए रखने के लिए सड़क के आदमी को हर पल याद दिलाता रहता है कि तू सड़क का बन, सड़क पर ही रह। वह उसे बार-बार दुत्कार कर इतना हीन बना देता है कि बेचारा सड़क का आदमी उसे नियति मानकर स्वीकार कर लेता है और स्वभाव व कार्य-कलापों में सड़क के किसी आदमी की तरह ही व्यवहार करने लगता है। कभी कोई सड़क का आदमी खुद को सिस्टम से ऊपर समझने की भूल न कर बैठे, इसलिए सिस्टम उसे कदम-कदम पर तुच्छ साबित करता रहता है।

वह जागते-सोते, रोते-हंसते, चलते-दौड़ते, बैठते-उठते... अपने रोम-रोम में सड़क को बसाए रखता है और मन को यही दिलासा देता है कि उसके भाग्य में ही सड़क का आदमी होना लिखा है, तो क्या करे। धीरे-धीरे उसका सोच ही सड़क के आदमी की तरह हो जाता है। जब सोच ही सड़क वाला हो जाएगा तो वह सड़क से ऊपर कैसे उठेगा! इसलिए सड़क का आदमी हमेशा सड़क का होकर रह जाता है। पहले भी वह सड़क का था, अब भी सड़क का है और मरते दम तक सड़क का ही रहेगा। हां, सड़क के आदमी की छवि से उसे छुटकारा मौत के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद सड़क के आदमी को कोई याद नहीं करता।

## पोस्ट

पिछले दो बार से भाजपा मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची नहीं निकाल रही। बिहार के बाद बंगाल में भी उम्मीद के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुना गया है।
सुकेश रंजन@RanjanSukesh

लगता है कांग्रेस के द्रमुक गठबंधन से बाहर निकलने के बाद आइएनडीआइए का स्वरूप समाप्त हो गया है। डीएमके को गुस्सा इस बात पर आया है कि कांग्रेस ने फैसले की जानकारी एमके स्टालिन को नहीं दी, जबकि अन्य सहयोगी दल उनसे बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि हमें क्यों बताना चाहिए? परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर होंगे।
धन्य राजेंद्रन@dhanyarajendran

तमिलनाडु में इन दिनों जिस तरह पुराने गठबंधन टूट रहे हैं एवं सत्ता की लालसा उन राजनीतिक रंजिशों पर भारी पड़ रही है, जिन्हें कभी न भूलने योग्य बताया जाता था, वह स्थिति बहुत कुछ सिखाने वाली है। असल में आज सत्ता ही एकमात्र उद्देश्य बन गई है। बाकी सब खरीदे और बेचे जाने वाली चीज बनकर रह गई हैं।
निस्तुला हेब्बार@nistula

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को ठुकरा कर सही किया?**

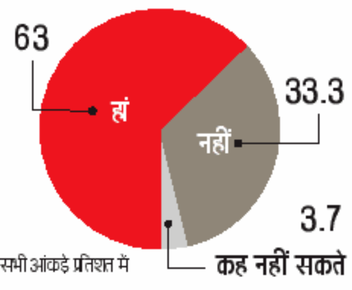


सभी आंकड़े प्रतिशत में

**आज का सवाल**

**क्या कांग्रेस के डीएमके से नाता तोड़ने से विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए और अधिक कमजोर होगा?**

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

## जनपथ

हारीं ममता जी मगर परेशान अखिलेश,
है उनके आगे खड़ा सत्ताइस का क्लेश।
सत्ताइस का क्लेश जमे पहले से बाबा,
नाचो-गाओ आप दिलों में रखकर 'काबा'!
बीजेपी का दांव पड़ रहा सब पर भारी,
चला न 'खेला' एक उसी से ममता हारीं!!
-ओम प्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

बिहार डायरी

# सरकारी कामकाज में तेजी आने की आशा

राज्य मंत्रिमंडल के पूर्ण विस्तार के बाद अब आशा की जा सकती है कि सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक बहुत तेजी से काम करेगी। क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी कामकाज की गति ठहर गई थी। नवंबर में चुनाव परिणाम आए, उसके बाद से अब तक विशुद्ध राजनीति ही चल रही थी। राज्य में पहली बार भाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिला है। अच्छी बात यह है कि सरकार की स्थिरता में इस समय कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे तेजी से काम करेंगे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने विकास और सुशासन के मुद्दे पर अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं।

सरकार की संरचना पर ध्यान दें तो यह कुछ-कुछ नीतीश कुमार के वर्ष 2005-10 के कार्यकाल की तरह है। नीतीश के कार्यकाल का वह दौर ऐसा था, जिसमें सरकार को कहीं से चुनौती नहीं मिल रही थी। नीतीश अपने एजेंडा के अनुसार सरपट चल रहे थे। आज बिहार में जो कुछ अच्छा नजर आ रहा है, उसकी नींव उन्हीं वर्षों में रखी गई थी। उसके बाद के शासन में नीतीश को राजनीतिक मोर्चे पर हर कार्यकाल में कठिनाइयां उठानी पड़ी। 2010 में जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था, भाजपा से नीतीश का मध्य अवधि में टकराव हो गया। वर्ष 2015-20 और 2020-25 के बीच उन्हें दो बार गठबंधन बदलना पड़ा। राज्य का विकास और सरकार बचाने की चुनौती, नीतीश को इन दोनों मोर्चे पर लड़ना पड़ा था।

ध्वस्त हो चुके पुल निर्माण कार्य में तेजी। फाइल

यह ठीक है कि सम्राट को नीतीश की समृद्ध विरासत मिली है। लेकिन, राज्य को आगे बढ़ाने और समय-समय पर जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए यही काफी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि सरकार को नियम संगत ढंग से चलाने में अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। तंत्र यदि सुस्त हो या उसमें स्वयंभू होने का भाव उत्पन्न हो जाए तो वह राज्य के लिए फलदायक नहीं रह जाता है। तंत्र के कामकाज में सुस्ती और लापरवाही का एक उदाहरण भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु है। इसका एक स्लैब टूट कर नदी में समाहित हो गया। प्रत्यक्ष रूप में यह एक घटना है। लेकिन, पृष्ठभूमि को देखें तो पता चलता है कि इसमें तंत्र की सुस्ती का बड़ा योगदान है। क्योंकि पुल की मरम्मत के लिए धन आवंटन की संचिका सरकारी विभागों के बीच घूमती रही। समय पर उपचार न होने से पुल का एक हिस्सा गिर गया।

इससे पता चलता है कि तंत्र आम जनता की सुविधाओं के प्रति कितना संवेदनहीन हो सकता है। वह फाइलों को किस हद तक उलझा कर रखने में सक्षम है। इससे पहले भी कई पुल टूटे हैं। ढंग से खोजबीन हो तो हर मामले में तंत्र की ऐसी ही सुस्ती सामने आएगी। इन वर्षों में राज्य के प्रशासनिक तंत्र में एक तरह की जड़ता बन गई है। यहां उपलब्ध केंद्रीय और राज्य सेवाओं के पूरे कार्य बल का शायद ही कभी उपयोग हो पाया। परिणाम यह निकला कि अधिकारियों का एक छोटा समूह ही हमेशा सक्रिय रहा। बड़ा हिस्सा केवल नौकरी करने के लिए छोड़ दिया गया।

राज्य सचिवालय में एक-एक अधिकारी के पास प्रभार वाले कई विभाग हैं। इन अधिकारियों की क्षमता पर प्रश्न नहीं है। मगर, यह प्रश्न तो है ही कि कार्य बल की पूर्ण क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने बहुत सीमा तक तंत्र से जुड़े लोगों के मन से उत्तरदायित्व की भावना को कमजोर किया है। क्योंकि उन्हें पता है कि परिणाम के आधार पर कुछ बनने-बिगड़ने वाला नहीं है। इस स्थिति से निर्वाचित जन प्रतिनिधि आहत नहीं हैं। उनका विक्षोभ कभी-कभी विधानसभा की बैठकों में सामने आता है, जब वे अपनी ही सरकार की किसी उपलब्धि वाले दावे को तथ्यों के साथ चुनौती देने लगते हैं। इसी से भ्रष्टाचार को भी संरक्षण मिलता है।

नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति के पालन का दावा किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता के मामले में वे शून्य सहनशीलता की नीति पर चलते रहेंगे। भला इस सच से कैसे इन्कार किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के बावजूद यह कम नहीं हुआ है। इसका पता उस समय चलता है कि जब कोई निगरानी एजेंसी किसी लोकसेवक को पकड़ती है तो अकूत बेनामी संपत्ति का रहस्य खुलता है। इन वर्षों में भ्रष्टाचार करने और उसे रोकने के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। आशा है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के मोर्चे पर शून्य सहनशीलता की जीत होगी।

भारत-बांग्लादेश

# आबादी की हो अदला-बदली

**बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को देखते हुए भारत में रह रहे हिंदू संगठनों को भारत व बांग्लादेश के बीच हिंदू एवं मुस्लिम आबादी की अदला-बदली की मांग उठानी चाहिए**

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

बंगाल में भाजपा की प्रचंड विजय के बाद बांग्लादेश ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार बनने पर वहां बसे बांग्लादेशियों को जबरन बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। वहां के गृहमंत्री ने वहां की प्रेस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत की ओर से बांग्लादेशियों को जबरन बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील-उर-रहमान कह चुके हैं कि अगर लोगों को जबरन धकेलने की कोशिश की गई, तो बांग्लादेश उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश सरकार की ओर से 'बार्डर गार्ड बांग्लादेश' को लोगों को जबरन भेजने की कोशिश को रोकने के लिए सीमा पर सतर्क रहने के लिए भी कह दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के एक बयान को लेकर भी बांग्लादेश के विदेश विभाग ने वहां भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। बिस्वा सरमा ने असम से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कही थी।

यह तो बात हुई बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देते ही बांग्लादेश में उपजी बेचैनी की। अब हमें आंकड़ों के आलोक में भारत और बांग्लादेश में स्थायी शांति और दोनों देशों की उन्नति की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। 1941 की जनगणना के अनुसार तत्कालीन पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 28 प्रतिशत थी। बंटवारे के बाद 1951 की पहली जनगणना में यह संख्या घटकर 22 प्रतिशत (लगभग 97 लाख) रह गई थी। हालांकि बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार वहां अब 1.31 करोड़ हिंदू ही बचे हैं। कुल जनसंख्या के अनुपात में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 7.95 प्रतिशत रह गई है।

अब एक नजर डालते हैं भारत की आजादी एवं देश विभाजन के समय हुई जनसंख्या के विस्थापन पर। वर्ष 1947 के भारत विभाजन के बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के आंकड़ों के लिए 1951 की जनगणना को मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) से लगभग 47 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) से लगभग 26 लाख लोग भारत आए थे। अर्थात 1951 की भारतीय जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों से कुल 73 लाख हिंदू और सिख विस्थापित होकर भारत आए। बदले में भारत से लगभग 65 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान और सात लाख पूर्वी पाकिस्तान गए। इस प्रकार विभाजन के दौरान 1.45 करोड़ लोगों ने सीमा पार की, जो इतिहास के सबसे बड़े मानव विस्थापन में से एक था।

अब बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की। वर्ष 2004 में तत्कालीन गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि असम में लगभग 50 लाख एवं बंगाल में लगभग 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) के पूर्व विशेष सचिव अमर भूषण जैसे विशेषज्ञों के शोध पर भरोसा करें, तो अकेले बंगाल में ही आज तीन करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिये हो सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या गैरमुस्लिम घुसपैठियों की भी हो सकती है। इस प्रकार बंगाल एवं असम के मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही कुल अनुमानित संख्या आज बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से लगभग दोगुनी बैठेगी। यह स्थिति तब है, जब इन दोनों राज्यों में घुसपैठियों की संख्या का कोई सटीक निर्धारण नहीं हो सका है।

वास्तव में, न सिर्फ इसका सटीक निर्धारण किया जाना चाहिए, बल्कि आजादी के बाद से अब तक कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो चुके जुल्मों को देखते हुए भारत में रह रहे हिंदू संगठनों को भारत और बांग्लादेश के बीच हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या की अदला-बदली की मांग जोर-शोर से उठानी चाहिए। भारत सरकार को भी अपने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) में संशोधन करके बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में इसकी समय सीमा बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। यह बात कुछ लोगों को अतार्किक लग सकती है, लेकिन पांच अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अपदस्थ किए जाने के बाद वहां के हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, उसे देखते हुए इस 'अतार्किक' सी लगनेवाली बात को भी 'तार्किक प्रस्ताव' में बदले जाने की आवश्यकता महसूस होती है। आखिरकार 1903 से 1905 के बीच लार्ड कर्जन द्वारा लाए गए बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं 1947 में भारत विभाजन के दौरान बंगाल में श्यामाप्रसाद मुखर्जी और असम में गोपीचंद बोरदोलोई ने हिंदुओं का हित देखते हुए ही तब जिन्ना और सुहरावर्दी जैसे नेताओं का विरोध कर बंगाल एवं असम समेत पूरे पूर्वोत्तर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया था।

भारत और बांग्लादेश के बीच आबादी के व्यावहारिक अदला-बदली करने पर हो विचार। फाइल

माना कि आज इस सोच को गले से नीचे उतारना आसान नहीं होगा। लेकिन आज असम और बांग्लादेश के साथ केंद्र में भी भाजपा जैसी राष्ट्रवादी सोच की सरकार रहते इस लक्ष्य को मुश्किल से ही सही, लेकिन पूरा किया जा सकता है। यदि भारत की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया जाए, तो बांग्लादेश की सरकार को भी उस पर गंभीरता से सोचकर 'हां' या 'ना' कहना चाहिए। क्योंकि अपनी सवा करोड़ से ज्यादा आबादी को निरंतर खतरे में डालकर, और दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

## चौथी तिमाही में टाइटन को 1,179 करोड़ का लाभ

**नई दिल्ली:** टाटा समूह की आभूषण और घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन को जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान 1,179 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 871 करोड़ रुपये के मुकाबले 35.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बीती तिमाही के दौरान कंपनी की बिक्री 48.28 प्रतिशत बढ़कर 20,607 करोड़ रुपये रही है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का लाभ 52 प्रतिशत बढ़कर 5,073 करोड़ रुपये रहा है। (प्रेट्र)

भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने विश्व-स्तरीय पैमाना हासिल कर लिया है, लेकिन डिजिटल पहुंच, डाटा गवर्नेंस, इंटरआपरेबिलिटी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

**- वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 77,328.19 ▼ 516.33 | निफ्टी | 24,176.15 ▼ 150.50 | सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 1,55,900 ▼ ₹ 100 | चांदी प्रति किलो ग्राम | ₹ 2,61,300 ▼ ₹ 200 | $ डालर | ₹ 94.47 ▲ ₹ 0.25 | क्रूड प्रति बैरल | $ 100 |

## एक नजर में

### हुंडई मोटर इंडिया के लाभ में 22 प्रतिशत की गिरावट

**नई दिल्ली:** हुंडई मोटर इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान उसका लाभ 22.22 प्रतिशत घटकर 1,255.63 करोड़ रुपये रहा है। इसकी वजह ज्यादा खर्च रही है। जनवरी-मार्च 2025 के दौरान कंपनी को 1,614.35 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भी कंपनी का लाभ घटकर 5,431.52 करोड़ रुपये रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 5,640.21 करोड़ रुपये था। कंपनी 21 रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश देगी। (प्रेट्र)

### 7.79 अरब डालर घटा विदेशी मुद्रा भंडार

**मुंबई:** बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.79 अरब डालर की गिरावट रही है। आरबीआइ के अनुसार, एक मई को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 60.693 अरब डालर रह गया है। बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियों में 2.797 अरब डालर की कमी दर्ज की गई और अब यह घटकर 551.825 अरब डालर रह गई है। इसी तरह, स्वर्ण भंडार का मूल्य 5.021 अरब डालर घटकर 115.216 अरब डालर रहा गया है। इससे पहले 24 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.82 अरब डालर घटा था। (प्रेट्र)

### जेप्टो समेत छह कंपनियों के आइपीओ को मिली मंजूरी

**नई दिल्ली:** कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने छह कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी दी है। इन कंपनियों में क्विक कामर्स यूनिकार्न जेप्टो, आटो उपकरण निर्माता धूत ट्रांसमिशन, हारिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, सर्गीवियर, क्रिस्टल क्राप प्रोटेक्शन और होटल पोलो टावर्स शामिल हैं। आइपीओ के जरिये जेप्टो करीब 11 हजार करोड़ रुपये और धूत ट्रांसमिशन 2,258 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं। हारिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स नए शेयरों की बिक्री के जरिये आइपीओ में 2,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। (प्रेट्र)

# तेल कंपनियों को 30 हजार करोड़ का नुकसान

## अब बढ़ाई जा सकती है पेट्रोल-डीजल की कीमत, आम जनता पर अभी तक नहीं डाला गया बोझ

- पश्चिम एशिया संकट के कारण 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ी तेल कंपनियों की इनपुट लागत
- एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई जाती तो 62,500 करोड़ रुपये तक बढ़ जाता यह नुकसान

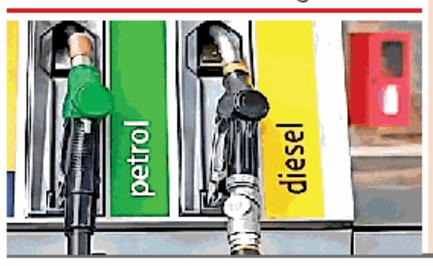


**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** पश्चिम एशिया संघर्ष ने वैश्विक क्रूड बाजार में जिस तरह से आग लगाई है, उससे अभी तक तो आम जनता को बचा कर रखा गया है लेकिन अब ज्यादा दिनों तक यह संभव नहीं दिख रहा। वजह यह है कि सरकार की तरफ से तमाम उपायों के बावजूद सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों (इंडियन आयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम) के लिए अब पेट्रो उत्पादों की बिक्री में होने वाले घाटा को सहना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि सिर्फ मार्च व अप्रैल के बीच उक्त तीनों कंपनियों को संयुक्त तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो गया है। अगर केंद्र सरकार ने उन्हें उत्पाद शुल्क में कटौती करके मदद नहीं की होती तो यह घाटा 62,500 करोड़ रुपये का हो गया होता।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जब कच्चे तेल की कीमत 120 डालर प्रति बैरल को पार गई थी, तब पेट्रोल पर प्रति लीटर लगभग 24 रुपये और डीजल पर लगभग 30 रुपये का बोझ उठाया था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये से शून्य करके हानि को कम करने में मदद की है। लेकिन इससे केंद्र सरकार को भी राजस्व का नुकसान भी हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष अब ग्यारहवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और मौजूदा व्यवस्था अनिश्चितकाल तक नहीं चलाई जा सकती। वैसे भी दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारतीय ग्राहक अभी तक पेट्रो महंगाई से सुरक्षित रखे गए हैं। इस दौरान हांगकांग में पेट्रोल की कीमत में 25 प्रतिशत, सिंगापुर में 30 प्रतिशत, इटली-जर्मनी-फ्रांस जैसे देशों में 35-30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जबकि भारत में पेट्रोल अभी भी लगभग 95-96 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। कई छोटे देशों ने और भी सख्त कदम उठाए जैसे बांग्लादेश ने ईंधन राशनिंग लागू की, श्रीलंका ने चार दिवसीय कार्य सप्ताह, फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया, पाकिस्तान और ताइवान में भी प्रतिबंध लगाए गए।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने से पहले 72 डालर प्रति बैरल के आसपास था। पश्चिम एशिया में तनाव के चरम के दौरान ब्रेंट क्रूड 144 डालर प्रति बैरल के उच्च सत्र तक पहुंचा था।

### ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाओं पर असर संभव

अधिकारी बताते हैं कि अगर खुदरा कीमतों को बढ़ाकर पेट्रोलियम व्यवसाय को व्यवस्थित नहीं किया गया तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का रणनीतिक भंडार बनाने, गैस पाइपलाइन बिछाने, रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने जैसी ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। भारत का वर्तमान रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व मात्र 53.3 लाख टन है, जो करीब 15 दिन के आयात के बराबर है। एलपीजी के लिए 30 दिन का समर्पित रिजर्व बनाने की योजना है। पश्चिम एशिया संकट के बाद इन योजनाओं पर तेजी से काम करने की जरूरत है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं जिसे ज्यादा दिनों तक बनाए रखना संभव नहीं है।

हमारी तेल विपणन कंपनियां बाजार से महंगा कच्चा तेल, गैस और एलपीजी खरीद रही हैं। लेकिन अपने उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वे इसे कम कीमतों पर बेच रही हैं। इससे तेल वितरण कंपनियों को हर महीने करीब 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकार को भी हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। - **सुजाता शर्मा**, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

# बीते वित्त वर्ष में एसबीआइ को 80,032 करोड़ रुपये का लाभ

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआइ को बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 80,032 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। बैंक ने शुक्रवार को बताया कि इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के 70,901 करोड़ रुपये के मुकाबले 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के बोर्ड ने 17.35 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान चार जून को किया जाएगा।

बैंक ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान उसका एकल शुद्ध लाभ छह प्रतिशत बढ़कर 19,684 करोड़ रुपये रहा है। इसमें खराब लोन में कमी का प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी-मार्च 2025 के दौरान बैंक को 18,643 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। हालांकि, बीती तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय घटकर 1,40,412 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 1,43,876 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान बैंक ब्याज से आय बढ़कर 1,23,098 करोड़ रुपये रही है, जो एक वर्ष पहले समान अवधि में 1,19,66 करोड़ रुपये थी।

बीती तिमाही के दौरान बैंक का सकल एनपीए घटकर कुल अग्रिम का 1.49 प्रतिशत पर आ गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के 70,901 करोड़ रुपये के मुकाबले 13 प्रतिशत की वृद्धि रही, 17.35 रुपये प्रति शेयर लाभांश देगा बैंक

### किफायती घरों की परिभाषा की समीक्षा हो: शेट्टी

एसबीआइ के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि औसत लोन का आकार अब बढ़कर 51 लाख रुपये हो गया है, जबकि दो साल पहले यह करीब 35-40 लाख रुपये था। ऐसे में किफायती घरों की परिभाषा में बदलाव की जरूरत है। अभी 45 लाख रुपये तक की लागत वाले घरों को किफायती घर कहा जाता है।

# अप्रैल में शाकाहारी व मांसाहारी थाली की लागत दो प्रतिशत बढ़ी

**टमाटर और एलपीजी की कीमतों में तेजी का दिखा असर, सस्ते प्याज, आलू और दाल ने वृद्धि की कुछ भरपाई की**

**नई दिल्ली, एएनआइ:** अप्रैल 2026 में घर पर बनी शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह की थालियों की लागत में वार्षिक आधार पर दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की ताजा 'रोटी राइस रिपोर्ट' के अनुसार, इसकी वजह टमाटर, वनस्पति तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलिंडरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है, जिससे खाने-पीने का खर्च बढ़ गया।

थाली की लागत बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह टमाटर की कीमतों में तेजी रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में खेती का रकबा कम होने से उत्पादन में 3-4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसके चलते अप्रैल 2026 में टमाटर की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 38 प्रतिशत बढ़कर 29 रुपये प्रति किलो हो गईं। अप्रैल 2025 में यह कीमत 21 रुपये प्रति किलो थीं। वैश्विक आपूर्ति में रुकावटों के कारण वनस्पति तेल और एलपीजी सिलिंडरों की कीमतें भी सालाना आधार पर सात प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्रायलर (चिकन) की कीमतों में तेजी के कारण मांसाहारी थाली की लागत भी दो प्रतिशत बढ़ी है।

हालांकि, थाली की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की कुछ हद तक भरपाई प्याज, आलू और दालों की कम कीमतों से हो गई। पिछले महीने प्याज की कीमतों में वार्षिक आधार पर 16 प्रतिशत और आलू की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट रही है। वहीं, दाल की कीमतों में चार प्रतिशत की कमी रही है।

### भारत में ड्रोन और सर्वर बनाएगी गूगल: वैष्णव

**नई दिल्ली, आइएएनएस:** केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल के अधिकारियों से मुलाकात है। इसके बाद वैष्णव ने एक्स पोस्ट में कहा कि गूगल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को मौकों की तलाश कर रही है। इसमें सर्वर और ड्रोन का उत्पादन भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की उस घोषणा के कुछ समय बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी इस साल अपना कुल पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 185 अरब डालर कर देगी। इसका मुख्य कारण एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा जोरदार निवेश है। गूगल ने आंध्र प्रदेश में पहले ही 15 अरब डालर की एक बड़ी निवेश योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत विशाखापत्तनम में एआइ हब बनाया जाएगा।

# एअर इंडिया ने वेतन वृद्धि तीन माह टाली

- कुछ रूट्स पर सेवाएं रोकने पर भी विचार करेगी विमानन कंपनी
- कंपनी के सीएचआरओ ने कहा, हमें छंटनी की कोई उम्मीद नहीं

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** पश्चिम एशिया संकट के कारण विमान ईंधन महंगा हो गया है, जिससे विमानन कंपनियों की लागत बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए कंपनियां विभिन्न उपाय कर रही हैं। इस बीच एअर इंडिया ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों से गैर-आवश्यक खर्चों को टालने के लिए कहा। साथ ही कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को कम से कम एक तिमाही के लिए स्थगित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, एअर इंडिया ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि छंटनी की कोई उम्मीद नहीं है।

एक टाउनहाल को संबोधित करते हुए विमानन कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कहा कि कंपनी कुछ रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम करने या सेवाओं को रोकने पर विचार करेगी। इसका कारण यह है कि कुछ उड़ानें या तो पहले जितनी लाभदायक नहीं रहीं या फिर एयरस्पेस की पाबंदियों के कारण घाटे में चल रही हैं। एअर इंडिया के बेड़े में अभी लगभग 190 विमान हैं। वित्त वर्ष वर्ष के दौरान कंपनी ने हर सप्ताह लगभग 8,000 उड़ानें संचालित कीं। विल्सन ने कहा कि रुपये में तेज गिरावट हो रही है और जेट ईंधन की कीमतों में 2.5-3 गुना वृद्धि हुई है। एअर इंडिया समूह का अनुमान है कि उसे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 22 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

**योजनाबद्ध पदोन्नति जारी रखेगी कंपनी :** कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) रविंद्र कुमार ने बताया कि एयरलाइन पिछले वित्त वर्ष के लिए परिवर्तनीय वेतन जारी रखेगी और योजनाबद्ध पदोन्नतियों को जारी रखेगी। वार्षिक वृद्धि को कम से कम एक तिमाही के लिए स्थगित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम छंटनी की उम्मीद नहीं करते। इससे पहले गुरुवार को एयरलाइन की बोर्ड बैठक में भी विभिन्न लागत-बचत के कदमों पर चर्चा हुई थी। इसमें कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजना भी शामिल है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअरलाइन के पास लगभग 24,000 कर्मचारी हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

### 71 पैसे बढ़कर 93.51 पर बंद हुआ रुपया

**मुंबई, प्रेट्र:** पश्चिम एशिया अस्थिर हालात के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इससे शुक्रवार को डालर में गिरावट दर्ज की गई और रुपया अपनी शुरुआती गिरावट से उबरते हुए 71 पैसे की जोरदार बढ़त के साथ 93.51 प्रति डालर पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि निवेशकों की भावनाएं तब प्रभावित हुईं, जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य और नागरिक इलाकों में नए हमले किए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि संघर्ष विराम अभी भी लागू है। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और कमजोर घरेलू बाजारों का भी रुपये पर दबाव रहा। शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 516.33 अंक गिरकर 77,328.19 पर और निफ्टी 150.50 अंक गिरकर 24,176.15 पर आ गया।

## राष्ट्रीय फलक

# अनिल अंबानी की एडीएजी से जुड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

- कोर्ट ने जांच की निगरानी की योजना बनाई, जुलाई में सुनवाई
- सात मामलों में अनुमानित नुकसान करीब 27,337 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और इनकी कंपनियों से जुड़े कथित विशाल पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले की गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि सीबीआइ ने बताया कि सात मामलों में कुल अनुमानित नुकसान लगभग 27,337 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वर्तमान में जांच की निगरानी करने की योजना बना रहा है।

पीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें एडीएजी की कंपनियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी की अदालत द्वारा निगरानी की जांच की मांग की थी। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नौ एफआइआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से दो में चार्जशीट दाखिल की गईं और सात मामलों में जांच जारी है।

याची के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह अजीब है कि सीबीआइ और ईडी दोनों ने कहा कि यह 27,000 करोड़ का घोटाला है और अनिल अंबानी मुख्य आरोपित हैं, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। भूषण ने कहा,"हर जगह सीबीआइ और ईडी कह रहे हैं कि इस 27,000 करोड़ रुपये के घोटाले में अनिल अंबानी मुख्य आरोपित हैं। फिर भी ना तो सीबीआइ और ना ही ईडी उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हैं, जैसे कि वह एक पवित्र गाय हैं।" पीठ ने अवलोकन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा कि गिरफ्तारी का आदेश देने में वह अत्यंत संकोच करेगा जब तक कि जांच एजेंसी ऐसा नहीं चाहती। अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अनिल अंबानी जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उनका एकमात्र एजेंडा अनिल अंबानी को गिरफ्तार करना है। जबकि भूषण ने स्पष्ट किया कि याची नहीं चाहता कि किसी को प्रताड़ित किया जाए। पीठ ने कहा कि वह किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहती।

### लालू समेत अन्य पर आरोप तय करने पर 22 तक टला आदेश

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:** राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने आइआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को 22 मई तक के लिए टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को इस मामले में शुक्रवार को आदेश सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने इससे पूर्व 13 फरवरी को ईडी और आरोपितों की ओर से दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी।

यह मामला आइआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग का है। ईडी के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान आइआरसीटीसी होटलों के संचालन व रखरखाव में अनियमितता हुई थीं।

# मनमाना निलंबन होता रहा तो कोई अधिकारी काम ही नहीं करेगा: हाई कोर्ट

- इंदौर में आइएएस अधिकारी के फार्म हाउस पर जुआ पकड़ने वाले थाना प्रभारी का निलंबन किया निरस्त
- कार्रवाई को प्रतिशोधात्मक बताया, कहा- ऐसे दंडित करना अदालत की अंतरात्मा को झकझोरता है

**नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर**

आइएएस अधिकारी के किराये पर दिए फार्म हाउस पर जुए का संचालन पकड़ने वाले इंदौर के मानपुर थाना प्रभारी के निलंबन की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने मनमाना और प्रतिशोधात्मक मानते हुए निरस्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई होगी तो कोई भी अधिकारी निलंबन के भय से किसी परिसर पर छापा मारने का साहस नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून को लागू करने वाले अधिकारी को त्वरित, कुशल एवं कानून सम्मत कर्तव्य पालन करने पर दंडित करना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है और अधिकारियों की दुर्भावना की ओर संकेत करता है।

प्रकरण में मानपुर थाना पुलिस ने गत 10 मार्च की रात मध्य प्रदेश वित्त निगम की प्रबंध निदेशक आइएएस अधिकारी वंदना वैद्य के इंदौर स्थित फार्म हाउस पर जुआ खेलते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था।

अगले ही दिन पुलिस अधिकारियों ने मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोरे और दो उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया। 18 मार्च को हिहोरे का मुख्यालय इंदौर से बदलकर बुरहानपुर कर दिया गया। हिहोरे ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत की।

### अपराध का स्थल बदलने के लिए बनाया गया दबाव

हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित निलंबन आदेश गंभीर त्रुटियों से ग्रसित है। एसपी ने निलंबन आदेश में लिखा कि थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में असफल रहे जबकि यह बात रिकार्ड पर है कि थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की और बड़े पैमाने पर चल रहे जुए के संचालन पर छापा मारा। थाना प्रभारी ने पूर्ण निष्ठा का परिचय देते हुए एफआइआर में वास्तविक तथ्यों को दर्ज कराया, लेकिन अगले ही दिन उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सामान्यत: कोर्ट निलंबन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन याचिकाकर्ता निलंबित थाना प्रभारी ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि उन पर अपराध का स्थल बदलने के लिए दबाव बनाया गया था।

# मोहाली व चंडीगढ़ में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की दूसरे दिन भी जांच जारी

**राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़**

- जांच एजेंसी ने अब तक करीब एक करोड़ की नकदी व अन्य दस्तावेज किए बरामद

किसानों व निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के मोहाली व चंडीगढ़ में 11 स्थानों पर ईडी की जांच शुक्रवार को भी जारी रही। ईडी अधिकारी मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर्स सोसायटी के 9वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट के अलावा अन्य ठिकानों पर जांच छानबीन कर रहे हैं। अब तक जांच में ईडी ने करीब एक करोड़ रुपये की नकदी के अलावा अहम दस्तावेज जब्त किए हैं।

ईडी की ओर से जिन बिल्डरों के ठिकानों पर जांच की जा रही है, उनमें इंडियन कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी से जुड़े सुरेश बजाज और अजय सहगल पर आरोप है कि उन्होंने 15 जमीन मालिकों की 30.5 एकड़ जमीन के संबंध में फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए और सनटेक सिटी नाम के मेगा प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी हासिल की। जांच में आल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि कंपनी ने खरीदारों को गुमराह किया और करोड़ों रुपये का निवेश करवाया। वहीं, ईडी ने दावा किया कि गौरव धीर ने कंपनी से आल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट करीब 130 करोड़ में खरीदा, जबकि परियोजना की वास्तविक कीमत 170 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी के अनुसार, गौरव धीर पंजाब के कैबिनेट मंत्री का करीबी है।

**आप प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, केंद्र सरकार कर रही राजनीति :** आप के प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को केंद्र व ईडी पर मनगढ़ंत कहानियां लीक कर उन्हें बदनाम करने के लिए राजनीति से प्रेरित मुहिम चलाने का आरोप लगाया।

# वैष्णो देवी से लौट रहे बाइक सवार दंपती और तीन बच्चों की ट्रक से कुचलकर मौत

- बुलंदशहर में अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर धमरावली के पास हादसा
- दो वर्षीय बेटे को दादा-दादी के पास छोड़ गए थे, नहीं पहना था हेलमेट

**जागरण संवाददाता, बुलंदशहर**

माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खुर्जा से लौट रहे बाइक सवार दंपती और उनके तीन बच्चों को हाईवे पर ट्रक ने कुचल दिया। पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। दंपती अपने दो वर्ष के एक बेटे को घर पर छोड़ गया था। हादसे के बाद चालक फरार है। बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

45 वर्षीय उत्तम सिंह ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। पांच मई को 40 वर्षीय पत्नी उर्मिला, 10 वर्षीय पुत्र निशांत, आठ वर्षीय पुत्री दिशा व पांच वर्षीय अनायरा के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। उन्होंने अपने दो वर्षीय पुत्र रेयांश को दादा-दादी के पास गांव में छोड़ दिया था। यात्रा के दौरान उत्तम ने खुर्जा में अपनी साली के घर

परिवार के साथ बाएं से निशांत, उर्मिला, उत्तम सिंह और दिशा। सौ. स्वजन

बाइक खड़ी की और परिवार के साथ खुर्जा जंक्शन से ट्रेन पकड़कर दिल्ली गए और वहां से जम्मू। शुक्रवार सुबह वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वे खुर्जा लौटे और कुछ घंटे साली के घर पर रुके। दोपहर बाद वह पत्नी व बच्चों के साथ बाइक से गांव लौट रहे थे। शाम लगभग साढ़े चार बजे अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर गांव धमरावली में ठंडी प्याऊ पुलिस चौकी के पास पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सभी सड़क पर गिर गए और ट्रक उन्हें कुचलता हुआ चला गया। दंपती और तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने मृतकों के आधार कार्ड के जरिये उनकी पहचान की और स्वजन को सूचित किया। रोते-बिलखते स्वजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर ट्रक की पहचान करते हुए बताया कि ट्रक गुरुग्राम के श्रीआनंद के नाम पर है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

# अभिनेत्री आकांक्षा की मौत मामले में पुलिस को हलफनामा देने का अंतिम अवसर

**जागरण संवाददाता, प्रयागराज**

- कहा, पुलिस कमिश्नर व एसएचओ सारनाथ दाखिल करें हलफनामा

आकांक्षा दुबे। फाइल

मां ने की सीबीआइ जांच की मांग, हत्या का लगाया है आरोप

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी व थानाध्यक्ष सारनाथ को निर्देशित किया कि वे अगली सुनवाई तिथि 22 मई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली सुनवाई तिथि पर सुबह 10 बजे दोनों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

पुलिस आयुक्त वाराणसी को कोर्ट ने इस बात के लिए भी निर्देशित किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कराएं कि थानाध्यक्ष हलफनामा दाखिल कर दें। मामले में आरोपित समर सिंह तथा संजय सिंह को भी कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर नोटिस जारी करने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया है। याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर यह मामला सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। इससे पहले चार मई को कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। 26 मार्च 2023 को वाराणसी में सारनाथ स्थित एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव मिला था।